राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का ३८वां दिवस [संख्या २५

शनिवार, दिनांक १ अप्रेल, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद, यातायात, राजस्थान नहर सिंचाई, शक्ति एवं सार्वजनिक-निर्माण विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ६६३

श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये।)

थानेदार चरणसिंह व डिप्टी एस. पी. चूरू के विरूद्ध की गई शिकायतों पर कार्यवाही

६६४. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सही है कि श्री नारायणसिंह पुत्र बीजराजसिंह राजपूत, साकिन सुजानगढ़ ने थानेदार चरणसिंह तथा सिपाही रूडेखां के विरुद्ध दिनांक २५-७-५९ को बीकानेर आयुक्त को सेवा में शिकायत की थी ?

(ख) क्या यह सही है कि दि० ३ व ४-१२-५९ की रात को डिप्टी एस. पी., चूरू, मंगलचन्द एच. सी. तथा कुछ सिपाही उक्त नारायणसिंह के घर पर गये तथा अपने मातहत की शिकायत पर नाराज होकर उन्होंने नारायणसिंह तथा उसके लड़के को बुरी तरह मारा जिससे उसके चोटें भी आई ?

(ग) क्या यह सही है कि डिप्टी एस.पी. ने एक कागज़ पर उपरोक्त शिकायत के लिये लिखा लिया कि शिकायत झूठी है ?

Page No 2

(श्री भैरोंसिंह)

(घ) क्या यह सही है कि श्री नारायण सिंह ने दि० ४-१२-५६ को बीकानेर जाकर इसकी शिकायत आयुक्त महोदय को की तथा उनकी हिदायत से डॉक्टरी मुआयना कराया ?

(ङ) यदि हां, तो श्री चरणसिंह की शिकायत, डिप्टी एस. पी. को उपरोक्त कार्यवाही की शिकायत के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

(च) चरणसिंह के विरुद्ध की गई शिकायत के क्या तथ्य हैं ?

पृथक राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं। डी. एस. पी., पुलिस फोर्स के साथ, रात को गश्तकरने गया था और हमेशा के अनुसार बदमाशों की पड़ताल, जिनमें नारायणसिंह भी शामिल हैं को, क्योंकि कस्बा सुजानगढ़ में माह नवम्बर व दिसम्बर में चोरियों की बढ़ोतरी थी। नारायण सिंहजी उसके लड़के को दिन में थाने पर आने के वास्ते हिदायत की, जिसकी उसने आपत्ति की और झूठी शिकायतें कीं।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां, परन्तु इसने अपनी मर्जी से मुआयना करवाया।

(५) दोनों शिकायतें जांच से बेबुनियाद पाई गईं।

(६) तथ्य यह है कि श्री नारायणसिंह के हिस्ट्रीशीटर होने से उसके चालचलन पर पुलिस कड़ी निगरानी रखती है, जिसको बन्द करवाने के लिए श्री नारायणसिंह ने पुलिस पर दबाव डालने के लिए झूठी शिकायत की।

प्रश्न संख्या ६६५

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

पी. एस. सी. की अनुमति बिना नियुक्त सार्वजनिक सम्पर्क अधिकारी

६६६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या यह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) सन् १९५९-६० तथा ६०-६१ में बिना पी. एस. सी. की अनुमति के किन किन व्यक्तियों को कब कब और क्यों पी. आर. ओ. के पद पर नियुक्त किया गया ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें, जिसमें नाम के साथ पिता का नाम भी बताया जावे।

(ख) क्या पी. आर. ओ. के पद के लिये पी. एस. सी. को रिक्वीज़िशन भेजा गया था ? यदि हां, तो कब और कितने स्थानों के लिए ?

(ग) प्रश्न (क) के अनुसार की गई नियुक्तियां किस आधार पर किस प्रकार से किन किन अधिकारियों द्वारा की गई ?

(घ) जिन स्थानों पर ये नियुक्तियां हुई हैं वे स्थान कब २ से रिक्त थे ?

Page No 3

(श्री भैरोंसिंह)

(ङ) इनमें कितने व्यक्तियों का जनसेवा आयोग द्वारा कब कब सिलेक्शन या कन्फर्मेशन हो चुका है और किन किन को रिजेक्ट कर दिया गया है ?

पृथक राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) सन् १९५९–६० तथा ६०–६१ में केवल देवीप्रसाद शर्मा, पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद की नियुक्ति जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर ता० १२–५–१९६० को अस्थायी तौर पर छः माह अथवा जनसेवा आयोग द्वारा चुने गये व्यक्ति की नियुक्ति, जो भी पहले हो, तब तक के लिये की गई।

(ख) जी हां। ६ जनसम्पर्क अधिकारियों के स्थानों के भरने के लिए रिक्वीज़िशन जनसेवा आयोग को ता० १४–४–१९६० को भेजे जा चुके हैं।

(ग) श्री देवीप्रसाद शर्मा की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर सरकार द्वारा की गई थी।

(घ) ये स्थान ता० २१–१–६० से रिक्त थे।

(ङ) जनसेवा आयोग द्वारा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। कन्फर्मेशन तथा रिजेक्शन का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : जनसेवा आयोग को जो रिक्वीज़ीशन भेजा गया था वह कितने पदों के लिए भेजा गया था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ६ पदों के लिए।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस समय ६ स्थान रिक्त थे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह तो जितने की जरूरत थी उसके मुताबिक भेजा गया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन्हीं ६ स्थानों में से एक स्थान के ऊपर यह नियुक्ति की गई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उस वक्त यह जो स्थान खाली थे उसी पर इनको लिया गया है, इनका अपोइन्टमेंट हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल यह था कि जिन ६ स्थानों के लिए रिक्वीजिशन भेजा है, क्या उन ६ स्थानों में से एक पद पर उनकी नियुक्ति की गई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसा भी हो सकता है कि जिन २ स्थानों पर और पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर लगाने हैं उनको क्रियेट करने से नई पोस्ट हो सकती है जिनके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को यह भेजा गया है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा तो सवाल डेफिनिट है, इसके बारे में कि यह जो नियुक्ति की गई है, यह उन्हीं ६ स्थानों में से एक के ऊपर की गई है जिनके बारे में पी. एस. सी. को रिक्वीज़िशन भेजा था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने आप से निवेदन किया कि जिस स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई वह स्थान जनवरी से खाली था और ६ स्थान पहले से ही रिक्त हैं या नये बनेंगे, मैं नहीं कह सकता।

Page No 4

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि जिस स्थान पर उनकी नियुक्ति की गई उसके लिये पी. एस. सी. को रिक्वीजिशन नहीं भेजा गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह स्थान भी उन छः में शामिल है।

श्री अध्यक्ष : ६ से संभवतः ज्यादा खाली हो सकती हैं। रिक्वीज़िशन ६ के लिये भेजा था और हो तो मालूम नहीं। पोस्ट्स कितनी खाली थीं, उनके बारे में ये कह नहीं सकते लेकिन ६ के लिये रिक्वीज़िशन भेजा था ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो रिक्वीज़िशन ६ पोस्टस के लिये भेजा था उसके लिये एप्लीकेशन्स इन्वाइट की गई थीं और जिसको आपने नियुक्त किया है वह पी.-एस. सी. के सामने भी एपियर हुआ था और वहां इन्टर्व्यू में उसे रिजेक्ट किया गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसी बात नहीं है। पी. एस. सी. ने अभी तक किसी को बुलाया ही नहीं है। होम सेक्रेटरी के सामने इन्टर्व्यू हुआ था।

श्री भैरोंसिंह : क्या होम सेक्रेटरी नियुक्त कर सकते हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : टेम्पोरेरी कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : ६ महीनों का समय निकल गया, पी. एस. सी. एप्लीकेशन मांगती है, एक आदमी टेम्पोरेरी है जिसका सिलेक्शन नहीं होता वह नहीं रह सकता ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पी. एस. सी. को रिक्वीज़िशन भेजी जा चुकी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस आदमी की नियुक्ति के बाद पी. एस. सी. को रिक्वीज़िशन नहीं भेजी गई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उससे पहले ही भेज दी गई थी।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक पोस्ट के बारे में कह रहा हूँ। जिस पोस्ट पर इस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है उस पोस्ट के लिये रिक्वीज़िशन नहीं भेजी गई है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उसके लिये भी भेजा गया है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जाय कि इसके बारे में पी.एस.सी. ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पी. एस. सी. ने कुछ क्वालिफिकेशन और एज लिमिट में तरमीम चाही है इसलिये डिपार्टमेंट को वापिस भेजा है। यह केस एफ. डी. में एग्ज़ामिन किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या टेम्पोरेरी एम्पलॉयमेंट के लिये एप्लीकेशन्स इन्वाइट की थी?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या एडवर्टाइज़मेंट किया गया था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या एप्लीकेशन्स इन्वाइट करने के लिये एडवर्टाइज़मेंट किया गया था ?

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि उनको मालूम नहीं है ।

नगरपालिकाओं में बकाया ऋण रकम की सहायता रूप में परिणति की अपेक्षा

६६७. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान सरकार की कितनी रकम किन २ नगरपालिकाओं में कब से बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(ख) इन नगरपालिकाओं से किस प्रकार यह रकम वसूल हो सकेगी ?

(ग) क्या सरकार नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बकाया ऋण रकमों को सहायता के रूप में परिवर्तित करने का विचार रखती है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जिन जिन नगरपालिकाओं की ओर राज्य सरकार की रकम बकाया है उनकी तीन सूचियां–अ, ब, तथा स–सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(ख) जिन जिन नगरपालिकाओं से बकाया किश्तों की अदायगी नहीं होगी उनकी वसूली हेतु सम्बन्धित नगरपालिकाओं के बजट में वसूली के लिये प्रावधान किया जावेगा ।

(ग) अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

श्री मूलचन्द डागा : कुल आपकी रकम म्युनिसिपैलिटीज़ में १,२१,१५,००० रुपये बकाया हैं और आपने बताया है कि उदयपुर में आपने ३० लाख रुपये १९५३ में दिये हैं, उनमें से किसी तरह से ८ साल में १। लाख रुपया रिकवर हुआ है । कुल ३० लाख रुपये दिये और ८ साल में १ लाख २५ हजार रुपये वसूल हुए । क्या आपकी पूरी रकम रिकवर हो सकती है इस स्थिति से ?

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें तो उत्तर मिले ।

श्री सम्पतराम : आम तौर से नगरपालिकाओं को रकम दी गई है और उनसे जो रिकवरी हुई है उसकी इत्तला दी गई है । यदि इन्डीविजुअल म्युनिसिपैलिटी के बारे में अलग पूछें तो पोजीशन देख कर बता सकता हूँ कि क्या स्टेप्स लिये हैं और क्या ले रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : जिस म्युनिसिपैलिटी पर लाखों रुपयों का कर्जा पहले से ही था उसको आपने बार बार ५० हजार, ३० हजार और १ लाख रुपये दिये हैं । जयपुर, अलवर, भरतपुर इनको आपने बार

Page No 6

(श्री मूलचन्द डागा)

बार काफी रुपया दिया है और रिकवरी बराबर नहीं हुई है, इसका क्या कारण है ?

श्री सम्पतराम : इसको इन्कार कहां किया, स्टेटमेंट में सारी बात दी हुई है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह जानना चाहता हूँ कि सन् ५१ से ५३ तक लाखों रुपयों का कर्जा जिन म्युनिसिपैलिटीज़ पर है उनको बार बार कर्जा दे रहे हैं और रिकवरी नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है ?

श्री सम्पतराम : वसूली करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यदि उनकी फाइ-नेन्शियल पोज़ीशन ठीक है और बार बार कहने पर भी नहीं देंगे तो बजट में से प्रोविज़न कर दिया जायेगा और उसके मुताबिक वसूली होगी।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की है कि नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति कैसी है। खराब है या अच्छी है ?

श्री सम्पतराम : यह जानने का प्रयत्न किया कि ठीक ठीक काम कर रही हैं या नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : म्युनिसिपैलिटीज़ को कर्जा किन किन आधारों पर दे रहे हैं ?

श्री सम्पतराम : वे आधार यह देखते हैं कि कितना कॉन्ट्रिब्यूशन कर सकती है, किन किन चीजों को प्रोयोरिटी देना चाहते हैं, ऐसी चीजें हैं जिनको देख कर कर्जा दिया जाता है।

डॉ० चन्द्रकला : नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये क्या क्या प्रयत्न किये गये ?

श्री सम्पतराम : टैक्सेशन के जरिये, सेल ऑफ लैंड आदि से उनको ज्यादा से ज्यादा रुपये मिलें, इसका प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या हाउस टैक्स सभी जगह लागू किया जा रहा है ?

श्री सम्पतराम : करीब करीब।

डॉ० चन्द्रकला : जमीन की सेल कब शुरू हुई ?

श्री सम्पतराम : यह अलग सवाल है, माननीय सदस्या को इसके लिये नोटिस देना चाहिये।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जमीन की सेल आपने रोक दी थी, वापिस कब से शुरू की ?

श्री सम्पतराम : तारीख मेरे पास नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या मंत्रीजी को यह मालूम है कि जमीन की सेल काफी लम्बे अर्से तक रोक रखी थी जिसके कारण आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, डॉ० चन्द्रकला !

Page No 7

चिकित्सालयों में रोगियों के मनोरंजन की व्यवस्था

६६८. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राज्य के चिकित्सालयों में, जहां रोगी रुग्णावस्था में रहते हैं, रोगियों के मनोरंजन के लिये कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो किन किन चिकित्सालयों में क्या क्या व्यवस्था है ?

(२) क्या रोगियों के मन बहलाव एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिये ऐसी कोई व्यवस्था की जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा वह कब तक क्रियान्वित होगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस दिशा में जल्दी से जल्दी कोई सक्रिय कदम उठाने का विचार रखती है ?

पृथक राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (१) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) टी. बी. व मानसिक अस्पताल में स्पेशल बजट है। शेष अस्पतालों में ऑर्डिनरी बजट से व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जो मेडीकल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब के केन्द्रों पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। मेडीकल के हिसाब से जो जिले हैं उनके केन्द्रों पर मरीजों के मनोरंजन के लिये सब चीजें उपलब्ध हैं या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जहां जहां सुविधायें दी गई हैं उनका जिक्र लिस्ट में है। बहुत सी जगहों पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर पाये हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या मंत्रीजी ने यह जानने की कोशिश की है कि सूची में कहीं पर एक रेडियो है, कहीं पर दो रेडियो हैं और कहीं कहीं पर दूसरे सामान हैं; तो यह अलग अलग तरह की व्यवस्था क्यों है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जैसा जैसा सामान मिला वैसा वैसा प्रोवाइड किया है।

डॉ० चन्द्रकला : सवाई मानसिंह अस्पताल में एक रेडियो है और उदयपुर में सब जगह रेडियो है। क्या यह माना जाय कि सवाई मानसिंह अस्पताल में इसलिये नहीं रखा कि उपलब्ध नहीं हुआ ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : रेडियो वगैरह मेन्टल हॉस्पिटल्स में या टी. बी. अस्पताल में रखे जाते हैं। जगह जगह रख देंगे तो रोगियों का रहना मुश्किल हो जायेगा।

डॉ० चन्द्रकला : क्या मंत्रीजी ने यह जानने की कोशिश की है कि टी. बी. सेनिटोरियम या मेन्टल हॉस्पिटल में भी नहीं है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : आप बता दीजिये किनमें नहीं है ?

Page No 8

डॉ० चन्द्रकला : जो सूची में दिया है उससे अलग उत्तर जुबानी दे रहे हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कौन सा ?

डॉ० चन्द्रकला : आप बता रहे हैं कि केवल मानसिक अस्पतालों में और टी. बी. सेनिटोरियम में रखा है जब कि सूची में ऐसा नहीं है, ऑर्डिनरी जगह भी रखा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कहीं कहीं पर है। खास कर मेन्टल हॉस्पिटल्स और टी. बी. सेनिटोरियम में हैं। दूसरी जगह कहीं कहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को कहना चाहती हूँ कि उन्होंने सूची नहीं देखी है, सूची में बिल्कुल भिन्न तथ्य है, जो आप कह रहे हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकार ने जानने का प्रयत्न किया है कि अस्पतालों में रोगियों के मन बहलाव और मानसिक स्वास्थ्य के लिए किन किन उपकरणों की आवश्यकता है और कितने अंशों में दिये जाने चाहिए ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अगर माननीय सदस्या कोई सुझाव देंगी तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

डॉ० चन्द्रकला : क्या माननीय मन्त्री ने माननीय सदस्या या किसी और से सुझाव लेने का प्रयत्न किया है ? उनकी बुद्धि नहीं चलती है तो किसी से सुझाव लेते।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपको सुझाव देने के लिए ना नहीं किया होगा।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : मनोरंजन के बारे में माननीय सदस्या से मंत्री महोदय ने सुझाव क्यों नहीं लिये ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

तहसील दौसा में हुई चोरियां

६६६. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(क) तहसील दौसा में सन् १९५९–६० में कितनी चोरियां कौन कौन से ग्रामों में हुई ?

(ख) पुलिस ने कितनी चोरियां बरामद करवाई ?

(ग) पुलिस ने कितने चोरों को अदालत में पेश किया और उनमें से कितनों को दण्ड दिया गया ?

पृथक राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) तहसील दौसा में १–४–५९ से ३१–३–६० तक कुल ५७ चोरियां तथा नकबजनियां हुई। दौसा में २६, कुण्डल में २, निमाली में १, गोली का बास में १, मेसरा कलां में १, नागल में १, आलिदा में ५, बड़ा गांव में १, जफूता में १, जटवाड़ा में १, मंडाना में १, जसूता में २, पाटन में २, भाकरी में १, रूगली में १, हिंगोरियां में १, किरोली में १, जिदीता खुर्द में १, माडरिज में ३, धारीवास में १, बासी में १, श्यामबास में १ तथा लांटवाड़ा में १ चोरियां हुई।

(ख) इनमें पुलिस २९ चोरियों का पता

Page No 9

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

लगा सकी।

(ग) पुलिस ने ५२ अपराधियों का चालान किया जिनमें से ३ को सजा हुई, १८ को मुकदमों में राजीनामा होने से छोड़ा गया २० के मुकदमे अदालत में विचाराधीन है तथा २ बरी या रिहा हुए हैं।

श्री रामधन : कुल कितनी रकम की चोरियां हुई हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : कुल ३१, ०५६. ५६ नये पैसे की चोरी हुई है।

श्री रामधन : इसमें से उन ग्रामीणों को कितना वापिस दिया गया जिनकी चोरियां हुई ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी ?

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): इसमें से कितनी बरामद हुई और कितना रुपया दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : रिकवरी का पर्सेंटेज क्या है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ४५ पर्सेन्ट रिकवरी हुई है।

श्री रामधन : बाकी चोरियां मिलेंगी या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने जवाब में अर्ज कर दिया है कि जितनी चोरियों का पता लगा वे २६ हैं, बाकी का पता नहीं लग सकता।

श्री अध्यक्ष : तफतीश जारी है, उम्मीद कम है।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : यह मान कर चलते हैं कि आशा नहीं है।

प्रश्न संख्या ६७०

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३७१

श्री नारायणसिंह।

(अनुपस्थिति कृपया आगे देखिये।)

डॉ० बहादुरसिंह।

राजस्थान विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक फैकल्टी की स्थापना

६७२. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान विश्व-विद्यालय में कितनी फैकल्टीज़ हैं ?

(२) क्या विश्व-विद्यालय में आयुर्वेद फैकल्टी की स्थापना सम्बन्धी विचार विश्वविद्यालय सीनेट के समक्ष उपस्थित हैं ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय लिया जावेगा ? अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(डॉ० बहादुरसिंह)

(३) आयुर्वेद फैकल्टी विश्व विद्यालय में स्थापित करने में क्या क्या असुविधा विश्वविद्यालय महसूस कर रहा है ?

पृथक राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र-चौधरी) : The University of Rajasthan has at present the following faculties:-

1. Arts.
2. Science. (Including Agriculture)
3. Commerce.
4. Engineering and Technology.
5. Law.
6. Medicine, Pharmaceutics and Veterinary Science.
7. Education.

2. Yes, the University is concidering the Question of setting up a Faculty of Ayurved. A committee of experts on the subject has been appointed to examine the proposal in all its aspects. The report of the committee will be considered by the Academic Council which will make its recommendations to the Syndicate. The Syndicate will finally decide the question. It will take some time before a final decision is arrived at.

3. Unless the report of the Expert Committee is available it is premative to say anything about the difficulties in the implementetion of the proposal for establishment of a Faculty of Ayurved.

डॉ० बहादुरसिंह : यह जो कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाने की आशा है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इस प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में क्यों दिया गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह नहीं कह सकता। एक्सपर्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है, किस तारीख तक रिपोर्ट भेज देंगे, यह नहीं कहा जा सकता।

डॉ० बहादुरसिंह : कुछ लिमिटेशन है, दो महीने, चार महीने ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : कुछ लिमिटेशन फिक्स-अप नहीं की है। कमेटी के सुपुर्द की है, वह जांच करके ओपिनियन देगी तब आयेगा।

डॉ० बहादुरसिंह : उस कमेटी में कौन कौन है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अलग से सवाल है। आप अलग से पूछें तो बता सकता हूँ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : कमेटी नियुक्त कब हुई ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : तारीख मैं नहीं बता सकता।

श्री अध्यक्ष : यह बहुत आवश्यक प्रश्न है। माननीय सदस्य समय समय पर कहते रहे हैं। आप कृपया ताकीद करें।

Page No 11

एक माननीय सदस्य : मन्त्री महोदय तारीख नहीं बता सकते, बिल्कुल गोलमाल जबाब है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आजकल आपकी कैसे नहीं बन रही है इनसे ?

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : गंगानगर........

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

राजस्थान अपीलेट ऑथोरिटी के विचाराधीन मामले

६७३. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान अपीलेट ऑथोरिटी (अपाइन्टेड अन्डर दी इंडियन मोटर विहीकल्स एक्ट एण्ड रूल्स) की १ अप्रेल, सन् १९६० के पश्चात् किस किस तारीख को कितनी कितनी बैठकें हुई हैं और इसके कौन कौन सदस्य इन बैठकों में उपस्थित रहे हैं ?

(ख) इन बैठकों में से किस किस बैठक में कितनी कितनी अपीलों की सुनवाई हुई और कितनों में फैसले किये गये ?

(ग) १ अप्रेल, सन् १९६० को कितने मामले इस ऑथोरिटी के विचाराधीन थे और उसके पश्चात् १ जनवरी, सन् १९६१ तक कितनी और अपीलें दायर की गई हैं ? ये कुल अपीलें कब कब से विचाराधीन हैं और किस रूट से सम्बन्धित हैं ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

पृथक राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) अप्रेल १९६० के पश्चात् अपीलेट ऑथोरिटी की कोई मीटिंग १५ दिसम्बर १९६० तक नहीं हुई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) १–४–६० को कुल ४०२ अपीलें पेंडिंग थीं। उसके पश्चात् १–१–१९६१ तक ३३४ अपीलें और दायर की गई। इनमें कुछ अपीलें १९५९ में दायर हुई, बाकी सन् १९६० की हैं। अपील किन किन रूटस से सम्बन्धित हैं, इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री भैरोंसिंह : १५ दिसम्बर, १९६० के बाद में अपीलेट ऑथोरिटी की मीटिंग कब कब हुई हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसकी ७६ मीटिंगें हुई हैं और २४२ अपीलें फैसल हुई हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह बतायें कि १५ दिसम्बर, १९६० तक कोई मीटिंग नहीं हुई, इसके बाद कब कब मीटिंग हुई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह निवेदन किया कि १५ दिसम्बर, १९६० के बाद २७ मार्च तक ७६ बैठक हुई हैं और उनमें २४२ अपीलें फैसल हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : १५ दिसम्बर से लगा करके........

Page No 12

श्री रामचन्द्र चौधरी : १५ दिसम्बर से लगा कर २७ मार्च, १९६१ तक ७६ मीटिंगें हुई हैं।

श्री भैरोंसिंह : हो तो नहीं सकती, कुछ जंचता नहीं है; जनवरी, फरवरी, मार्च में दिन होते हैं कुल इतने।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : चार महीने हो गये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : काम बहुत पेंडिंग था इसलिए कन्टीन्युअसली मीटिंग्ज़ होती रहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि १५ दिसम्बर, ६० से लेकर २७ मार्च, ६१ तक ७६ मीटिंग्ज़ कर लीं और १५ अप्रेल से दिसम्बर तक कोई मीटिंग नहीं हुई, इसका क्या कारण है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : हाई कोर्ट में एक रिट पर यह मुकर्रर कर दिया गया कि मिनिस्टर इन चार्ज को जुडिशियल तजुर्बा नहीं है, इसलिए ट्रिब्यूनल के चेयरमैन नहीं हो सकते। उस फैसले के कारण मीटिंग रुकी रही। बाद में जब दूसरे मिनिस्टर लगे तो उन्होंने यह समझा कि लीगल हिच को दूर करके ही दूसरी मीटिंग की जाय। उन्होंने बीच में एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें लीगल रिमेम्ब्रेन्सर के नाम से बुला लिया जो दूसरे पहले के लॉ सेक्रेटरी थे। इसलिए वह मीटिंग बीच में पोस्टपोन करनी पड़ी।

श्री भैरोंसिंह : आप यह बतायें कि १५ अप्रेल, १९६० के बाद जब १०८ में अमेंडमेंट किया जाकर हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार जुडिशियल एक्सपीरियेन्स की बात को हटा दिया गया तो माननीय मन्त्री जो अपीलेट ऑथोरिटी के चेयरमैन हुए थे उन्होंने सोचा कि मैं जुडिशियल एक्सपीरियेन्स का आदमी नहीं हूं और जितनी व्यवस्था की गई है वह हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार नहीं की गई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मन्त्री महोदय ने सोचा कि दूसरा ट्रिब्यूनल कायम करके ही उसके सुपुर्द काम किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : जब उन्होंने ऐसा महसूस किया तो जो दूसरा ट्रिब्यूनल कायम कर दिया उसे १५ दिसम्बर तक इग्नोर क्यों किया, उसके बाद क्यों किया, उसके स्वयं सभापति कैसे रहे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो ट्रिब्यूनल है वह वन मेम्बर ट्रिब्यूनल है, उसमें सभापति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह कब से बना है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो अपीलें डिसाइड की गई वे वन मेम्बर ऑथोरिटी से हुई हैं, जिसके लोढ़ावाल मेम्बर हैं।

श्री भैरोंसिंह : कब से बनी है ?

श्री अध्यक्ष : दिसम्बर, १९६०।

(विराम)

डॉ० चन्द्रकला।

Page No 13

जयपुर शहर की आवास समस्या के हल हेतु योजनायें

६७४. डॉ० **चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इस समय जयपुर शहर की कितनी और कौन कौनसी आवास योजनायें सरकार के पास आई और उनमें से कितनी स्वीकृत हुई ?

(२) क्या इन योजनाओं के अन्तर्गत प्लॉटों का अलॉटमेंट शुरू हो गया है ? यदि हां, तो कब से ? अब तक कितने प्लॉट्स लोगों को दिये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) जयपुर शहर की आवास समस्या को हल करने के निमित्त सरकार क्या उपाय सोच रहो है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) इस समय नगर विकास मंडल द्वारा प्रेषित केवल आगरा-रोड नाम की योजना सरकार के विचाराधीन है। ट्रस्ट बन जाने के बाद से अभी तक कोई योजना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जयपुर नगर की आवास समस्या को हल करने के लिये अभी एक ट्रस्ट बनाया गया है। उसकी कार्यविधि के नियम आदि बन रहे हैं। कई योजनायें ट्रस्ट के विचाराधीन हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं :—

१—लालकोठी योजना: जिसमें लगभग २,००० भूखण्ड होने की सम्भावना है। इसका प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो चुका है तथा अवाप्ति की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

२—हसनपुरा योजना : यह नेशनल बॉलबियरिंग कम्पनी के पास बसी हुई है। इसी नाम की बस्ती को सुचारु रूप से बसाने की योजना है। यह लगभग तैयार हो चुकी है तथा शीघ्र ही राज्य सरकार की स्वीकृति के लिये प्रेषित की जाने वाली है। इसमें लगभग ३०० भूखण्ड होंगे।

३—बढ़ोदिया योजना : यह योजना स्टेशन के पास बनाई जा रही है। इसमें १३१ भूखण्ड होंगे। इसका मानचित्र करीब करीब पूरा हो चुका है।

४—गंगा टॉकीज़ के पीछे की योजना: यह योजना भी लगभग पूर्ण हो चुकी है तथा शीघ्र ही राज्य सरकार की स्वीकृति के लिये प्रेषित की जाने वाली है। इसके अतिरिक्त और भी कई छोटी छोटी योजनायें तैयार की जा रही हैं तथा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट इस समस्या को हल करने के लिये पूर्ण सचेष्ट है।

डॉ० **चन्द्रकला** : क्या अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को अलॉटमेंट करने के पॉवर्स हैं ?

श्री सम्पतराम : जी हां, उनको अलॉटमेंट करने के पॉवर्स हैं, पर इस प्रश्न को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। वह यह है कि जो योजनाएं बन चुकी हैं उनमें से कुछ का एग्ज़ीक्युशन हो चुका है और कुछ का नहीं हुआ है। इन स्कीम्स के अलॉटमेंट के लिये

Page No 14

(श्री सम्पतराम)

अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट में कोई व्यवस्था नहीं है। पर सरकार और सेक्रेटरी, डिप्टी-सेक्रेटरी विचार करके तय करें कि किस प्रकार के नियम अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट के तहत होने चाहिये। बोर्ड को अलॉटमेंट के अधिकार हैं, बशर्ते कि व्यवस्थित योजना बना कर अलॉटमेंट करे।

डॉ० चन्द्रकला : वैसे तो पॉवर हैं, पर व्यवहारिक तौर पर अलॉटमेंट करने के पॉवर नहीं हैं। इसके माने यह हैं कि कहीं न कहीं कानूनी खामी रह गई है और बोर्ड की शक्तियां ट्रस्ट को नहीं दीं, इसलिये अलॉटमेंट के पॉवर्स नहीं दिये हैं, क्या यह सच नहीं है ?

श्री सम्पतराम : जी नहीं, पूर्ण स्वतन्त्रता है। कुछ रूल्स हमें बनाने चाहिये और कुछ रूल्स उन्हें बनाने चाहिये। जो ऑलरेडी स्कीम्स थीं उनमें इतना अमेंडमेंट करना पड़ेगा। उसके अलावा अलॉटमेंट करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से एप्रूव कराना पड़ेगा।

डॉ० चन्द्रकला : जो रूल्स बनाने थे सरकार कब बना कर भेज देगी ?

श्री सम्पतराम : जल्दी ही भेज देगी।

श्री लादूराम सुलाणियां (दूदू-सु.) : क्या यह सही है कि बोर्ड के अलावा मन्त्रीजी को पॉवर्स हैं ?

श्री सम्पतराम : गवर्नमेंट को तो इन्हेरेन्ट पॉवर्स हैं ही !

श्री लादूराम सुलाणियां : इस अधिकार से कितने लोगों को प्लॉट दिये गये।

प्रश्न संख्या ६७५

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन।

राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र की जमीन के आवंटन हेतु नियम

६७६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मन्त्री, राजस्थान केनाल विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र की जमीनों के अलॉटमेंट के नियम तैयार कर लिये गये हैं ? अगर नहीं, तो कब तक तैयार कर लिये जावेंगे ?

पृथक राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : जी नहीं।

उपनिवेशन नीति, जो सरकार के विचाराधीन है, के निश्चित हो जाने पर नियम बनाये जायेंगे।

श्री भीमसेन : कब से विचाराधीन है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी: कोलोनाइजेशन कमिश्नर ने रूल्स बना कर भेज दिये हैं और

(श्री रामचन्द्र)

केबिनेट के कन्सीडरेशन में हैं।

श्री भीमसेन : केबिनेट के कन्सीडरेशन में कब से हैं ?

प्रश्न संख्या ६७७

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६७८

श्री मोगजी भाई।

बांसवाड़ा जिले के जंगल एरिया के सेटलमेन्ट का कार्य

६७८. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या वन विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले के जंगल एरिया के सेटलमेंट का कार्य संपूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो कौन २ से रिजर्व जंगल घोषित किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या रिजर्व जंगल के अलावा जो जंगल एरिया गांवाई घोषित किया है जो वृक्षहीन एरिया है और क्या उसको ग्राम पंचायतों के अधीन दिया जाने का विचार सरकार रखती है ? यदि हां, तो वह कब तक दे दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को वृक्ष लगाने के लिये ७५ प्रतिशत रकम प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता के रूप में देने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित कर दी जावेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं एडजोर्नमेंट रिक्वेस्ट करूंगा, इसका अगली टर्न पर जवाब दिया जायेगा।

श्री मोगजी भाई : क्यों साहब, जवाब दिया नहीं ?

श्री अध्यक्ष : कहा न कि दूसरे टर्न पर जवाब दिया जायेगा।

(विराम)

श्री मूलचन्द डागा।

सरदारसमन्द बांध से असिंचित भूमि का नहरी लगान

६७९. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) पाली तहसील के सरदार समन्द बांध द्वारा सरदार समन्द फार्म के अलावा कुल कितनी जमीन की सिंचाई होती है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस बांध द्वारा पिछले तीन सालों से नहरी पानी से जमीन की सिंचाई नहीं हो रही है ? यदि हुई है, तो सन् १९५८—५९ व १९६० में कितनी २ जमीन की सिंचाई हुई ?

(ग) क्या यह सत्य है कि सिंचाई न होने

(श्री मूलचन्द डागा)

पर भी खातेदारों से नहरी जमीन की दर से लगान वसूल किया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व जोधपुर स्टेट के जमाने में जब जमीनों की पिलाई बांध से नहीं हो पाती थी तो काश्तकारों से नहरी जमीन का लगान वसूल नहीं किया जाता था ? यदि हां, तो फिर इस समय पूरा लगान क्यों वसूल किया जाता है ?

(ङ) क्या यह सत्य है कि बीकानेर डिविजन में भी अभी तक उस जमीन का नहरी लगान नहीं लिया जाता है, जिस जमीन में नहरी पानी उपलब्ध नहीं होता है ? यदि हां, तो फिर सरकार द्वारा सरदार समन्द बांध से सिंचित नहरी जमीन वालों से जमीन सिंचित नहीं होने की अवस्था में भी नहरी लगान क्यों वसूल किया जाता है ?

पृथक राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) पूरा भरने पर इस तालाब से १८,००० एकड़ भूमि में सिंचाई की जा सकती है। पिछले १० सालों में जैसे सिंचाई की गई उसकी सूची संलग्न है।

(ख) पिछले तीन सालों में इस तालाब में पानी कम आया था, इस कारण नहरी जमीन में सिंचाई कम हुई। प्रश्न (क) के उत्तर में दी गई सूची में सिंचित जमीन बताई हुई है।

(ग) जी हां।

(घ) कहीं कहीं था।

(ङ) प्रश्न विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : एक जगह तो कह रहे हैं कि जिस जमीन की सिंचाई नहीं होती थी वहां सिंचाई लगान वसूल नहीं होता था, दूसरी जगह जहां पहले ३६ हजार बीघा जमीन की सिंचाई होती थी वहां १,१३६ बीघा और १,६०० बीघा ही सिंचाई हुई है; फिर भी सारी जमीन का पूरा नहरी सिंचाई का लगान लिया है !

श्री अध्यक्ष : कहा न कि विचार हो रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : लगातार तीन साल हो गये वहां नहर से पानी नहीं दिया जाता है। जोधपुर स्टेट के जमाने में यह था कि जिस साल नहर से पानी नहीं दिया जाता था उस साल नोमिनल फीस ली जाती थी, पर अब ऐसा है कि गत तीन साल से बन्ध में पानी नहीं आया है और लोगों को सिंचाई के लिये पानी नहीं दिया है, फिर भी उनसे पूरा नहरी सिंचाई का लगान वसूल किया रहा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : क्या आपकी यह मंशा है कि नहरों की जितनी दर है उनसे कोई रियायत की दर फिक्स की जावे ?

श्री मूलचन्द डागा : मैंने यह प्रश्न किया है कि बीकानेर डिविज़न में यह है कि यदि किसी साल नहरों से जमीन की सिंचाई नहीं होती है तो उन लोगों से नहरी लगान नहीं लिया जाता है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : बीकानेर डिवि-

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

जन में तो गंग नहर से सिंचाई होती है, माफ करने का सवाल नहीं।

श्री अध्यक्ष ; नेक्स्ट ! श्री पृथ्वीराज पटेल !

वामनवास कसबे को बिजली

६८०.**श्री पृथ्वीराज पटेल** (गंगापुर-सु.) क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या लालसोट से गंगापुर बिजली जाने वाली लाइन पर कस्बा वामनवास पड़ता है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस कस्बे की आबादी लगभग ६,००० है व कई सरकारी कार्यालय भी हैं ?

(ग) क्या वामनवास कस्बे को उक्त लाइन से बिजली दी जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, तृतीय पंचवर्षीय योजना में।

श्री पृथ्वीराज पटेल : जो किताब दी गई है उसमें वामनवास को लालसोट—गंगापुर लाइन पर कहीं नहीं बताया गया है।

श्री हरिश्चन्द्र : कौन से प्लान में आप फर्मा रहे हैं ? मैंने कहा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में विचाराधीन है, लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

टौंक से सवाई माधोपुर जाने वाली बस का उनियारा होकर नहीं जाना

६८१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि टोंक से सवाई माधोपुर को बस सर्विस चलती है ? अगर हां, तो किस कम्पनी की और उसका रूट कहां होकर रखा गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त बस उनियारा होकर नहीं जाती है ? अगर हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि उनियारा की जनता को सवाई माधोपुर जाने में रेल से जाना पड़ता है ?

पृथक राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) जी हां। निम्नलिखित तीन कम्पनियों की बसें। टौंक से वाया चंदलाई खास, काकोड़, सोताड़ा, अलीगढ़ कुसतला होकर ३ बसें सवाई माधोपुर चलती हैं :

१. जसवन्तसिंह आर. जे. यू. २३५

२. महमूदखां आर. जे. एक्स. २६

३. बद्रीदास कन्हैयालाल आर. जे. एक्स. ५१।

Page No 18

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

(ख) जी हां। उनियारा, अलीगढ़, आमली होकर एक दूसरी बस चली गई है।

(ग) उनियारा की जनता रेल द्वारा भी सवाई माधोपुर जा सकती है और यदि बस द्वारा पहुँचना हो तो उनियारा, अलीगढ़, आमली बस सर्विस से अलीगढ़ पहुंच कर टोंक—सवाई माधोपुर वाली बस में बैठ कर सवाई माधोपुर पहुँचा जा सकता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने कहा कि आमली होकर जाना पड़ता है तो आगे माधोपुर जायं तो भी रेल में बैठना पड़ता है, क्योंकि टोंक से सवाई माधोपुर जाती है वह बस ऐसे टाइम पर जाती है कि इस आमली वाली बस से क्रॉस नहीं करती।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उनियारा-अलीगढ़—आमली वाली बस दिन को १२ बजे उनियारा से रवाना होकर ढाई बजे अली-गढ़ पहुंचती है और सवाई माधोपुर वाली बस टोंक से १॥ बजे रवाना होकर ढाई बजे अलीगढ़ पहुँचती है। इस बस में ३ बजे बैठ कर साढ़े पांच बजे सवाई माधोपुर पहुँच सकते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि टोंक से सवाई माधोपुर जो बस जाती है उसके बीच में जो बड़े बड़े कस्बे हैं उनको छोड़ कर बस बिल्कुल जंगल में होकर जाती है, बड़े बड़े कस्बों को डेलिबरेटली छोड़ दिया गया है, इस तरह का रूट बनाया गया है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : डेलिबरेटली बड़े कस्बों को छोड़ कर रूट बनाया हो, यह समझ में नहीं आता, क्योंकि रूट तो कमाने के लिये बनाते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कमाने का सवाल पैदा नहीं होता, ६,००० के कस्बों को छोड़ दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

बांगड़ अस्पताल, पाली

६८२. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या मन्त्री, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

पाली स्थित बांगड़ अस्पताल की व्यवस्था के बारे में कितनी शिकायतें गत वर्ष सरकार व जिला स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष आई और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

पृथक राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : गत वर्ष केवल एक शिकायत जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष आई थी जिसकी जांच के पश्चात् स्टाफ नर्स श्रीमती जैड. एच. दास को आयंदा रोगियों के साथ अच्छा व्यवहार करने व समय पर दवा आदि देने के लिये लिखित वार्निंग दे दी गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के बाजार की सड़क का निर्माण कार्य

६८३. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर):

Page No 19

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

क्या मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में बाजार के अन्दर सड़क के लिये सोलिंग किये हुए कितने वर्ष हुए ?

(२) इस सड़क का कार्य पूरा क्यों नहीं होता है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) दो वर्ष।

(२) कार्य कुछ दिन बन्द रहा, अब फिर चालू कर दिया गया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि जिस समय केबिनेट की मीटिंग हुई थी तो इस प्रकार का आश्वासन दिलाया गया था कि कार्य विभाग द्वारा कराया जावेगा, यह काम म्युनिसिपैलिटी द्वारा नहीं कराया जा रहा है ?

श्री सम्पतराम : जी हां। यह काम पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा किया जा रहा है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि इस सड़क के सम्बन्ध में इस प्रकार की शिकायत हुई थी कि सड़क के मामले में गबन हुआ है ?

श्री सम्पतराम : जी हां।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सम्पतराम : एन्टीकरप्शन के सामने केस पेण्डिंग है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कब से ?

श्री सम्पतराम : तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : मैं यह नहीं समझ पाया कि एन्टीकरप्शन में गबन के केसेज़ कैसे जाते हैं ? गबन के केसेज़ एन्टीकरप्शन के पास लेकर जाते हैं तो एन्टीकरप्शन वाले कहते हैं कि एम्बेजलमेंट के केसेज की जांच एन्टीकरप्शन में नहीं की जाती। फिर यह गबन का केस एन्टीकरप्शन में कैसे गया है ?

श्री सम्पतराम : वह माननीय सदस्य चाहें तो सेपरेट क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, मैं इस समय नहीं बता सकता कि गबन के आधार पर गया है या किसी और आधार पर ?

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि गबन का मामला एन्टीकरप्शन को दिया गया, इसलिये पूछा है।

श्री सम्पतराम : यह आपका प्रिज़म्प्शन हो सकता है, पर................

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सतवन्तकौर।

आर बी. लोपर नहर पर पुल निर्माण

६८४. **श्रीमती सतवन्तकौर** (श्री-करणपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

Page No 20

(श्रीमती सतवन्तकौर)

(१) क्या यह सत्य है कि पदमपुर से जो कच्ची सड़क ५० आर. बी. होती हुई डाबला को जाती है उस पर आर. बी. लोपर नहर पर कोई पुल नहीं है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि दूसरा पुल २ मुरब्बे की तरफ को है और वह भी टूटा हुआ है जिसके कारण पदमपुर से सूरतगढ़ को जो बसें चलती हैं उनको ३-४ मील का चक्कर लगा कर जाना पड़ता है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार आर. बी. लोपर पर पुल बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

पृथक राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (१) पदमपुर—सूरतगढ़ सड़क (बारास्ता तामकोट) पर एक पुलिया १६४८६ आर. डी. पर आर० बी० लोअर पर बनी हुई है ।

(२) पदमपुर से सूरतगढ़ जाने वाली बसें डाबला से होती हुई आर० बी० लोअर नहर की बुर्जी नं० १६४८५ पर स्थित पुल से गुजर कर जाती है । इस पुलिया की पट्टियां टूट गई थीं जिनकी अब मरम्मत की जा चुकी है और अब इस प्रकार की शिकायत नहीं रही है ।

(३) प्रश्न नहीं उटता ।

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या यह सही है कि आगे तक दूसरी जगह बनी हुई है जहां बननी चाहिये तीन मुरब्बा दूर तक बनी है ?

श्री रामचन्द्र. चौधरी : पुल दूसरी बनाना चाहें तो भी इसके लिये फायदा है । कलेक्टर को रिपोर्ट करें उनकी सिफारिश पर उचित कार्यवाही की जा सकती है ।

एक माननीय सदस्य : आपने बताया कि यह पदमपुर से सूरतगढ़ जाने वाली बसें डाबला से होती हुई आर. बी. लोअर नहर की बुर्जी पर स्थित पुल से गुजर कर जाती हैं तो यह रूट कब चला ?

श्री रामचन्द्र चौधरी: रूट मैंने आपको बता दिया है ।

एक माननीय सदस्य : यह डाबला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, रावराजा श्री सरदारसिंह ।

टौंक से इन्द्रगढ़ जानेवाली बस का उनियारा होकर जाना

६८५. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सही है कि टौंक से इन्द्रगढ़ (कोटा) को कोई बस सर्विस चलती है ? अगर हां, तो किस रूट से ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त बसें उनियारा होकर नहीं गुजरतीं ? अगर हां, तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या यह सही है कि उनियारा की जनता को इन्द्रगढ़ जाना होता है तो चौथ

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

का बरवाड़ा सवाई माधोपुर होकर कोटा लाइन से रेल में जाना पड़ता है ?

पृथक राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) जी हां । टौंक से इन्द्रगढ़ बस सर्विस वाया मामोरा, बानेटा, अलीगढ़, खाटोली, बिसनपुरा होकर चलती है ।

(ख) जी हां । उनियारा होकर दूसरी बस टौंक, उनियारा, अलीगढ़, आमली होकर चलती है इस कारण से टौंक से इन्द्रगढ़ जो बस चलती है वह उनियारा होकर नहीं चलती ।

(ग) यह सही है कि उनियारा की जनता को यदि इन्द्रगढ़ जाना हो तो वह रेल द्वारा सवाई माधोपुर से होकर कोटा लाइन से जा सकती है और यदि मोटर द्वारा उनियारा से इन्द्रगढ़ पहुंचना हो तो टौंक, उनियारा, अलीगढ़, आमली बस सर्विस द्वारा आमली पहुंच कर वहां से इन्द्रगढ़ पहुंचा जा सकता है जो करीब ५ मील का फासला है । दूसरे अलीगढ़ पहुंच कर वहां से टौंक इन्द्रगढ़ वाली बस को बदल कर इन्द्रगढ़ पहुंचा जा सकता है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि टौंक से इन्द्रगढ़ अलीगढ़ होकर जाती है वह किस आधार पर बताया है ? वह अलीगढ़ होकर तो जाती नहीं । उसका रूट बनेटा, डाबली आदि से होती हुई इन्द्रगढ़ होकर जाती है । अलीगढ़ का नाम माननीय मन्त्री ने कैसे लिया, यह समझ में नहीं आया ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या यह सही है कि उनियारा में ज्यादा आदमी सवारी के लिये नहीं मिलते ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं यह निवेदन करूंगा कि वह बस अलीगढ़ होकर नहीं जाती । वह उनियारा से एक मील दूर होकर जाती है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : टौंक से १२ बजे रवाना होकर २॥ बजे उनियारा पहुंचती है और ४ बजे अलीगढ़ पहुंचती है । उनियारा २॥ बजे पहुंचा देती है.....

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि टौंक से इन्द्रगढ़ कैसे पहुंचते हैं ?

प्रश्न संख्या ६८६

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल ।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित

दौसा लालसोट सड़क पर पड़ने वाले नाले

६८७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सच है कि दौसा-लालसोट सड़क पर सात नाले बड़े बड़े हैं जिससे बरसात में यातायात रुक जाता है और मोटर्स दलदल में फंस जाती है जिससे सवारियों को परेशानी उठानी पड़ती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी हां। छोटे बड़े कुल मिला कर ६-७ नाले हैं। इनके कारण जब कभी अधिक वर्षा हो जाती है तब मोटरों को रुकावट हो जाती है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : ये नाले कब तक बनवा दिये जावेंगे ?

श्री अध्यक्ष : क्या नालों पर पुल बनाने की योजना है ?

श्री हरिश्चन्द्र : तीसरी पंच वर्षीय योजना में इसके लिये दो लाख रुपये रखे गये हैं और आशा की जाती है कि इससे नालों का काम जल्दी शुरू कर दिया जावेगा।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या यह सही है कि इसके लिये एस्टीमेट बना कर भेज दिया गया था ? गवर्नमेंट ने इसके लिये एस्टीमेट मांगा था और ६ महीने हुए एस्टीमेट भेज दिया गया, क्या यह बात सही है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है।

प्रश्न संख्या ६८८

श्री अध्यक्ष : श्री रावतमल पारीक।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६८९

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

भीलवाड़ा में गांधी सागर स्थित शिव-मन्दिर की मूर्तियों का भंजन

६९०. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भीलवाडा में गांधी सागर स्थिति शिव मंदिर की मूर्तियों को कुछ गुण्डों ने तोड़ दिया है ?

(२) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पृथक राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (१) जी हां।

(२) धारा २९५ भारतीय दण्ड संग्रह के अधीन प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है। गुप्तचर विभाग द्वारा भी इसकी जांच करवाई गई परन्तु अभी तक अपराधी का पता नहीं लग पाया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह किस तारीख को केस हुआ था ; यह मामला कब हुआ ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : १९-२-६१ को।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया कि अभी तक कोई इसका सुराग नहीं लगा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। रावराजा श्री सरदारसिंह।

टौंक-लाखेरी से तथा लाखेरी-वाही-इन्द्रगढ़-खातोली-उनियारा टौंक सड़क का निर्माण

६६१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि टौंक से लाखेरी और लाखेरी से वाही—इन्द्रगढ़—खातोली—उनियारा टौंक की सड़क निर्माण की स्वीकृति हो चुकी थी ?

(२) अगर हां, तो इस कार्य के हेतु सन् १६५८-५६ व ५६-६० के बजट में कितनी कितनी धनराशि रखी गई थी और उसमें से कितनी खर्च की गई और कितनी बाकी रही है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क का कार्य चालू है ? अगर हां, तो वह कहां तक तैयार हो चुकी और अब कितनी बाकी है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): (१) जी हां, टौंक से उनियारा तक सड़क बनाने को स्वीकृति हो चुकी थी। उनियारा से खातोली होती हुई इन्द्रगढ़ के टुकड़े की स्वीकृति अभी तक नहीं दी गई है।

(२) वर्ष	स्वीकृति	व्यय
१६५८–५६	६०,००० रु.	६७,०१५ रु.,
१६५६–६०	१,०१,००० रु.	६६,७४६ रु.।

(३) इस सड़क का कार्य स्वीकृति के अनुसार टौंक से उनियारा तक करीब २ पूर्ण कर दिया गया है। उनियारा तक सड़क बन कर तैयार हो चुकी है, सिर्फ ४ फर्लांग का टुकड़ा उनियारा से अलीगढ़ के बीच बाकी है जिसका कार्य चालू है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह सड़क कुल कितनी लम्बी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ३७ मील।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अलीगढ़ माधोपुर के लिये लाखेरी की सड़क उनियारा तक बन गई है। लेकिन उनियारा से लाखेरी की सड़क नहीं बनी। जहां कोटा और बूंदी का था उसको बना कर डामर हो चुका है।

श्री हरिश्चन्द्र : इसको तीसरी पंच-वर्षीय योजना में लेने की कोशिश की जायेगी।

प्रश्न संख्या ६६२.

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री किशनाराम।

रतनगढ़ नगरपालिका के निर्वाचित अस्थायी अध्यक्ष, पं. खेमचन्द्र शर्मा को पुनः कार्यभार सम्भलवाना

६६३. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) :

(श्री किशनाराम)

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि नगरपालिका रतनगढ़ के समस्त सदस्यों ने दिनांक २-४-६० को उपस्थित होकर सर्व सम्मति से पं० श्री खेमचन्द्र शर्मा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया था ?

(ख) क्या यह सही है कि दिनांक ४-४-६० को पं० खेमचन्द्र शर्मा ने अध्यक्ष पद का कार्यभार सम्हाल कर कलेक्टर, चुरू, स्थानीय निकाय, जयपुर एवं स्वायत्त शासन सचिव, जयपुर को विधिवत् सूचित कर दिया था।

(ग) क्या यह सही है कि इसके बाद भूतपूर्व उपाध्यक्ष, श्री मनसुखराम को पालिका के अध्यक्ष का कार्य करने का आदेश किसी अधिकारी द्वारा दिया गया ? यदि हां, तो नगरपालिका अधिनियम, १६५६ की किस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऐसा किया गया ?

(घ) क्या दिनांक २-४-६० को सम्पन्न हुआ अस्थायी अध्यक्ष का सर्व सम्पन्न निर्वाचन अवैध घोषित हो चुका ? यदि हां, तो कब व किस अधिकारी द्वारा ? यदि नहीं, तो सरकार ने निर्वाचित, अस्थायी अध्यक्ष पं० खेमचन्द्र शर्मा को कार्यभार वापस सम्हला देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): (क) जी हां।

(ख) निर्देश स्थानीय निकाय, जयपुर के कार्यालय में यह सूचना प्राप्त हो गई थी। सरकार के पास इसकी कोई सूचना भेजा जाना नहीं पाया जाता।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां कलेक्टर चुरू द्वारा दिनांक ४-४-६० को।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने सुना नहीं है, फिर से पढ़ दीजिये।

श्री सम्पतराम : (क) जी हां।

(ख) निर्देश स्थानीय निकाय, जयपुर के कार्यालय में यह सूचना प्राप्त हो गई थी। सरकार के पास इसकी कोई सूचना भेजा जाना नहीं पाया जाता।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां, कलेक्टर चूरू द्वारा दिनांक ४-४-६० को।

श्री भैरोंसिंह : जब डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ के पास इन्फॉर्मेशन आई तब क्या वे इन्फॉर्मेशन नहीं भेजते ?

श्री सम्पतराम : इन्फॉर्मेशन भेजने की क्या जरूरत है ? जब एक व्यक्ति का चुनाव हो गया तो....

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जावे कि सरकार ने दूसरे को नोमीनेट कर दिया।

(श्री भैरोंसिंह)

और जो कार्य कर रहा था उसको हटा कर दूसरे का चुनाव कर लिया है ?

श्री सम्पतराम : मालूम ऐसा होता है कि माननीय सदस्य इस प्रश्न को समझे नहीं हैं ।

एक चेयरमैन छुट्टी में चला गया। उसके बाद कार्यवाहक चेयरमैन की आवश्यकता हुई, उन्होंने चुना । दो दिन के बाद चेयरमैन आ गया था इसलिये वह ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाता है ।

श्री किशनाराम : क्या यह सही है कि जो अध्यक्ष छुट्टी गया था उसने खुद ने शामिल होकर दूसरे चेयरमैन का चुनाव किया था । आप दो दिन बाद की बात कहते हैं । मैं यह कहता हूँ कि वह दो दिन पहले उस चुनाव में शामिल था ।

श्री सम्पतराम : दो दिन बाद भी अगर वह वापिस आता है तो भी वही चेयरमैन रहता है ।

श्री किशनाराम : मैं यह कहूँगा कि जिस समय दूसरे चेयरमैन का चुनाव हुआ था उस समय वह उसके चुनाव में शामिल था ।

श्री लादूराम सुलाणियां (दूदू-सु०) : क्या यह सही है कि जिस समय उसका चुनाव हुआ उस समय वह विरोध में था ?

श्री सम्पतराम : यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री लादूराम सुलाणिया : आपने एक्ट में साफ माना है और आपकी तरफ से वह नियुक्त किया गया....

श्री सम्पतराम : इसके लिये रूल्स राजस्थान राज-पत्र में निकले हैं । मैं यह बता देना चाहता हूँ, हालांकि इसका कोई सम्बन्ध नहीं है कि यह एक्शन उसकी दफा ४ के अन्तर्गत किया था ।

श्री लादूराम सुलाणिया : छुट्टी में जा रहा है तो नोमिनेट क्यों किया ?

श्री सम्पतराम : हमारे सोचने समझने का यहां सवाल पैदा नहीं होता है । सरकार ने रूल्स बना रखे हैं और उनके अनुसार ही काम होता है ।

श्री किशनाराम : टोटल लोगों ने उसको चुना है, दो तारीख को आकर शिकायत करता है । वह खुद शामिल था उसमें । हमको समझना चाहिये ।

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य यदि रूल्स को पढ़ेंगे तो उनको मालूम होगा । एक दफा चेयरमैन चुन लिया जाता है तो जब तक उस व्यक्ति के प्रति कोई नौकॉन्फिडेन्स मोशन न आ जावे तब तक वह व्यक्ति चेयरमैनशिप से हट नहीं सकता है ।

श्री किशनाराम : यह बतावें कि वह व्यक्ति अल्पमत से चुना गया था या बहुमत से ?

श्री सम्पतराम : अल्पमत और बहुमत का सवाल नहीं है ।

श्री किशनाराम : क्यों नहीं है, है अल्पमत और बहुमत का सवाल ?

श्री सम्पतराम : इसलिए नहीं है कि उसको कार्यवाहक चुना गया था। दो दिन के लिए छुट्टी गया था और वह वापिस लौट आया।

श्री किशनाराम : यह झूठी बात है। वह खुद उस समय मौजूद था।

श्री अध्यक्ष : फिर भी कार्यवाहक चुन सकते हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया : पहले जो अध्यक्ष था और दूसरा कार्यवाहक चुना, तो फिर उस अध्यक्ष को निर्वाचित करने का सवाल कहां उठता है ?

श्री सम्पतराम : मेरे सवाल के उत्तर का अफसोस यह है कि माननीय सदस्य स्वयम् समझ ही नहीं सके हैं। मैंने यह कहा था कि यदि कोई नगरपालिका का अध्यक्ष छुट्टी जाता है तो रूल्स के अनुसार दूसरा कार्य-वाहक अध्यक्ष चुना जा सकता है। वह व्यक्ति जो अध्यक्ष थे वे दो-तीन दिन की छुट्टी चले गये और उनके स्थान पर छुट्टी के काल में कार्य चलाने के लिए दूसरे को कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लिया गया।

श्री किशनाराम : वे उस समय चुनाव में मौजूद थे।

श्री सम्पतराम : इससे क्या कॉन्क्ल्यूड करना चाहते हैं ?

श्री लादूराम सुलाणिया : उस अध्यक्ष के छुट्टी जाने पर दूसरा कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लिया, जब छुट्टी से आ गया तो निर्वाचन करने के लिए सरकार को आदेश देने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

श्री दलपतसिंह (आबू) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय।

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में सिरोही जिले में विद्युत व्यवस्था

६६५. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) [श्री दलपतसिंह (आबू) द्वारा पूछा गया] : Will the Power Minister be pleased to state :-

1. Whether the Government is contemplating to provide urban and rural electeification in Sirohi District during the Third Five Year Plan ?

2. If so, has the survey for the same been ordered ?

3. What is the provision kept for this electrification for Sirohi District in the Third Plan programme ?

4. Does the Government realise that without power agriculture & Indurtry in this District cannot flourish and economical prosperity among the masses cannot come ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : 1. Yes.

2. Yes.

(श्री हरिश्चन्द्र)

3. Rs. one lakh for the present for the next two years.

4. In principle, this applies to all areas in the country, but work will have to be done according to availability of funds and material.

श्री दलपतसिंह : एक लाख का पैसा लगेगा वह रूरल एरिया के लिए लगेगा या सिटी एरिया के लिए ?

श्री हरिश्चन्द्र : एक्स्टेन्शन ऑफ लाइन्स के लिए है ?

श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या प्रत्येक जिले को इस प्रकार का डिस्ट्रिब्युशन हो चुका है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी नहीं।

श्री दलपतसिंह : रूरल एरिया के लिए है ?

श्री हरिश्चन्द्र : एक्सटेन्शन ऑफ लाइन्स के लिए है।

श्री दलपतसिंह : Extension only in the municipal area or whether you will extend to the rural area also ?

श्री हरिश्चन्द्र : It will be outside the municipal area.

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : ६७० का उत्तर दिला दिया जाय।

अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड जयपुर द्वारा आवंटित भूमि

६७०. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) [डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जयपुर द्वारा ३० अक्टूबर, १९५९ के बाद के दिये हुए प्रार्थना-पत्रों पर कितनों को प्लॉट दिये गये ?

(२) दी गई जमीन पर कितनों ने मकान नहीं बनवाये ?

(३) कितने व्यक्तियों ने जमीन के पैसे बोर्ड में जमा नहीं कराये ?

(४) हाउसिंग सहकारी समितियों ने बोर्ड से कितनी जमीन मांगी और उनको कितनी अलॉट की गई ?

(५) क्या इन्हें प्राथमिकता दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के भूमि अलॉटमेन्ट के अधिकार ता० १७-२-५९ से रोक रखे हैं।

(२) उत्तर (१) के अनुसार प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

(श्री सम्पतराम)

(३) उत्तर (२) के अनुसार।

(४) निम्न लिखित हाउसिंग सोसाइटियों ने अब तक भूमि के लिए प्रार्थना-पत्र दिये हैं :—

१. शिवा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी।

२. रेल्वे विभाग हाउसिंग सोसाइटी।

३. पथिक कालोनी गृह निर्माण समिति।

४. नल-बिजली कर्मचारी हाउसिंग कॉलोनी।

५. महालेखापाल भवन निर्माण सहकारी समिति।

इनमें से किसी को भी भूमि नहीं दी गई है।

(५) उत्तर (४) के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ० चन्द्रकला : अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड की सिफारिशों पर प्लॉट्स के अलॉटमेंट क्या निश्चित अवधि में किये गये हैं ?

श्री सम्पतराम : कुछ का किया है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या उन पर मकान बन गये हैं ?

श्री सम्पतराम : यह मैंने जानकारी नहीं की।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु.): जब मकान नहीं बने तो ऐसा नियम है कि दो साल में प्लॉट्स पर कोई मकान नहीं बनायें तो वापिस प्लॉट्स जब्त कर लिये जाते हैं, तो क्या ये भी जब्त हो जावेंगे ?

श्री सम्पतराम : यह तो पट्टे की शर्त पर निर्भर करता है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : जब सरकार ने इसको रोक रखा था तो फिर सिफारिश का सवाल अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के सामने कैसे आया ?

श्री सम्पतराम : स्कीम तो उसी की थी। एक ओवर ऑल यूनिफॉर्म पोलिसी तय करने का मामला था इसलिए सबको ही रोका गया था।

श्री भैरोंसिंह : ३० अक्टूबर, '५६ के बाद ऐसे आवेदन-पत्र सरकार के पास आये हैं कि जिन पर अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड की रिकमन्डेशन्स थीं ?

श्री सम्पतराम : कुछ आदमियों को प्लॉट्स दिये गये थे जो कि निम्न श्रेणी के हैं।

श्री भैरोंसिंह : ३० अक्टूबर, ५६ के बाद दरख्वास्तें आई थीं....

श्री सम्पतराम : तारीख के बारे में नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : लैंड के अलॉटमेन्ट के

(श्री भैरोंसिंह)

जो रूल्स हैं उनके अनुसार लैंड का अलॉटमेंट किया जाता है, तो क्या उन दर्ख्वास्तों को डिस्पोज़ ऑफ करते समय उनका भी ध्यान रखा गया था ?

श्री सम्पतराम : अलॉटमेंट कायदे कानून के अनुसार ही किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि राजस्थान लैंड अलॉटमेंट के जो रूल्स बने हुए हैं, प्रायोरिटी के बेसिस पर प्रार्थना पत्र डिस्पोज़ ऑफ किये जाते हैं तो उन रूल्स को देते समय ध्यान में रखा गया था या नहीं ?

श्री सम्पतराम : प्रायोरिटी का सवाल दूसरा है। फिक्स्ड प्राइस पर देने का सवाल है वह दूसरा है। खाली प्लॉट्स पड़े हुए हों तो दे सकते हैं। माननीय सदस्य जिसके बारे में संकेत कर रहे हैं मैं उसके बारे में डेफिनिट नहीं हूं।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.): हरिजनों को प्लॉट्स मिल गये तो फिर उनको हटाने की क्यों कार्यवाही हो रही है ?

श्री सम्पराम : यदि इस प्रकार की एक भी घटना मेरे ध्यान में लावेंगे तो मैं उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री हरिप्रसाद यादव : हसनपुरा, पी. डब्ल्यू. डी. के पीछे जो बस्ती है उसको दिया। आपके विभाग द्वारा भेदभाव बरता जाता है और जातिवाद के आधार पर प्लॉट्स दिये जाते हैं।

श्री सम्पतराम : जातिवाद के आधार पर कतई जमीन नहीं दी जाती है। अलॉटमेंट के रूल्स बने हुए हैं और उनके अनुसार ही जमीन दी जाती है। जहां हटने का सवाल पैदा होता है वह इस कारण पैदा होता है कि व्यवस्थित बसाना चाहते हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : तो क्या यह माना जाय कि हरिजनों को नहीं हटाया जायेगा ?

श्री सम्पतराम : यह स्वतन्त्रता से मान कर चलना चाहिये। किसी हरिजन को नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसके इन्ट्रेस्ट में ही दूसरी जमीन उसको अलॉट न कर दी जाय।

डॉ० चन्द्रकला : जमीन से बेदखल करने का सवाल नहीं है, जितनी जमीन नगरपालिका देती है तो हरिजनों के लिए क्या हो ?

श्री सम्पतराम : ४० वर्षों से बैठे हुए हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाती है, उनका पहले क्लेम होता है।

श्री हरिप्रसाद यादव : हरिजनों का जिन जमीनों पर कब्जा है, पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आये हैं। आपके विभाग के तिवारीजी को उनके कच्चे मकान अच्छे नहीं लगते। उन लोगों पर जोर डाला जा रहा है, यह अच्छी परम्परा नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हरिजनों को उन जमीनों से न हटाया जाय। अस्पृश्यता का कानून पास किया गया था, उसके बावजूद भी मन्त्री महोदय के डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी भेदभाव बरतते हैं, मकान नहीं बनाते उनके लिए,

(श्री हरिप्रसाद यादव)

उन्हें ज़मीनों से हटाया जाता है। इसलिए मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अधिकारियों को वे खास तौर पर हिदायत दे दें कि हरिजनों के साथ कोई भेदभाव न बरता जाय।

श्री सम्पतराम : भेदभाव की भावना जहां कहीं हो तो उसको दूर करने में माननीय सदस्य को भी प्रयत्न करना चाहिये। जहां तक अलॉटमेन्ट का सवाल है, अमीरी और गरीबी का ही भेदभाव होता है, जाति विशेष का नहीं। किसी गरीब आदमी को बेदखल नहीं किया जा रहा है।

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या यह सत्य है कि उन लोगों से पैसा वसूल नहीं किया, वह कब तक कर लेंगे ?

श्री सम्पतराम : सवाल पैदा नहीं होता। माननीय सदस्य ने सवाल को ही नहीं पढ़ा मालूम होता है।

प्रश्न संख्या ६७१

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री लादूराम सुलाणिया : आपने कीमत से दिया है या मुफ्त दिया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा।

रूपनगढ़ तहसील के ग्रामों में पानी का अभाव

६७५. **श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि रूपनगढ़ तहसील के कई गांवों में सिंचाई व पानी पीने के कुओं में पानी की काफी कमी आ गई है और इससे इन ग्रामों के निवासी काफी परेशान है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि ऊटड़ा बांध बंध जाने से जो पानी रूपनगढ़ तहसील की नदी की तरफ बह कर जाता था वह रुक जाने से और जो सेजा का पानी इन ग्रामों के कुओं को मिलता था वह मिलना बन्द हो गया है ?

(ग) अगर हां, तो सरकार ने अब इन ग्रामों को राहत पहुंचाने के लिये क्या उपाय सोचे हैं ?

पृथक राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। गांवों में पानी की कमी बरसात की कमी के कारण हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा : यह बिल्कुल गलत है, आप जांच करवाइये। यह बांध बंधने से पानी की कमी आई है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : बांध से नीचे नाले से

(श्री रामचन्द्र)

खेतों में और पीने के लिये पानी गांवों में जाता है।

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा : बिल्कुल गलत है। वहां पानी है ही नहीं। पानी का इन्तजाम करिये।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

डॉ. चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिये।

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत राज्य में खोली जाने वाली रेल्वे लाइनें

६७७. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) [डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल, बाज़ार जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी नई रेल्वे लाइन खोलने की सिफारिश भारत सरकार को की गई है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है ? जो लाइन्स खोलने की सिफारिश की गई है, कृपया उसकी तालिका सदन की मेज पर रखें।

पृथक राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : निम्नलिखित रेल्वे लाइनें खोलने की सिफारिश तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार को की गई जिस पर भारत सरकार द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है:—

१. हनुमानगढ़ भटिन्डा लाइन को बड़ी लाइन में परिणत करना।

२. सवाईमाधोपुर, सांभर, जयपुर होकर बड़ी लाइन में परिणत करना।

३. रतलाम, डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा और गलियाकोट।

४. टोडारायसिंह, देवली, बूंदी, कोटा।

५. चित्तौड़गढ़ से कोटा।

६. श्री मथुरा से गंगापुर वाया करौली।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री रावतमल पारीक।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

(१२. २ म० प०)

स्थगन-प्रस्ताव

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Sir, I had given an adjournment motion yesterday.

श्री अध्यक्ष : It will be considered in due course and you will be intimated the decision.

विधायी–कार्य

राजस्थान विद्युत् मण्डल का १९६१–६२ का वित्तीय विवरण (आय–व्ययक)

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण आयव्ययक, १९६१–६२ जो दिनांक २९–३–१९६१ को सदन की मेज पर रख दिये गये थे, विचारार्थ लिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड का बजट है और जो इसकी बहस माननीय सदस्य करेंगे इसके पहले मैं यह चाहता हूँ कि सदन को यह जान–कारी कराऊं कि हमारी दूसरी योजना के क्या क्या अचीवमेंट्स हुए हैं और तीसरी योजना के हमारे क्या लक्ष्य हैं ।

राजस्थान जब से बना, उस वक्त से जहां तक विद्युत का सवाल था, राजस्थान में विद्युत किलोवाट बहुत कम था और टोटल १३,२७१ किलोवाट पॉवर राजस्थान के पास थी । उसमें से फर्म पॉवर ७,४८३ किलोवाट की थी । माननीय सदस्य इससे समझ सकते हैं कि इतना कम पॉवर अवेलेबेल होने पर राजस्थान की तरक्की असम्भव थी ।

पहली योजना और दूसरी योजना में इस बात का पूरा प्रयत्न किया गया कि राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा बिजली मिल सके क्योंकि इस बात को सरकार मान कर चलती है कि अगर राजस्थान में विद्युत की कमी हुई या विद्युत पर्याप्त रूप में नहीं मिल सकी तो राजस्थान तरक्की के मार्ग पर नहीं चल सकता । लेकिन इस बात को देख कर, मैं समझता हूँ, माननीय सदस्य भी खुश होंगे कि जो काम दूसरी योजना में राजस्थान विद्युत मण्डल ने किया है उसके लिए वह बधाई का पात्र है । सरकार की पॉलिसी है कि देश में समाजवादी समाज की स्थापना की जावे । मैं इस बात को मान कर चलता हूँ कि इस स्थापना का मीडियम पॉवर हो सकता है और वह इस वास्ते हो सकता है कि जब तक देश में देश का एग्रीकल्चर और इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ता नहीं, उसका इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन नहीं होगा, तब तक सोश्यलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी हिन्दुस्तान में नहीं आ सकती है । तो मैं यह माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहूँगा कि जितनी तरक्की विद्युत में होगी उसी प्रमाण से हम हमारे जो कार्य हैं सोश्यलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी स्थापित करने के हिन्दुस्तान में उनको उसी तेज रफ्तार से हम चला सकेंगे ।

पहली योजना में राजस्थान में ३४,९०० किलोवाट पॉवर ऐड की । इसमें से १५,३९९ किलोवाट पॉवर फर्म अवेलेबल थी राजस्थान के पास ।

दूसरी योजना में आकर आखिर में इस बात को देख कर, मुझे भी खुशी है,कि हमारी टोटल इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी १,०८,९९२ किलोवाट दूसरी योजना के अन्त तक हो जावेगी और हो गई है । इसकी ६४,८३० किलोवाट फर्म कैपेसिटी राजस्थान को प्राप्त

(श्री हरिश्चन्द्र)

होगी । राजस्थान के फोर्मेशन के वक्त, क्योंकि पॉवर की कमी थी इसलिये देहातों में और दूसरी जगह भी ट्रान्समिशन लाइन की कमी थी । टोटल माइलेज ऑफ ट्रान्समिशन लाइन सिर्फ २०० मील लम्बी थी । आज जब कि दूसरी योजना खत्म हुई उस वक्त हमारे सामने १,२११ मील लम्बी हाई टेन्शन और लोकल डिस्ट्रिब्यूशन लाइन अवेलेबल है । दूसरी योजना के टार्गेट जो माननीय सदस्यों ने देखे होंगे बजट के समय, टोटल एलोकेशन १,६६६.५१ लैक्स था । इसका ब्रैक अप विभिन्न मदों में इस तरह से है : कामन–पूल व भाखरा ३३२.२२ यह तो एलोकेटेड था, इसके अगेन्स्ट, जो ६०–६१ तक ही हुआ है, ३३८.४३ लाख रुपया खर्च हुआ । पृथक सप्लाई १३८.७८ इसके अगेन्स्ट में १३६.५४ लोकल डिस्ट्रिब्यूशन भाखरा का ११४ अगेन्स्ट १०४.६५ ।

चम्बल कॉमन–पूल–वर्क २३३ अगेन्स्ट २३३ लैक्स । ट्रान्समिशन लाइन ४२० इसके अगेन्स्ट ४४०.७८ ।

राणा प्रतापसागर का २५० अगेन्स्ट ५ । अब मुझ से पूछेंगे कि जब २५० का एलोकेशन था तो इसमें से राणा प्रतापसागर में पांच ही क्यों खर्च हुआ ? इसके लिये निवेदन करना है कि इसको स्वीकृति सी० डब्ल्यू० पी० सी० से देर से आई इसलिये यह खर्चा सिर्फ पांच लाख ही हो पाया ।

थर्मल स्टेशन में टोटल एलोकेशन रूरल अर्बन इलेक्ट्रिफिकेशन का २१६ अगेन्स्ट ३५७.३८, रूरल एण्ड अर्बन इलेक्ट्रिफिकेशन ८० लैक्स का अगेन्स्ट ७२.६४; अदर स्कीम्स का २०५.५१ के अगेन्स्ट ४३.४४ ।

माननीय सदस्य यह फिर पूछेंगे कि यह इतनी कमी क्यों ? इसमें बहुत सारा पैसा अजमेर पॉवर हाउस का लेने का था और अजमेर पॉवर हाउस की क्योंकि अपील सुप्रीम कोर्ट के पास पेन्डिंग है इसलिए एक्वीज़ीशन का जो पैसा था वह खर्च नहीं हो सका । प्रो–रेटो ओवरहैड चार्जेज़ १२.७३, यों करके टोटल आयेगा अगेन्स्ट दी एलोकेशन ऑफ १,६६६.५१ और १,७४६.५६ । ये तो मैंने फाइनेन्शियल टार्गेट्स बताये । लेकिन जहां तक फिज़िकल टार्गेट्स का सवाल है सेकण्ड फाइव इयर प्लान में एचीवमेंट्स हैं वे इस तरह हैं। चम्बल का जो टार्गेट था ३,४३,००० किलोवाट का वह पूरा का पूरा एचीव कर लिया है । भाखरा से १६,४३७ किलोवाट बिजली आनी चाहिए उसके अगेन्स्ट ४,६०० किलोवाट अभी तक आई है । बाकी जो बचती है वह इस साल के आखिर तक हमें मिल जायेगी । थर्मल में जो स्कीम का लक्ष्य था वह २२,००० किलोवाट का था और डीज़ल का ६,००० का लक्ष्य था । इस तरह २८,००० किलोवाट स्टीम डीजल के टार्गेट्स थे । उसके बदले हमने ३३,३८३ किलोवाट कुल पॉवर जेनरेट की है । तो यों इसमें अगर आप हमारी इन्सटाल्ड कैपेसिटी जो एग्ज़िस्टिंग सोर्सेज़ की है उसको मिला कर २४,६७२ किलोवाट और जोड़ दें जो कि एग्ज़िस्टिंग है, फर्स्ट फाइव इयर प्लान की है, यों मिला कर १,०८,६६२ किलोवाट टोटल इन्सटाल्ड कैपेसिटी सेकिण्ड फाइव इयर प्लान के आखिर तक राजस्थान में प्राप्त हुई है ।

अब माननीय सदस्यों के सामने मैं ब्रीफ

(श्री हरिश्चन्द्र)

में तीसरी पंचवर्षीय योजना की थोड़ी चर्चा करूंगा। तीसरी योजना के लिए राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने राजस्थान सरकार से ४५ करोड़ की मांग की थी। लेकिन ओवर ऑल सीलिंग को देखते हुए और राजस्थान सरकार के और अन्य कामों को देखते हुए यह मुनासिब समझा कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सीलिंग जो कि राजस्थान सरकार ने फिक्स की है। वह ३५ करोड़ रुपये की होनी चाहिए। अब ३५ करोड़ रुपये का ब्रेक–अप में आपके सामने पेश करना चाहूँगा। भाखरा में जो हमारी टोटल कैपेसिटी किलोवाट में जेनरेट होगी थर्ड फाइव ईयर प्लान में वह ५३,००० किलोवाट होगी और इसका टोटल फाइनेन्शियल आउट–ले होगा ७९३ लाख रुपये का। चम्बल में जो फोर्थ यूनिट ऑफ गांधीसागर इन्स्टाल होगा वह २३,००० किलोवाट का और राणाप्रताप सागर डेम और कोटा डैम, इन दोनों को मिलाकर राणाप्रताप सागर से ६४,००० और कोटा डैम से ३६,००० किलोवाट बिजली पैदा होगी और टोटल फाइनेन्शियल आउट–ले ५६२.२४ लाख रुपये होगा। जो ५३,००० किलोवाट बिजली भाखरा से राजस्थान को मिलेगी उसमें २५,००० किलोवाट तो फर्टीलाइज़र फैक्टरी राजस्थान को एलॉकेट हुई है, उसके लिए दी जायेगी और २८,००० हमारे दूसरे कामों के लिए मिलेगी। इसके अलावा ७९३ लाख रुपये का जो फाइनेन्शियल आउट–ले बनाया इसके अन्दर जो राजस्थान और पंजाब के जोइन्ट वेन्चर हैं, व्यास और स्तलज का, जो कि अब स्वीकार हो गया है उसके १ या १। करोड़ रुपये भी इसमें शामिल हैं। थर्मल स्टेशन्स के लिए सी० डब्ल्यू० पी० सी० ने और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने इस बात को माना है कि राजस्थान में क्योंकि विद्युत की कमी है इस वास्ते भाखरा एरिया में ५०,००० किलोवाट का थर्मल स्टीम टर्बाइन और लगाया जाये तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इसके साथ ही साथ चम्बल सर्विसेज़ एरिया में ३०,००० किलोवाट का एक थर्मल स्टेशन और लगाया जायेगा। हमें इस बात की सूचना मिली है कि सी० डब्ल्यू० पी० सी० ने इस बात को भी माना है कि यह ३०,००० किलोवाट का थर्मल स्टेशन है इसको ५०,००० का कर लिया जाये। तो भाखरा और चम्बल दोनों एरिया में मिला कर कम से कम लाख किलोवाट का थर्मल यूनिट मिलता है। इसी तरह से जोधपुर में, क्योंकि पॉवर की कमी महसूस होने लगेगी साल, ड़ेढ़ साल में, लिहाज़ा थर्ड फाइव इयर प्लान में ३,००० किलोवाट का एक स्टीम टर्बाइन और लगेगा और उसके लिए ऑर्डर भी प्लेस कर दिया गया है। आशा है कि जल्दी से जल्दी उसका काम भी शुरू हो जायेगा। डीज़ल सैट के लिए १०,००० किलोवाट टोटल पॉवर रखी है। जिस तरह भी लोड डेवलप होता जायेगा और बोर्ड जो जो जगह डिटर्मिन करेगा इन कन्सलटेशन विथ दी गवर्नमेंट सैट लगेंगे। थर्मल स्टेशन का टोटल आउट–ले ६६५ लाख रुपये का होगा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इन्क्लुडिंग अजमेर वर्क्स ऑफ दी सेकण्ड प्लान। इसके लिए १११.३२ लाख रुपये रखे गये हैं सेकण्ड फाईव ईयर प्लान के अन्दर जिसमें से ११.३२ लाख सेकण्ड फाइव इयर प्लान में अजमेर वर्क्स के थे। लेकिन क्योंकि अजमेर पॉवर हाउस को

(श्री हरिश्चन्द्र)

एक्वायर नहीं कर सके इसलिए यह पैसा खर्च नहीं हुआ जो अब तीसरी योजना में खर्च होगा जो वहां की डिस्ट्रिब्यूशन लाइन है उसमें। अब ट्रान्समीशन एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन लाइन का लम्पसम रखा है ६६८.४४ लाख रुपये और इसकी जो तफसील है वह इस प्रकार है। चम्बल १३२ के० वी० लाइन राणाप्रताप सागर भीलवाड़ा सवाई-माधोपुर-जयपुर सेकण्ड सर्किट लाइन। एक सर्किट तो खिंच रहा है और यह दूसरा सर्किट है भीलवाड़ा-अजमेर, भीलवाड़ा-उदयपुर, झालावाड़ जोधपुर और जयपुर-भरतपुर वाया राजगढ़। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में १३२ के० वी० लाइन इरेक्ट होगी। इसके साथ ही साथ ६६ के० वी० लाइन की तफसील इस प्रकार है। पाली-फालना, राजगढ़-अलवर, नीमच चित्तौड़-झालावाड़-कोटा, झालावाड़ और भाखरा में जो लाइन है वह हनुमानगढ़ और खेतड़ी की है। क्योंकि खेतड़ी में जैसा माननीय सदस्यों को मालूम है कॉपर स्मेल्टिंग प्लान्ट चलाने के लिए पॉवर की जरूरत पड़ेगी; तो खेतड़ी की लाइन के लिए भी हमें इसी में से पैसे को लगाना पड़ेगा। मिसलेनियस स्कीम ७० लाख की रखी गई है। इसके अन्दर establishment of laboratories, survey and investigation, acquisition of private owned power houses etc. यह ७० लाख में इन्क्लुडेड है। Total capacity power available at the end of third Five Year plan जो राजस्थान को प्राप्त होगी वह होगी २,७७,६३७ के० वी०। यह लक्ष्य रख कर हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना को बनाया है और मैं आशा करता हूं कि हम लोग इसमें सफल होंगे।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष, यह बड़े हर्ष की बात है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दिन हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वाद-विवाद कर रहे हैं........

कई माननीय सदस्य : फर्स्ट अप्रेल तो नहीं बना रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : (अश्रव्य)।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, और यदि इन बजट एस्टीमेट्स वगैरह को देखें और सन् १६५७ के अन्दर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कायम हुआ उसके बाद में जो इसकी गतिविधि रही है उसको देखें तो बड़ी ही आशा और विश्वास उत्पन्न होना चाहिए पब्लिक सेक्टर की कार्यक्षमता के ऊपर और उसके मैनेजमेंट के ऊपर। उसके साथ ही जो लोकल टेलेन्ट्स हैं जिन्होंने कि वर्क किया है, वह भी बहुत ही प्रशंसनीय है।

माननीय अध्यक्ष, यद्यपि माननीय मन्त्री महोदय ने काफी फीगर्स दे दिये हैं उनको वापिस नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन यह बात जरूर है कि अगर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो टार्गेट्स हैं, फाइनेन्सयली भी उनका मिलान करें तो विदित होगा कि बहुत ही अन्तर है। पहला प्लान जो था उसमें ६५८.२३ लाख रु० रखा था और खर्च १२३.४५ लाख हुआ था। हम कुल १२ परसेन्ट खर्च कर सके थे फाइनेन्शि-

Page No 36

(श्री सोहनलाल भटनागर)

यल टार्गेट्स का। लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जब उसकी समाप्ति हुई तो १९९.३५ में से ४.५० लाख ज्यादा खर्च किये हैं, यानी कुल ८० पर्सेन्ट फाइनेन्शियल टार्गेट्स एचीव किये हैं। इसी तरह से फिजीकल टार्गेट्स का जहां तक स्वाल है पहली से दूसरी में हमने काफी एक्सीड किया है। मैं उनके फीगर्स नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी माननीय मन्त्री महोदय ने बताये हैं। भाखरा से ४,६०० किलोवाट और चम्बल से २०,००० किलोवाट प्राप्त की है।

अब जब किसी ओर्गनाइजेशन या बोडी की पोज़ीशन देखते हैं तो सबसे पहले उसकी फाइनेन्शियल पोजीशन के ऊपर विचार करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष, अगर हम इसकी फाइनेन्शियल पोज़ीशन पर विचार करें तो सदन में सभी माननीय सदस्यों को भली प्रकार से विदित है कि उसके फाइनेन्स की क्या हालत थी और आज क्या हालत है ? जैसा कि स्पष्ट है कि सन् १९५८ में १८.५८ लाख का घाटा था और आज बजट एस्टीमेट में है उससे ऐसा मालूम होता है कि यह बड़ा आशाप्रद है। घाटे के आधार से हट कर बराबर और कम से कम २.५१ लाख का इसमें एक्सेस बताया गया है............

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : पॉवर कितनी हुई ?

श्री सोहनलाल भटनागर : इसका भी मैं अभी बताता हूं।

इसी तरह से, माननीय अध्यक्ष, जो रनिंग एक्सपेन्सेज़ थे, १,९६,४७,०००) रु० थे और उसका रिवाइज्ड एस्टीमेट १,९९,००,०००) हुए। अब जब कि किसी चीज के बजट को हम देखें तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में देखना है कि यह जो रनिंग एक्स-पेन्डीचर है इसमें कमी की जाय। जो सरप्लस मिलता है वह रहे। रेवेन्यू से एक्सपेन्डीचर को डिडक्ट करने के बाद जो सरप्लस मिलता है वह मिल सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब हमको हाइडल पॉवर मिलती है, नये एन्जिन लगा रखे हैं तो रनिंग एक्सपेन्डीचर इतने नहीं बढ़ने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इसके बारे में कोशिश करनी चाहिए कि रनिंग एक्सपेन्डीचर जो है वह कम हो।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष, इसके बारे में एक बात और निवेदन करनी पड़ेगी। वह यह है कि जो एवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं और जो युटिलाइजेशन है उसके बीच में कोई लेग नहीं रखें। जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि चम्बल से हमको २०,००० किलोवाट एवेलेबल रिसोर्सेज हैं लेकिन केवल २,००० किलोवाट युटिलाइज कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रि-सिटी बोर्ड ने काफी प्रयत्न किया है, काफी सामान वगैरह प्राप्त करने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे कारण हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो फाइनेन्शियल पोज़ी-शन है वह काफी ठीक हो सकती है यदि लेग बिटवीन एवेलेबल रिसोर्सेज़ और युटिलाइ-जेशन का नहीं रहे।

माननीय अध्यक्ष, इसके युटिलाइजेशन में और एवेलेबल रिसोर्सेज़ में लेग रहने का

(श्री सोहनलाल भटनागर)

सबसे बड़ा कारण है वह मेरे ख्याल से ट्रान्स-मिशन लाइन है, उसको पूरी तरह से नहीं बनाने का है। इस दृष्टिकोण से हमें सोचना है। और भविष्य में बजट में स्पष्ट रखें कि ट्रान्समिशन लाइन वगैरह के लिए पूरा प्रोविजन करें। इस तरह से इसके अन्दर २.७९ करोड़ चम्बल वगैरह ट्रान्समिशन लाइन का रखा गया है वह कम पड़ेगा। जो एवेलेबल रिसोर्सेज़ है उसको युटि-लाइज़ नहीं कर सकेंगे।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, इससे जो संबंध रखने वाली चीज है वह रेट्स के बारे में है। इसके बारे में हमने एक प्रश्न भी पूछा था और यह सही है कि हाइडल पॉवर आने के बाद आज जनता की भावना यह थी कि जो रेट्स हैं वे कम होंगी, लेकिन जहां तक इन्डस्ट्रीज़ का सवाल है उसमें काफी कन्सेशन दिये हैं, उनके डिटेल्स में जाना नहीं चाहता लेकिन इसके साथ ही जो दूसरे रेट्स हैं, चंबल के रेट्स मुकर्रर नहीं हुए हैं हमारे यहां, लेकिन कल या परसों के अखबार में मैंने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश में चम्बल के रेट्स मुकर्रर कर दिये हैं और ऑर्डिनरी कयूज्मर जो है उसके लिए १८ नये पैसे रखे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे यहां भाखरा नांगल के रेट्स हैं तो भाखरा के रेट्स मुकर्रर कर दिये गये हैं और चम्बल के भी जल्दी ही मुकर्रर किये जायेंगे। आम जनता में हमने यह कहा था कि हम क्रान्ति ला रहे हैं, हम सस्ती बिजली प्रदान करेंगे, यह नारा दिया था। मैं आशा करता हूं कि इस नारे को सरकार कामयाब करेगी और सस्ती बिजली आम जनता को जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेगी।

दूसरी, बात माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ताल्लुक रखती है वह यह है कि रेट्स के अन्दर, भाखरा के अन्दर जो हमारा शेयर था और भाखरा का जो प्रॉजेक्ट बना था उसके बाद में दिल्ली को पोवर कुछ दिया है। पंजाब और राजस्थान का कुछ हिस्सा दिल्ली को दिया गया है। माननीय अध्यक्ष, दिल्ली एक दूसरा प्रदेश है जो कि इस प्रोजेक्ट के अन्दर साथ नहीं था, उसको हम सस्ती बिजली दे रहे हैं हमारा नुकसान करके। इसके बनिस्बत यहां की जनता को, जिस राज्य ने पैसा खर्च किया है वहां की जनता को सस्ती बिजली नहीं मिल रही है। इसके बारे में भी आप प्रयत्न करेंगे।

तीसरी बात, माननीय अध्यक्ष, जो इससे ताल्लुक रखती है वह सबवेन्शन बाइ दी इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट। इसमें सबवेन्शन के लिए लिखा है। सस्ती बिजली बड़े, लघु और मीडियम कारखाने जो हैं उनको दी जाती है उसके बारे में इस बजट में बताया गया है कि सरकार द्वारा सबवेन्शन किया जाता है। कम रेट है। कितनी रकम दी जाती है, मेरे खयाल से नहीं बताया गया है। माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमको इन्डस्ट्री का विकास करना है, वह हमारे प्रोजेक्ट के हिस्से में है, लेकिन इसके साथ वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सबवेन्शन की रेट माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सब-वेन्शन की रेट अच्छी होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर ज्यादा भार नहीं पड़े।

एक बात इसके साथ और जुड़ी हुई है

Page No 38

(श्री मोहनलाल भटनागर)

वह है प्राइवेट पॉवर हाउस की । आज कई जगह नये पॉवर हाउस या हाइडल पॉवर को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ में प्राइवेट पॉवर हाउसेज़ हैं वे भी लगे हुए हैं । इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए कि जिस जगह नई बिजली दी जाती है उसके बाद में प्राइवेट पॉवर हाउस की क्या स्थिति रहेगी ? वह समाप्त होगा या पब्लिक सेक्टर के अन्दर जो बिजली दे रहे हैं उसी का लाभ पहुँचेगा और पुराने भी दोनों चलते रहेंगे ? दोनों का इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें कामयाबी नहीं मिल सकेगी ।

इसके साथ थोड़ा सा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन और करना चाहूंगा, वह यह है कि यदि हम अपने प्रदेश का दूसरे देश के प्रदेशों के साथ मिलान करेंगे तो विदित होगा कि हमारा पर–कैपिटा कन्जम्शन कम है । जहां राजस्थान के अन्दर पर कैपिटा ४.६२ किलोवाट का कन्जम्पशन है उसके बनिस्बत दूसरे प्रदेशों का कन्जम्पशन काफी ऊंचा है । हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिसिटी की योजना और खास-तौर से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में प्रयत्न करना चाहिए । माननीय अध्यक्ष, यह बिल्कुल खुशी की बात है कि पहले राजस्थान के निर्माण के वक्त केवल ४२ जगह बिजली थी और उसके बाद फर्स्ट प्लान के आखीर में केवल ६६ जगह थी और आज १२१ जगह है । तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ५५० नई जगहों पर की जा रही है । लेकिन इसके साथ ही दूसरे प्रदेशों में जितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है रूरल और अरबन का, तो आप देखेंगे कि वह इस तरह की बात में बड़े आगे बढ़े हुए हैं । आज पंजाब में अभी अभी ६०० नई जगहों पर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है । तो हमारी स्पीड जो है वह कम है । इस दृष्टिकोण से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी जो इलेक्ट्रिफिकेशन, खास तौर से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की जो स्पीड है उसको एक्सीलरेट करना चाहिए ।

एक बात और मैं जोड़ दूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। वह यह है कि हम देखते हैं, बजट के डिटेल्स वगैरह में हम जाते हैं तो जहां पर थरमल, डिज़ल पॉवर पहले से मौजूद हैं उन्हीं जगह पर हाइडल पॉवर भी दे रहे हैं । हाइडल पॉवर के आने के बाद भी हम डिज़ल और थरमल पॉवर पर काफी खर्चा कर रहे हैं । इस दृष्टि से ऐसा प्लानिंग करना चाहिये कि हमारा डबल एक्सपेन्डिचर न हो, बोर्ड को और भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके ।

आखिर में, माननीय अध्यक्ष, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा कि जब हमारा थर्ड फाइव इयर प्लान बना था तब इलेक्ट्रिसिटी का प्लान काफी एम्बिशियस था लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसको काफी कर्टेल कर दिया गया है । उसमें सबसे ज्यादा कटौती डिस्ट्रिब्यूशन में हुई है । पहले इसमें २५ करोड़ रखे थे, लेकिन अब १० करोड़ ही रखे हैं । तो यह रकम काफी कम होगी । जब रिसोर्सेज़ बढ़े हैं तो डिस्ट्रिब्यूशन का खर्चा कम करना वाजिब नहीं होगा । इस दृष्टिकोण से सरकार सोचेगी और

(श्री सोहनलाल भटनागर)

डिस्ट्रिब्यूशन और ट्रान्समिशन में अधिक से अधिक रकम रखी जायेगी।

आज इलेक्ट्रिसिटी की स्थिति बढ़ रही है। अब लोस के बनिस्बत प्रोफिट की ओर जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि जिस सिद्धान्त से पब्लिक सेक्टर में बोर्ड बनाया गया उसके अनुसार सरप्लस रेवेन्यू राज्य के विकास और जनता की बढ़ोतरी के लिये काम आवे। मैं आशा करता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी व सारा बोर्ड इस दृष्टि से काम करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और कम से कम खर्चा हो।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो आय व्ययक है और उसका जो अंकन किया गया है, उसमें जो फीगर्स दिये गये हैं उनको देखने से यह कहना पड़ता है कि वह बहुत ही उत्साहवर्धक है। लेकिन एक कहावत है:

"The taste of pudding lies in its eating."

इसके अनुसार हमको देखना यह होगा कि आया यह जो कुछ खर्चा हुआ, जो कुछ फिगर्स दिये गये उनके अनुसार बिजली या विद्युत ने हमारे प्रान्त में कितनी प्रगति की।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि हो सकता है आपने शहरों में बिजली पहुंचा दी, शहरों में कई स्टेशन्स लगा दिये, चकाचौंध होने लगी, लोगों को रोशनी मिल गई, लोगों को पंखे मिल गये, लेकिन सवाल यह है और यह देखना है कि इस सब प्रगति से हमारी उपज की प्रगति कितनी हुई, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहां जहां तक एग्रीकल्चर का सवाल है, खेती का संबंध है, बिजली या विद्युत का प्रयोग उसमें नहीं के बराबर है। राजस्थान के किसी भी भाग में यह कहा जाय कि आम तौर से बिजली मिल रही है या खेती के काम के लिये बिजली दी जा रही है तो मैं निवेदन करूंगा कि यह गलत होगा। वास्तव में किसी भी प्रान्त की या किसी भी देश को उन्नति निर्भर है उसकी उपज पर और उपज निर्भर है हमारे यहां इस पर कि शक्ति का सही प्रयोग करें। यदि शक्ति को अपने भोगविलास के काम में लेते हैं, रोशनी, पंखों और थर्मस के लिये काम में लेते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि यह शक्ति का सही उपयोग नहीं है....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इससे काम करने की शक्ति बढ़ती है।

श्री रघुवीरसिंह : काम करने की शक्ति तब बढ़ती है जब उपज में लगे। उपज राजस्थान में नहीं के बराबर है। मैंने हाल ही में कई प्रान्तों में देखा, जिस स्टेशन को भी देखा वहां पर बिजली से चकाचौंध थी, कहीं पर ट्यूब-वैल्स चल रहे थे, कहीं पम्पिंग सेट्स लगे थे और पानी इस तरह से बह रहा था जैसे बरसात का मौसम हो। इनके मुकाबले में राजस्थान को कम्पेअर करते हैं तो यह जान कर दुःख होता है कि साधारण खेती के लिये भी पानी का अभाव है। इसलिये निवेदन करता हूँ कि वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सराहना हो रही है तो किस चीज के

(श्रीं रघुवीरसिंह)

लिये ? गवर्नमेंट का डिपार्टमेन्ट उसको न रख कर इन्डिपेन्डेन्ट बोर्डी बनाने के दो ही मकसद हो सकते हैं, दो ही हल होने चाहिये थे, एक तो यह कि कॉमर्शियल बेसिस पर चलता, घाटा नहीं होता और लाभ अधिक होता व दूसरी ओर इसका अधिक से अधिक उपयोग होता और लोगों को सही और सस्ते दामों पर बिजली उपलब्ध होती ।

लेकिन आज भी हमारे यहां रेट्स बहुत ऊंची हैं । कहने को खेती के लिये मिलेगी लेकिन यदि यही रेट्स रहती हैं तो काश्तकार लोग बिजली लेंगे ही नहीं । इसलिये सबसे पहली बात यह है कि बिजली की रेट्स को रिवाइज़ किया जाय और ऐसी रेट कायम की जाय जो इकॉनोमिक हो ।

दूसरी बात यह है कि हमारा जो रूरल सेक्टर है उसमें या गांवों में बिजली किस प्रकार से पहुँच सकती है ? इस समय १५० स्टेशन्स पर या २०० स्टेशन्स पर बिजली पहुँचा दीजिये या नये स्टेशन्स बना दीजिये उनसे कोई लाभ उपज में नहीं होगा, जब तक कि बिजली गांवों में नहीं पहुँचेगी । मैं तो आज से नहीं, बहुत पहले से ऐसा सोचता आया हूँ कि यदि राजस्थान में अन्न की प्रोब्लम उपज की प्रोब्लम या अनएम्पलोयमेंट की प्रोब्लम हल हो सकती है तो वह एक ही तरीके से हो सकती है और वह है कि चीप इलेक्ट्रिसिटी मिले, चीप मोड ऑफ लिफ्टिंग वाटर हो, सिंचाई का साधन ठीक हो । इसके लिये हमने भाखरा-नांगल पर दृष्टि डाली है, चम्बल पर हमारी निगाह है । लेकिन इन दोनों के बावजूद देखना यह होगा कि राजस्थान का कितना हिस्सा ऐसा है जिसमें सिंचाई के साधनों की कमी के कारण पूरी उपज नहीं हो रही है ? सारे ईस्टर्न राजस्थान में सिंचाई का अभाव है और इस कारण से उपज गिर गई है ।

इसी प्रकार से साउथ और वेस्टर्न राजस्थान का भाग भी सिंचाई के साधनों के अभाव में पूरी उपज नहीं कर सकता । इसलिये मैं निवेदन करता हूँ कि बिजली की योजना इस प्रकार सेट की जाय कि जहां हमारा नहरी पानी नहीं आ सकता या नहरी पानी आने की संभावना नहीं है । उस इलाके में नेट वर्क ऑफ ट्यूब वैल्स और पंपिंग सेट्स कायम करें, वहां पर ऐसी सस्ती बिजली मिले कि सब लोग उसे सिंचाई के काम में ले सकें । यदि इसको सस्ता बना कर सिंचाई के लिये उपलब्ध नहीं कर सकेंगे तो जो कुछ प्रयास किया गया है उसमें असफल होंगे । कुए बन रहे हैं, उनके लिये तकावी दी जाती है, लेकिन तब ही काम कर सकते हैं जब कि बिजली उपलब्ध हो सस्ते भावों पर । पानी सींचने का सवाल आता है तो वह इतना महंगा होता है कि आज लोग कुओं को छोड़ कर बारानी पर जाते हैं। राजस्थान का ईस्टर्न और साउथ पोर्शन ऐसा है कि कुंए बहुत बने हुए हैं लेकिन बैल महंगे हैं, आदमी महंगे हैं, दूसरा सामान महंगा है, इसलिये कुओं से सिंचाई छोड़ कर बारानी पर खेती करते हैं । इसका फल यह होता है कि राज्य की उपज कम होती जा रही है । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि सारे राजस्थान में पॉवर एक्सटेन्ड करें और खास करके उस जगह दी जाय जहां कुएं हैं, उनमें पानी है और वह पानी उपरोक्त कारणों से काम में

(श्री रघुवीरसिंह)

नहीं आ रहा है। इन सब का सर्वे होना चाहिये। राजस्थान में कौनसा इलाका ऐसा है जिसमें पानी पर्याप्त है, लेकिन सिंचाई नहीं कर सकते, इस चीज़ का सर्वे हो जाने के बाद हमको यह तय करना होगा कि किस भाग में कितनी बिजली, विद्युत की आवश्यकता है और वहां पर विद्युत किस प्रकार से पहुँच सकती है। आज लोग इस बात के लिये तड़फ रहे हैं कि हम किसी प्रकार से पम्पिंग सेटस लगा सकें, सस्ता पानी निकालने का साधन बना सकें। वहां न तो पम्पिंग सेट्स कायम किये हैं और न ही बिजली पहुँचने की संभावना है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सफलता का माप-दंड यह होना चाहिये कि कितने इलाके को सर सब्ज बना दिया, बिजली पहुँचाकर पानी निकालने का साधन बना दिया और जो जगह रूखी-सूखी पड़ी थी उसको हरी-भरी भूमि में परिणत कर दिया।

खाली शहरों में चकाचौंध करना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के काम का कोई माप-दण्ड नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अब विचारणीय सवाल यह है कि हमारे यहां एक तरफ देखते हैं, मैं अलवर जिले के बारे में निवेदन करता हूं, अलवर जिले में एक तरफ पंजाब का बोर्डर लगता है। उस पंजाब बोर्डर में अलवर जिले से एक मील की दूरी पर भाखरा लाइन पास होती है और पंजाब में हर गांव में बिजली सप्लाई हो चुकी है, पम्पिंग सेट्स गांवों में काम कर रहे हैं और एक साल में तीन तीन फसले खेतों में होती हैं। उसके मुकाबले में एक मील इधर, जहां अलवर शुरू होता है, राजस्थान शुरू होता है, वहां देखते हैं कि बिजली का सर्वथा अभाव है। एक काश्तकार जो एक मील इधर का है, वह सोचता है—मैं हिन्दुस्तान में बसता हूँ या किसी दूसरे प्रदेश में बसता हूँ। जब यह देखता है कि पंजाब का काश्तकार बिजली का पूर्ण उपयोग कर रहा है, पूरी तरह से बिजली आई हुई है और उसके यहां ट्यूब वैल्स लगे हुए हैं, उसके यहां अन्य छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज़ काम करती हैं और बिजली का पूरा उपयोग कर रहा है। जब कि वह लाइन हमारे राजस्थान-अलवर के बोर्डर से पास होती है। यह नहीं कि लाइन बाहर से निकलती है, अलवर डिस्ट्रिक्ट के एक अंश में से होकर पास होती है, लेकिन वह उससे फायदा नहीं उठा सकते। आज राजस्थान के नागरिकों को बिजली नहीं मिल रही है। तो राजस्थान के उस इलाके के नागरिक को सोचना पड़ता है कि क्या कारण है, क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी कमजोर है या इतनी अकर्मण्य है कि पंजाब का नागरिक जितनी बिजली चाहता है वह उसको अवेलेबल है, वहां नहरें हैं, बिजली है और ट्यूब वैल्स हैं और उसके मुकाबले में जब इधर देखते हैं तो राजस्थान के नागरिक के लिए नहर का प्रश्न ही नहीं उठता, उसको बिजली भी सस्ते दामों पर नहीं मिलती है? तो यहां के काश्तकार को एक आघात पहुँचता है और वह विचार करता है कि क्या हमारी राजस्थान गवर्नमेंट इतनी इम्पोटेन्ट है कि पंजाब गवर्नमेंट सारी चीजों को हड़प कर जाय और राजस्थानवाले मुंह ताकते रह जायं, जब कि वह लाइन हमारे यहां से पास होती है। मैं निवेदन करूंगा कि हमको बहुत सीरियसली इस बात पर सोचना होगा कि

(श्री रघुवीरसिंह)

कितने दिनों में, कितनी जल्दी हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं, हमारे देहातों में हम बिजली कितनी जल्दी पहुँचा सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं । अगर वह कर सकते हैं तो मैं मानूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कुछ किया है, अन्यथा समझूंगा कि केवल शहरों में चकाचौंध है, जिसे एक तरह से कहना होगा कि भरे को भरना है, शहरी लोग पहले ही आराम में हैं, बिजली उनको दे दीजिये, पानी दे दीजिये, नल दे दीजिये और देहातों में फिर भी मरना ही रहा, न पानी मिलता है, न रोशनी मिलती है और न नल मिलता है ।

राजराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का १९६१–६२ का बजट सदन में विचारार्थ पेश है । अध्यक्ष महोदय, जब से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्थापित हुआ है और यह महकमा हमारे माननीय मन्त्रीजी के सुपुर्द हुआ है तब से तो हमको बड़ी बड़ी आशायें हो रही थीं कि हमारा जो यह महकमा है, प्रोपर डेज़िग्नेशन पर आया है। इसकी वजह से,जैसा अभी माननीय मन्त्रीजी ने फर्माया कि सोश्यलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के रूप में कार्य कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि आप पहले अपने शासन में सब के साथ समानता का बर्ताव करते थे और अब जब राजस्थान सरकार के इस पद पर होने पर, यह डिपार्टमेंट आपके पास आने पर हमने तो यह आशा लगाई थी कि आप ऐसा नहीं करेंगे । मगर आप जिस तरह समानता से और जिस एकता से बर्ताव किया करते थे वे बर्ताव नहीं करेंगे । यह कहावत है :

"काला बखे धोला बैठे तो रंग नहीं तो लखण तो ले ही" ।

अब आप यहां आकर बिराजे तो यह भावना हो गई, जैसी आज तेरह वर्ष से एक मेरे क्षेत्र के साथ भावना हो रही है । अध्यक्ष महोदय, दो जगह हैं, जहां से बिजली मिलेगी चाहे शहरों के लिए, चाहे गांवों के लिए, चाहे खेती के लिए, चाहे डोमेस्टिक यूज़ व पर्पजेज़ के लिए और वे हैं—या तो भाखरा या चम्बल । तो भाखरा की बिजली आना हमारे यहां मुश्किल है, चम्बल से हमारा सम्बन्ध है, चम्बल से आने की उम्मीद है । तो मेरा जो क्षेत्र है वह ऐसी जगह है, इधर टोंक, इधर बून्दी, इधर कोटा, इनके बीच में है । हमको जो किताब दी गई इसको देखने से साबित होता है कि यह जो चम्बल की बिजली आती है उसका भी सोशलिस्टिक पैटर्न पर बंटवारा न होकर एक मिनिस्टीरीयल हैसियत से बंटवारा हो रहा है । इसको मुझे देखने से मालूम होता है; बून्दी, कोटा, काकेड़, झालावाड़, झालरापाटन, भवानी मंडी इत्यादि इत्यादि तो बड़े चकाचौंध बिजली से होंगे और हमको तो शायद थर्ड फाइव इयर प्लान में भी मिलना मुश्किल है ।

तो मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा क्षेत्र है वह सिर्फ बारानी इलाके का क्षेत्र है । वहां पर अनाज की उपज बहुत ज्यादा है । तो जहां अनाज की उपज बहुत ज्यादा है वहां इसको और इम्प्रूव करने के लिए आसपास बांध बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाते हैं । तो पहले उस जगह को तरजीह दी जानी चाहिए जहां इसकी अत्यन्त आवश्यकता है, जिससे सरकार को अधिक आमदनी हो और पब्लिक को भी

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

फायदा पहुँचे। इसके साथ ही जो आपकी फूड की स्केअर्सिटी है उसमें भी कुछ फायदा पहुँचे। लेकिन इसका ध्यान नहीं रखा जाता। ध्यान रखा जाता है अपने ऐश और आराम का। आप सोचते हैं कि जहां कहीं से एक दफा चुन कर आ गये तो अगर अपने क्षेत्र को सर सब्ज नहीं करेंगे तो फिर चुन कर नहीं आयेंगे। हमारे यहां तो चाहे बिजली–पानी भेजो, चाहे न भेजो और जब हमारे यहां डबल फोर्स लगाते हो तब भी मैं बराबर चुन कर आ जाता हूँ इसलिये आप उन्हें फायदा नहीं देते हैं।

मेरा निवेदन करने का मतलब है कि इतनी बड़ी किताब छाप कर, बजट में करोड़ों रुपयों का प्रावधान करके यह खर्चा करते हैं और हमारे यहां काम करने के लिए, हमारे फायदे के लिए कहते हैं कि चम्बल की बिजली आपके पास आने वाली है, साल–दर–साल विश्वास देते हुए हो गये लेकिन उन इलाकों का इसमें कहीं नाम नहीं है। बिजली आप तीन जगह से लेते हैं, एक तो आप चम्बल के जरिये से लेते हैं। जहां चम्बल की बिजली नहीं पहुँचती है वहां डीजल इंजन के जरिये से लेते हैं। डीजल इंजन के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं कि उनियारा में भूतपूर्व जागीरदार ने प्राइवेट पॉवर हाउस चलाया था, वह आर्थिक कठिनाई होने से टूट गया, उससे बिजली नहीं मिलती। एक जो मालपुरा है–वहां एक डीजल इंजन लगाया, उसको ऐसा कर दिया। तो मैं आपसे कहता हूँ कि मालपुरा उदयपुर का एक मॉडल कायम करके बनाना चाहते हैं। मैं आपसे कहता हूँ वह तो मिनिस्टर साहब की कॉन्स्टीट्यूएन्सी है, लेकिन जहां काश्तकारों की आबादी ज्यादा है वहां आप यदि बनायें तो उससे आपकी जो सोशयलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की पॉलिसी है वह सक्सेसफुल हो सकती है। ये बड़े बड़े बजट बनाते हैं, इसमें इतना रखते हैं, चम्बल से ला रहे हैं, चम्बल से ला रहे हैं, इस तरह केवल विश्वास दिलाने वाले हैं। लेकिन अब दुनिया समझ गई है, वह यह जानती है कि आप हमको कैसा विश्वास देते हैं ?

तो मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि यह डिस्क्रिमिनेशन ठीक नहीं है। इन्द्रगढ़ मेरे उनियारा से मिला हुआ है। माधोपुर ले गये बिजली, रोजाना आदमी वहां हाट में जाते हैं, वहां पर लोग बिजली देखेंगे और हमारे यहां नहीं देखेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे ? यह आपकी क्या पॉलिसी है ? हमारे पड़ौस में बिजली देते हैं और हमारे यहां पर नहीं देते हैं। विरोधी क्षेत्र में नहीं देना चाहते तो डिक्लेयर कर दीजिये कि हम विरोधियों को बिजली नहीं देना चाहते। तो हम लोग भी उन लोगों को कह देंगे कि भाई, तुम लोग वोट इन्हीं को दो, ये तुम्हारे यहां पर बिजली ले आयेंगे, सड़कें बनवा देंगे, नहरें ले आयेंगे, सब कुछ कर देंगे। पर आप एक तरफ तो सोशियलिस्टिक पैटर्न का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ काम कैपिटेलिस्ट्स का सा करते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। यह आपकी पॉलिसी कुछ समझ में नहीं आती।

तो मैं कहता हूँ कि किसानों को बिजली दो! किसानों को, गांवों को बिजली देने से कृषि की पैदावार बढ़ेगी और उन लोगों की

(.वराजा श्री सरदारसिंह)

आर्थिक कठिनाइयां भी दूर होंगी। अभी लाइनें खींच रहे हैं, इस पर भी मैं यही सुझाव देता हूँ कि उस क्षेत्र के प्रोमिनेन्ट आदमी, कलेक्टर, वगैरह जिला परिषद् की मीटिंग करके आपको रिकमन्ड भी कर दिया कि उनियारा में बिजली नहीं देते तो डीजल एंजिन सेट-अप कर दो। आप यह कहते हैं कि पंचायत समिति से रिकमंड करा के, जिला परिषद् से रिकमेंड कराके भेजो, जिला परिषदों से रिकमेन्ड कराओ, पर हम यहां आपके यहां जनता के प्रतिनिधि आते हैं, उनके प्रोपोजल्स को किस आधार पर रिजेक्ट कर देते हैं ?

सबसे पहला सवाल हमारे सामने यह होना चाहिये कि गांवों की आमदनी कैसे बढ़े और गांवों के रहने वालों की आर्थिक कठिनाइयां किस तरह से दूर की जायं ? आप गांवों की आमदनी शहरों में लगाते हैं। अब शहरों से हट कर आप गांवों में आइये। शहर वैसे ही बड़े कन्जेस्टेड हो गये हैं, अब आप शहरों से गांवों की तरफ आ जाइये और गांवों को पॉवर देकर उत्पादन को बढ़ाइये और गांव वालों की आर्थिक स्थिति को ठीक करिये।

इसलिये मेरा निवेदन है कि शहरों से हट कर गांवों की तरफ आइये और पॉवर किसानों को दीजिये। उनियारा के लिये भी निवेदन करूंगा कि वहां पर बिजली दीजिये।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट पेश हुआ, वह उपयुक्त है पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि विद्युत् शक्ति जितनी राजस्थान में उपलब्ध होनी चाहिये उतनी नहीं हो सकी है। मेरी यह राय है कि जब तक बिजली का ठीक ढंग से वितरण नहीं होगा तब तक राजस्थान की उन्नति भी नहीं हो सकती।

यह निश्चित है कि राजस्थान विद्युत् बोर्ड बनने के बाद हमारे प्रोविन्स में विद्युत शक्ति की काफी प्रगति हुई है, पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अब भी जहां पर इन्डस्ट्रीज हैं और वहां पर विद्युत् शक्ति है, पॉवर हाउसेज चल रहे हैं वहां पर भी जो लोग छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाते हैं उनको पॉवर नहीं मिलती है। हमारे यहां पर जो बेरोजगारी है उसको मिटाने के लिये हम छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, इनसे हमारी बेकारी मिट सकती है, उत्पादन भी बढ़ सकता है पर इन छोटे छोटे उद्योगों को आज पॉवर नहीं दी जाती है। बड़े बड़े पॉवर हाउसेज़ शहरों में लगते हैं, उनका उपयोग भी होता है। शहरों में भी पॉवर हाउसेज़ लगाने चाहिये, क्योंकि हमारा राजस्थान शहरों में भी बसा हुआ है, शहरों की उन्नति के साथ साथ गांवों की भी उन्नति होती है, यह मानी हुई बात है। एग्रीकल्चर और इन्डस्ट्रीज दोनों की प्रगति से राजस्थान की प्रगति हो सकती है। तो इन्डस्ट्रीज के साथ साथ एग्रीकल्चर को कितना पॉवर देते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर पर ही इन्डस्ट्रीज की

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

उन्नति निर्भर है; यह देखना चाहिए। कच्चा माल एग्रीकल्चर से पैदा होता है तो पॉवर देकर एग्रीकल्चर की उन्नति नहीं करेंगे तब तक हम इन्डस्ट्रीज़ की भी तरक्की नहीं कर सकेंगे और हमारे सामने एक बड़ी समस्या पैदा होगी। जहां नहरों से सिंचाई के साधन हैं वहां पर विद्युत् शक्ति बाद में दी जाय तो कोई हर्ज की बात नहीं, पर जहां नहरों से सिंचाई नहीं होती, कुओं से सिंचाई होती है, बैलों से सिंचाई करनी पड़ती है वहां मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि उन लोगों के लिये जरूर ऐसे उपाय सोचने चाहिये कि चाहे राजस्थान सरकार को अधिक से अधिक धनराशि कर्ज लेनी पड़े पर एग्रीकल्चर पर्पज के लिये बिजली अधिकाधिक मिल सके।

देखा यह जाता है कि जहां शहरों के पास में गांव हैं, शहर से एक मील की दूरी पर कोई गांव है तो भी उनको पम्पिंग सेट के लिये, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिये बिजली नहीं मिलती है, इससे गांवों में बड़ा असंतोष फैलता है और लोग कहते हैं कि हमारे यहां पर कब बिजली आयेगी, न मालूम आप लोग कब तक हम लोगों को आश्वासन देते रहेंगे?

जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक है और जहां डीज़ल सैट्स लगे हुए हैं वहां भी एक तरह की रेट्स नहीं हैं। कहीं पर ८ आना यूनिट है तो कहीं पर ६ आना यूनिट है और कहीं कुछ लगा रखी हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सब राजस्थान में एक सरीखी रेट्स लगानी चाहिये ताकि लोगों के दिमाग में यह आ जाय कि सब जगह एक सरीखी रेट्स हैं। राजस्थान विद्युत् बोर्ड बना था तो हमने इस बात की आशा की थी कि राजस्थान विद्युत् बोर्ड इस बारे में विचार करेगा पर इस बोर्ड ने इस बारे में भी अभी तक विचार नहीं किया है।

किशनगढ़ के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले बिजली की लाइन फुलेरा से किशनगढ़ देना चाहते थे, अब कहते हैं कि अजमेर से देंगे। किशनगढ़ का मिल चालू होने वाला है, सन् ६२ में वहां मिल चालू हो जायगा। वहां पर यदि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर नहीं आई तो इस मिल का भी वही हाल होगा जिस तरह कि वहां १४ लाख रुपया लगा कर वाटर वर्क्स बनाया गया, पर पॉवर हाउस से बिजली देने को तैयार नहीं हुआ और इस तरह वाटर वर्क्स पर लगा। १४ लाख रुपया अभी तो यों ही बेकार साबित हुआ है। उसी तरह कहीं ऐसा नहीं हो कि मिल लग जाय और हाइड्रो इलेक्ट्रिक वहां पर पहुंचे ही नहीं।

तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करें और ऐसी स्थिति पैदा करें कि किसानों को पॉवर दी जाय और उससे किसानों को फायदा पहुंचे। छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज़ जो लोग खोलना चाहते हैं या चला रहे हैं उनको भी पॉवर दी जानी चाहिये। किशनगढ़ में कई लोगों ने वर्षों से छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज़ के लिये पॉवर देने के लिये एप्लीकेशन्स दे रखी हैं पर उनको जवाब दिया जाता है कि हम बिजली नहीं दे सकते। बिजली स्टेशन पर है, शहर में बिजली जलती है, पर इन्डस्ट्रीज़, जिनसे कि उत्पादन बढ़ता है, लोगों

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

की गरीबी मिटती है उनके लिये बिजली नहीं देते तो इससे लोगों में असन्तोष पैदा होता है और वे लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में बातें बनाते हैं। बिजली के लिये जिन लोगों की एप्लीकेशन्स आयें उनको जल्दी से जल्दी जवाब दिया जाना चाहिये, आज बारह महीने, दो दो वर्ष तक उन लोगों को जवाब नहीं दिया जाता है। कितने ही लोगों ने इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के हुक्म से पैसे जमा करा दिये हैं पर उनको पॉवर नहीं देते हैं।

मेरा निवेदन है कि पॉवर यदि देना है तो मिकदार मुकर्रर कर दीजिये कि इतने किलोवाट बिजली इन्डस्ट्रीज़ को देंगे और उतनी ही बिजली के लिये आप लोगों से एप्ली-केशन्स मंगवाइये ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके पास अभी तक यह हिसाब नहीं है कि भाखरा नांगल और चम्बल से हमको कितनी बिजली मिलने वाली है....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): है न ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा: नहीं, यह गलत है। कितनी बिजली आपको किस रेट से दे रहे हैं? आपके हिसाब में यह नहीं है कि कितना रुपया आपने जमा कराया है और किस रेट से आपको दे रहे हैं। मध्यप्रदेश को कितना रुपया देना है, कितनी बिजली प्राप्त हुई है, जो कॉन्ट्रेक्ट है उसके मुताबिक मिल रही है कि नहीं, इस बात को देखना चाहिये ताकि बजट में ज्यादा गुंजाइश की जा सके, जितनी पॉवर हमें मिल रही है उसको उपयोग में ले सकें, तभी विद्युत मंडल कामयाब हो सकेगा। जब तक डिस्ट्रिब्यूशन के लिये लाइनें ज्यादा से ज्यादा नहीं निकलेंगी, हर गरीब के घर में लाइन नहीं पहुंच जायेगी तब तक सही माने में हमें इस दिशा में काम-याबी नहीं मिलेगी।

सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बोर्ड का ज्यादा से ज्यादा बजट हो, पर्वाह नहीं कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। जब आप यह मानते हैं कि समाजवादी समाज की स्थापना आपका लक्ष्य है, हर गरीब का भला करने का हमारा लक्ष्य है तो सरकार को चाहिये कि हर किसान को, हर गरीब को पॉवर दें ताकि गरीबों की आर्थिक कठिनाइयां दूर हों, हमारे प्रान्त का प्रोडक्शन बढ़े और हमारे प्रान्त का फायदा हो।

(अनेक माननीय सदस्यों को बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंह दांता ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो कुछ भी आंकड़े दिये और पॉवर के सम्बन्ध में फरमाया, यह ठीक है कि राजस्थान में प्रयत्न हो रहा है और यह सब मानते हैं, होना भी चाहिये। मन्त्री महोदय ने कहा कि एस्टेब्लि-शमेंट भी हुआ है, पॉवर भी दिया जा रहा है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। पर जहां इसका उपयोग होना चाहिये था वहां पॉवर पहुँच रहा है कि नहीं? राजस्थान में कई काम हैं, इस सम्बन्ध में केवल पॉवर के मामले को ही नहीं एज्यूकेशन साइड को देखते हैं तो वह भी जिन लोगों के लिये हमने विचार किया था

(श्री मदनसिंह)

वहां न इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रही है, न एज्यूकेशन पहुँच रही है और न दूसरी चीजें पहुंच रही हैं और मैं समझता हूँ कि यह इलेक्ट्रिसिटी का जिसने निर्माण किया उसके दो ही पहलू हो सकते हैं। एक तो आराम लोगों को मिले और दूसरा पहलू सस्ताई का था। गरीबों को इतनी इलेक्ट्रिसिटी मिले कि वे अपने आपको किसी बड़े से बड़े आदमी से कम न समझें। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सोशियलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी इस पॉवर से हो सकती है। आज एक गरीब के यहां पर बिजली है तो वह ऐसा महसूस करता है कि जिस प्रकार जयपुर नरेश अपने घर में बिजली लगा कर अपने आपको महसूस करते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मंत्री) : मैंने यह नहीं कहा था कि सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को बढ़ाने के लिये है। मैंने यह कहा कि इसके द्वारा प्रोडक्शन बढे और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो हम सोशियलिस्टिक पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं।

श्री मदनसिंह : प्रोडक्शन कब बढेगा, बिजली लोगों को कब मिलेगी ? मेन्टली भी लोग सोच सकते हैं। आज हम देखते हैं कि जयपुर में जौहरी बाजार में दो हजार रोशनी की बत्तियां हैं। आज कोई जयपुर में देहाती आवेगा तो वह क्या सोचेगा कि क्या यहां जौहरी बाजार के रहने वाले इतने अन्धे हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : बिजली से तो अन्धों को भी नहीं दिखता है।

श्री मदनसिंह : मैं सूझते हुए अन्धों के लिये कह रहा हूँ।

मतलब यह कि जिसने बिजली का आविष्कार किया होगा उसने इकॉनोमिक पोइन्ट ऑफ व्यू को लेकर किया होगा, किस तरह से आर्थिक संकट दूर हो। आज आध्यात्मिक दृष्टि से सोचा जावे तो कुछ नहीं है यह बाहर की चीज है। आविष्कारक ने इकॉनोमिक दृष्टिकोण से इसका आविष्कार किया। इकॉनोमिक दृष्टि से देखते हैं तो किस प्रकार से उन्नति हो सकती है ? मैं समझता हूँ कि गांवों में लोगों के पास काम नहीं है और बेकार बैठे हैं। अगर वहां पर बिजली हो तो बहुत सी बेकारी दूर हो सकती है। मगर गांवों में बिजली नहीं होने से वह दिक्कत गांव वालों को हो रही है। केवल प्रचार मात्र के लिये कि हम चुनावों में किस प्रकार आवें, इसके लिये केन्द्र खोलें तो वह उचित नहीं कहा जा सकता। मैं कहूँगा कि इसमें गवर्नमेंट का सही रुख नहीं होगा। आप कितना ही खर्चा कर ले लेकिन जब तक आप इकॉनोमिक फैक्टर को नहीं देखेंगे कि सही माने में इसका कहां पर यूज हो सकता है और होना चाहिये जहां कि नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ, जहां पर इसकी जरूरत हो और सही माने में वहां पर पॉवर नहीं पहुंचे तो जनता के रुपये हैं, जिन्होंने आपके आश्वासन पर रुपये दिये हैं उनके साथ भी आप न्याय नहीं करते हैं। बाहर गांवों में बड़े बड़े हॉस्पिटल और कॉलेज हैं वहां पर बिजली नहीं है। अगर बिजली हो तो बहुत सुविधा हो जाती है और जो एग्रीकल्चरिस्टस हैं उनको भी बिजली से काफी सुविधा मिल सकती है। शहरों में हर प्रकार की सहूलियत मिल सकती है। खाने पीने में भी आजकल जो खर्चा हो रहा है वह खर्चा भी मामूली नहीं

(श्री मदनसिंह)

है। आज हम देखते हैं कि गांवों में लकड़ी का बहुत अभाव है जिसको हम महसूस नहीं कर सकते। लोगों को जलाने के लिये लकड़ी आसानी से नहीं मिलती है। आज वहां पर अगर बिजली का प्रबन्ध हो तो उसके द्वारा खाने-पीने का प्रबन्ध भी हो सकता है। आज किसानों को उनके खेत से लकड़ी नहीं काटने देते। आज तेल का क्या भाव है? उसको हम शहर में रहने वाले भूल गये हैं। आज गांवों में पानी पीने के लिये बड़ी मुश्किल से लोगों को मिलता है। आज जो शहरों में रहने वाले हैं उनको यह कमी महसूस नहीं होती क्योंकि यहां पर नल लगे हुए हैं। हम नहीं सोचते कि डे टू-डे लाइफ में बिजली की कितनी आवश्यकता है और कम पैसा होते हुए भी वहां पर बिजली का पॉवर नहीं पहुँचता है उससे गांवों की बहुत दुर्दशा हो रही है और वे ऐसा सोचते हैं कि पुराने युग में जिस प्रकार शहरों और गांवों में बहुत बड़ा अन्तर होता था उसी प्रकार वे अभी भी महसूस करते हैं।

इसके अलावा मैं यह कहूँगा कि राज्य का जो भी काम होता है वह पोलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए होता है। यह भी एक कारण नहीं होना चाहिये। जहां पहले बिजली थी वहां पर फिर केन्द्र हो रहे हैं और जहां पर वाकई में बिजली के पहुँचने के लिये बहुत आवश्यकता है वहां पर नहीं पहुँच रही है। मैं यह कहूँगा कि एक मिनिस्टर जिनके घर पर और फार्म में बिजली पहुंच गई जो पहले मिनिस्टर थे और जहां पर २० हजार की काश्तकारी होती है वहां पर बिजली नहीं पहुँचती है। इस प्रकार की पोलिटिक्स के द्वारा कार्य किया जाता है। मैं नहीं समझता कि मौजूदा मंत्री महोदय का उसमें हाथ है। उन को तो बनी बनाई योजना मिली है उसके अनुसार कार्य करते हैं। आप जो कुछ करना चाहें कर लें। सन् ६२ में करने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि बाद में भी आप ही यह कार्य करेंगे, यह विश्वास नहीं होता। यह पुरानी योजना है और आप इस पर विचार कर रहे हैं, यह हमें विश्वास है। परन्तु जब तक यह नहीं होगा कि जहां पर इसकी जरूरत है इसको पहुंचाया जावे तब तक कोई भला नहीं हो सकता। जो लोग इकॉनोमी में बहुत पीछे हैं उनके लिये कहूँगा कि जो हरिजन चमड़े का काम करते हैं अगर उनको पॉवर दिया जावे तो वे इतनी उन्नति कर सकते हैं कि आज शहर में जो फैक्ट्रीज हैं वे भी नहीं कर सकतीं। आज उनका इकॉनोमिक सेट-अप इतना अच्छा हो सकता है कि जो बेकार है वह बेकार नहीं रह सकता। इस पर और भी लोग कहेंगे कि क्या क्या घोटाले हुए हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि घोटाले प्रूफ हो गये हैं, उनको न तो वे रोक सकते हैं न रुक सकते हैं। इसलिये मैं इस बात पर ज्यादा जोर दूंगा कि जिनके पास पॉवर पहुंचना चाहिये और जो ठीक ढंग से उसको उपयोग में ले सकें उनके पास पॉवर पहुंचे। अगर उदयपुर में इसकी ज्यादा जरूरत है यह कहें और वहां पर ज्यादा पॉवर इन्सटाल करें तो मैं यह कहूँगा कि सरकार के मनी और जनता के मनी का वैस्टेज होगा। मैं यह कहूँगा कि चुनावों के समय में पोल लग जाते हैं मगर बिजली नहीं आती। लोग यह समझते हैं कि बिजली आनेवाली है मगर बिजली नहीं आती और खंभे ही लग कर रह जाते हैं। पहले तो सरकार ने एक नारा शुरु किया था वह पंचवर्षीय योजना

(श्री मदनसिंह)

का था और अब नया नारा शुरु किया है सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का। कोई भी काम हुआ तो फौरन सोशियलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी का नारा लगाते हैं। कैसे कैसे शब्द पकड़ लेते हैं और उनको लेकर आगे बढ़ते हैं। मैं यह समझता हूँ कि गरीबों के पास बिजली पहुँचनी चाहिये। आप देखेंगे कि शिक्षा का भी यही हाल है। बड़े बड़े लोगों के लड़कों को शिक्षा प्राप्त होती है और गरीबों के लड़कों को बहुत कम। वैसा ही हाल बिजली का है। इसको हम सब समझते हैं और सोचते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास उनकी आवाज नहीं है। गवर्नमेंट उसको पूरा करने के लिये तैयार नहीं है। इसलिये लोग यह कहते हैं कि जिस समय वोट का समय आता है आकर पुकारा जाता है, जिस जिस की कॉन्स्टिटयून्सी होती है उसमें।

मैं यह कहूँगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में सबसे ज्यादा राजस्थान में कुएं हैं। लेकिन कुओं से पानी खीचनें के साधन नहीं हैं। वहां के किसान इतने पैसे वाले नहीं हैं कि इतने ऊन्डे कुओं से पानी निकालने के लिये १० जोड़ी बैल रख सकें और कोई दूसरा साधन नहीं कि वे पानी निकाल कर उसका ठीक तरह से प्रयोग कर सके। हमारे उधर से लाइन निकलती है, मगर दांता रामगढ़ में बिजली नहीं है। दांता रामगढ़ को ऐसा समझ रखा है कि उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं। मुझे कोई अफसोस नहीं अगर ठाकुर मदनसिंह के यहां पर बिजली नहीं लगे, मुझे इसकी परवाह नहीं, मगर मेरी वजह से पब्लिक को बिजली नहीं मिले, यह आज उनका दुर्भाग्य है। लेकिन अगर यह सोच कर कि हमारा यहां पर प्रभाव है या नहीं, हमको यहां से वोट मिलेंगे या नहीं इस चीज़ को लेकर पॉवर डिस्ट्रिब्यूट करगे तो मैं यह कहूँगा कि सोशिएलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का नारा जैसा आपने फर्माया वह नहीं रहता है। मैं समझता हूँ कि गांवों में गरीब लोग फिजूल बैठे हुए हैं, उनके छोटे २ उद्योग धन्धों के लिए यदि इलेक्ट्रिसिटी, पॉवर नहीं दिया जावेगा और पूरा शहरों को ही दिया जाता रहेगा तो उससे ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है। मैं समझता हूँ कि आप ही आइन्दा के लिए इस विभाग में विराजे और अपनी योजना को पूरा करें। आज फर्स्ट अप्रैल है इसलिए इस बात के लिए बधाई है आपको मेरी।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, आज सदन में राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक), १९६१–६२ पर विचार-विमर्श हो रहा है।

पहले बिजली विभाग की स्थिति बड़ी खराब थी तो राजस्थान सरकार ने यह निर्णय किया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना दिया जाय और इसको एक व्यॉपारिक दृष्टिकोण से रन किया जाय तो विद्युत् शक्ति बढ़ सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि जो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है वह बड़ा कामयाब हुआ है, इसलिए मैं मंत्री महोदय को और स्टाफ को बधाई देता हूँ। यह बोर्ड काम कर रहा है, इसका प्रमाण है। विद्युत् शक्ति जो जेनरेट होती थी उसमें वृद्धि की है और उसको संतोषजनक भी कहा जा सकता है। राजस्थान के इस बोर्ड के मैं ६०–६१ और ६१–६२–इन

(डॉ० बहादुरसिंह)

दो वर्षों के आंकड़े सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा। ६०-६१ में ७२, २८३ किलोवाट बिजली उत्पन्न की और ६१–६२ में ९२,६२० किलोवाट करना चाहते हैं। इस प्रकार से इस वर्ष, जो आज से शुरू होता है, २५ हजार किलोवाट से अधिक शक्ति का उत्पादन बढ़ जावेगा। इसी प्रकार से जहां विद्युत् शक्ति बढ़ी है तो मुनाफा भी बढ़ा है। यदि मुनाफे के आंकड़ों को देखेंगे, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है, २ लाख ५१ हजार का मुनाफा हुआ। मैं उसमें जाने से पूर्व यह बताऊं कि किन किन आंकड़ों से यह वृद्धि होगी। थर्मल स्टेशन्स से दो करोड़ की आमदनी होगी। मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि २५१ हजार का मुनाफा अंकित किया है, लेकिन चाहे यह अलोचना हो, इस बात पर, इसमें ब्याज सम्मिलित नहीं किया गया है और यदि इसमें ब्याज सम्मिलित कर दिया जाता तो यह २७ लाख के घाटे का हो जाता। कोई दूकानदार किसी चीज़ पर केपिटल लगाता है तो उसके लिए उसको इन्ट्रेस्ट अपनी बचत पर पहले लगाना पड़ता है

(१. म० प)

गत वर्ष हानि में थे। ६१–६२ के वर्ष में मुनाफे का सवाल है। मैं इस बात पर संतोष करता हूं। यदि इस पर ब्याज देना पड़े तो २७ लाख का घाटे में हो सकता है। लेकिन बिजली सेल होगी और जो रनिंग खर्चा है उस सब के बाद भी २.५९ लाख का मुनाफा होता है। ये सारे एस्टीमेट उपस्थित करने के बावजूद भी पिछली बार सदन में सवाल आया था कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज़ हैं वे कितने हैं ? न विभाग ने और न ही मंत्री महोदय ने इस पर रोशनी डाली है। अब माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर दें तो यह बताने की कृपा करें कि ६०-६१ में कितने इलेक्ट्रिक ड्यूज़ थे, उनमें से कितनी रिकवरी कर पाये, कितना बाकी रहा है, स्टेन्डिंग में कितना रह जाता है ? जिस व्यक्ति पर हमारा रुपया बाकी है वह हम बकाया देना चाहेंगे।

हमारे जितने पॉवर स्टेशन्स हैं, वे कितने घाटे और मुनाफे में चलते हैं ? कुछ पॉवर स्टेशन्स की मैंने छान–बीन की है। ३६ पॉवर स्टेशन्स के अकाउन्ट्स इसमें हैं। इसमें मुनाफे में केवल ११ पॉवर हाउसेज़ चलते हैं। जो पिछली साल घाटे में थे और अब मुनाफे में आये हैं वे तो दो ही पॉवर हाउसेज़ हैं। १६ तो ऐसे हैं जिनमें गत वर्ष से भी इस वर्ष अधिक घाटे के होने की संभावना है। हमारा मुनाफा अधिक होगा यदि ये जो छोटे २ पॉवर स्टेशन्स हैं उनमें थोड़ी अधिक केपिटल लगा कर विद्युत् बढ़ावें। वैसे सारे काम योजना-बद्ध होते हैं और धीरे २ कदम बढ़ा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस ओर सफलता पूर्वक बढ़ रहा है। लेकिन एक बात निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो १६ पॉवर स्टेशन्स हैं, गत वर्ष से भी उनमें अधिक हानि होने की संभावना है। तो उसकी खोज–बीन करनी चाहिये, ताकि जिनमें हानि होने की संभावना है उनको किस प्रकार से दूर किया जा सके। पॉवर स्टेशन्स पर मैं अधिक डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा। केवल एक निवेदन और करना चाहूंगा। हम पहले तो बजट के आंकड़े बनाते हैं और उनके बनने के बाद जब रिवाइज़्ड एस्टीमेट्स आते हैं तो उनमें फर्क होता है। किन किन

Page No 51

(डॉ० बहादुरसिंह)

टैक्निकल आधारों पर यह फर्क आता है, यह मेरी समझ में नहीं आया है। लेकिन जो आंकडे मैंने देखे हैं उनसे मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि फर्क रहा है।

जब बजट एस्टीमेट्स बनायें तो उस वक्त ही यदि सारी बातों पर ध्यान रखें तो रिवाइज़्ड बजट पर जो फाइनेन्शियल परेशानियां होती हैं वे उन पर जाकर नहीं पड़ेगी।

धौलपुर के बारे में कुछ अर्ज करना चाहूँगा। क्षेत्रीय भावना समझ कर ही कुछ कहना चाहूँगा। वहां पर पॉवर की स्थिति सुधार पर है यह मैं सदन में स्वीकार करता हूँ और यह भी स्वीकार करता हूँ कि गत वर्ष जो स्थिति थी वह अब नहीं है। यदि हमें राजस्थान का औद्योगीकरण करना है तो राजस्थान के पॉवर स्टेशन्स की स्थिति को सुधारना होगा। यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर ही निर्भर करता है। चाहे हम किसी प्रकार से सोचें, मैं उन माननीय सदस्य की आलोचना नहीं करना चाहता जो जन संघ से आते हैं; विभाग में घोटाला है या क्या है ? न तो घोटाला सामने रखा, केवल उन्होंने कहा कि दो हजार किलोवाट्स की जयपुर शहर को बात है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि विद्युत् औद्योगीकरण की दृष्टि से यदि उद्योगों को सस्ती बिजली दे सकें तो राजस्थान की सम्पत्ति में वृद्धि होगी।

धौलपुर और मुरेना के लिए निवेदन करूंगा। इस रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि कोटा और सवाई माधोपुर को मार्च ६१ तक समाप्त करना चाहते हैं, कम्प्लीट टार्गेट है वह ६१ का है। उधर ग्वालियर और मुरेना का हो गया है और केवल धौलपुर और मुरेना का ही बच जाता है। इसलिए इसको प्रारम्भ कर देना चाहिये। ६१ में इलेक्ट्रिसिटी पूरी होने पर मुरेना में आवेगी, धौलपुर में भी आ सकती है।

तो मैं इस आशा के साथ कि आप इस सम्बन्ध में कुछ विचार करें और इस काम को प्रारम्भ करने का प्रयास करेंगे, अपना निवेदन समाप्त करता हूँ।

मैं एक बात और रखना चाहूँगा, जैसा कि आपने समाचार पत्रों से भी मालूम किया होगा। केन्द्रीय सरकार एटोमिक पॉवर स्टेशन यू. पी. में बनाने जा रही है। उत्तरप्रदेश और दिल्ली के वह निकट बनेगा। इसमें राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों की भी बात आती है। मैं चाहूंगा कि इस बारे में सरकार और खास तौर से विद्युत विभाग सतर्क रहे और अधिक से अधिक बिजली इससे प्राप्त करने और उसे उचित रीति से खपाने की कोशिश करे।

मैं आपके विभाग को और भी बधाई देता हूं कि आप लेबर लफ़ेयर के काम में भी अग्रसर हुए हैं और इस बजट में एक लाख से भी ज्यादा रकम रखी है। पर इसमें एक बात है। इस एक लाख को खर्च करने के लिये प्रशासनिक व्यवस्था में आप ५०,७२६) रुपया खर्च करने जा रहे हैं। इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों के नाम पर इतना रुपया लेकर इसका बहुत बड़ा भाग व्यवस्था पर ही खर्च कर दें; यह कतई उचित नहीं होगा और इसलिये हमे

Page No 52

(डॉ० बहादुरसिंह)

व्यवस्था पर खर्चा कम करना चाहिये या फिर यह रुपया और बढ़ाना चाहिए। अन्त में बधाई देते हुए यह निवेदन करता हूं कि जब आप काम शुरू करें तो धौलपुर के बारे में शीघ्रता करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री दलपतसिंह।

श्री दलपतसिंह (आबू) : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि इस विद्युत मण्डल की प्रगति देख कर हमें खुशी होती है। पर इसके वितरण के बारे में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक उसने वितरण का काम अर्बन एरिया में ही किया है। सबसे ज्यादा जोर मैं रूरल एरिया में इसके वितरण पर देना चाहता हूं। हम तीसरी योजना में ३५ करोड़ खर्च करने जा रहे हैं। अब तक रूरल एरिया में जोरों की प्रगति है। देश की प्लानिंग के लिये और इण्डस्ट्री और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिये सब का समान विद्युतीकरण आवश्यक और नितान्त उपयोगी है। इससे मैं यह नहीं कहता कि शहरों को बिजली न दी जावे। दी जावे, पर आज हमारा प्रधान लक्ष्य एग्रीकल्चर के डवेलपमेंट का भी होना चाहिये। हमारी तीसरी योजना बहुत कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर निर्भर करती है।

एग्रीकल्चर में काफी एक्सपेन्डीचर प्रोड्यूस के लिये करना पड़ता है, पर आज ईल्ड हमें उतना नहीं मिल रहा है। आज बैलों पर और उससे अगर कहीं आगे बढ़े हैं तो पम्पिंग सेट पर खर्च ज्यादा होता है। इनके लिये क्रूड ऑइल डीजल ऑइल पर खर्चा ज्यादा पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस खर्चे को अनेलाइस किया जावे और इसके मुकाबले में अगर वहां बिजली दी जावे तो उसके खर्चे का भी अनेलिसिस करके दोनों का मुकाबला करके देखा जाय कि किससे फायदा रहेगा।

इसके लिये मेरा जहां तक प्रिज़म्पशन है कि बिजली से इस खर्चे में काफी बचत होगी। बिजली के देहात में जाने से किसान का लिविंग स्टेन्डर्ड भी कुछ बढ़ेगा और हम जो सोशियलिस्टिक पैटर्न के समाज की बात करते हैं उसके लिये भी यह उचित होगा। आज पम्पिंग सैट या डीज़ल आदि से चलने वाली मशीनें भी खराब होती ही रहती हैं। इससे भी प्रोडक्शन में काफी बाधा पड़ती है। तो बिजली देने से वहां यह भी बाधा दूर हो जावेगी।

एग्रीकल्चर के अलावा वहां पर हमारे यहां जैसे सिरोही, जालोर और कुछ सुमेरपुर वगैरह के पास में कुएं हैं। उन पर बिजली लग जावे तो अच्छी सिंचाई हो सकती है। वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक मिलने की सम्भावना नहीं है। वहां तो आप थर्मल एन्जिन ही लगा सकते हैं। तो इस दृष्टि से आप सर्वे कराइये कि आबू में कितने कुएं हैं, आसपास के इलाकों के कितने कुएं हैं। अगर वहां पर एक अच्छा एन्जिन उस एरिया के बीच में लगा दिया जावे तो हजारों कुओं से सिंचाई की जा सकेगी, इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में भी वृद्धि होगी और साथ ही किसानों का लिविंग स्टेन्डर्ड भी बढ़ेगा।

मन्त्री महोदय सिरोही जब पधारे थे तो

Page No 53

(श्री दलपतसिंह)

वहां की ज्योग्राफिकल पोजीशन उनको बताई थी। यह भी बताया था कि सिरोही और आबू में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अलावा छोटी मोटी इन्डस्ट्रियों के चलने का भी काफी स्कोप है, इसका रॉ मेटीरियल वहां काफी है; जैसे सीमेन्ट और कागज के कारखाने वहां लग सकते हैं। पर आज पॉवर नहीं मिलने से छोटे छोटे उद्योग भी सफलतापूर्वक नहीं चल सकते तो इन बड़े बड़े उद्योगों की तो बात ही नहीं की जा सकती। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरफ तवज्जोह दी जावे। सिरोही एग्रीकल्चरल और छोटे-मोटे उद्योग धन्धों को देखते हुए अच्छी पोटेन्शियेलिटी वाला जिला है। पानी का काफी साधन है, काफी कुए वहां हैं। सोइल भी वहां की अच्छी है, कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ का भी काफी स्कोप है। चाहिये बिजली। इससे एम्प्लॉयमेंट के हल करने में भी काफी मदद मिलेली।

अन्त में, मैं निवेदन करूंगा कि आपने अर्बन एरिया में अब तक काफी पॉवर दिया है, अब रूरल एरिया को भी ज्यादा से ज्यादा पॉवर देने की तरफ तवज्जोह दिलावें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु.): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में विद्युत मण्डल की जब से स्थापना हुई तब से हमारे राज्य की विद्युत योजना बनी और उसके बनाने में हमारे मन्त्री माननीय हरिश्चन्द्रजी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने परिश्रम से इस योजना को बनाया और राजस्थान पर लागू करने के लिये इसका बजट ६१-६२ का सदन में प्रस्तुत किया।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे क्षेत्र में एक शुगर फैक्टरी है-भूपाल सागर में, इसमें भी आप बिजली दे रहे हैं। दूसरा मेरे क्षेत्र में बल्लभनगर तहसील में भींडर जो आदिवासी क्षेत्र है, जो हजारों वर्षों से पिछड़ा रहा है, उस इलाके के आदिवासी मीणा लोगों को भी बिजली के द्वारा सहूलियत मिलेगी, छोटे-मोटे उद्योग धन्धे चला सकेंगे, कुओं से पानी निकाल सकेंगे और इससे कृषि को भी फायदा मिलेगा और इसमें वृद्धि होगी। इससे हमारे राजस्थान की आय भी बढ़ेगी।

एक निवेदन कर दूं कि बड़े बड़े शहरों को बिजली दी जावे, देना भी चाहिये उनको पर वह जनसंख्या के आधार पर दी जानी चाहिये। गाँव में कृषक जनता को भी जन-संख्या के आधार पर मिलनी चाहिये। काश्त की जमीन उनके पास अच्छी है, पानी के कुंए भी अच्छे हैं, पर आज लाव चड़स के द्वारा या पम्पिंग सेटों के द्वारा भी पानी निकालते हैं पर इससे खर्चा ज्यादा पड़ता है और खेती की आय बढ़ती नहीं है।

यदि माननीय मन्त्री महोदय उन लाखों कृषकों को बिजली दें जिनके कुओं में काफी पानी है तो बिजली उन इलाकों में दी जाये जहां बिजली द्वारा पानी खींचकर अपनी जमीन को दो फसली बनाना चाहते हैं। एक तरफ हमारी राज्य सरकार के सामने यह प्रश्न भी है कि अनाज बाहर से लाना पड़ता है और दूसरी तरफ सैकड़ों एकड़ जमीन सरकार के पास

(श्री हरिप्रसाद यादव)

पड़त पड़ी हुई है। तो मैं निवेदन करूंगा कि यदि अधिक अन्न उपजाना चाहते हैं तो मन्त्री महोदय उन कृषकों को विद्युत् मण्डल योजना में सम्मिलित कर लें। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने यह भी कहा है कि फलां जगह यह हो रहा है। तो जहां भाखरा और चम्बल से जितना फायदा राजस्थान को होगा उससे अधिक मध्यप्रदेश के गांवों को भी होगा। कोई बड़ी योजना लागू होती है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी हो जाता है कि जैसे हमारी राजस्थान केनाल है, मैं उदाहरण पेश करूं, उससे पंजाब को फायदा होगा, तो जितना फायदा पंजाब को होगा उससे अधिक राजस्थान को भी होगा और राजस्थान का रेगिस्तान उससे मिटेगा। तो विद्युत् मंडल के अधिकारियों द्वारा यह परम्परा न लग जाये कि व्यक्तिवाद और जातिवाद का नारा लगा दें, तो जो हमारा राजस्थान का पिछड़ा हुआ इलाका है वह पिछड़ा हुआ ही रह जायेगा।

श्री अध्यक्ष : कौनसे जातिवाद का नारा लगाया गया ?

श्री हरिप्रसाद यादव : मेरा मतलब यह है कि कहीं राजपूतों को ज्यादा बिजली दे दें।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : शिड्यूल्ड कास्ट को ज्यादा दीजिए।

श्री हरिप्रसाद यादव : जिस तरह से जमीन के मामले में भेदभाव चल रहा है उस तरह कहीं इसमें भी न होने लगे। तो मैं मेरे क्षेत्र की वकालत करता हुआ मैं राजस्थान के इन २५ जिलों की भी वकालत कर रहा हूँ। इन जिलों को निष्पक्ष रूप से बिजली से वंचित न रखें। तो मेरा बस यही निवेदन है।

तीसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इस अधिवेशन में बहुत महत्वपूर्ण बिल पास होते हैं। जैसे समाज शिक्षण बोर्ड का बिल भाई श्री जनार्दनरायजी नागर ने रखा....

श्री अध्यक्ष : यह इससे सम्बन्ध नहीं रखता है।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं उदाहरण दे रहा हूँ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : बिजली में आप वंचित नहीं रहेंगे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : इस पर आपको कल बोलने नहीं दिया गया था इसलिए आज बोलने दीजिए।

श्री हरिप्रसाद यादव : इसलिए मेरा कहना यह है कि हरिजन और आदिवासियों को बिजली के मामले में वंचित न रखें।

(१. ३५. म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आदिवासी और हरिजनों को जो कल समाज शिक्षण बोर्ड

(श्री हरिप्रसाद यादव)

विधेयक रखा गया उसमें भी वंचित कर दिया....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! कल जो बिल पास हो चुका है उसके सम्बन्ध में, उसकी प्रगति और विकास या उसकी व्यापकता कुछ भी हो, नहीं बोलेंगे ।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उदाहरण पेश किया था।

तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वह एक वीर भूमि है । मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने उस वीर भूमि में जन्म लेकर इस स्वराज्य की नींव लगाई थी । मैं यह चाहता हूँ कि मेवाड़ के महाराणा के क्षेत्र में आदिवासी और हरिजन लोग रहते हैं जिन्होंने प्रजामण्डल के जमाने से आज तक लड़ाई लड़ी है।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय विद्युत् मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे आदिवासी और हरिजनों को उनके क्षेत्रों में बिजली से वंचित न रखें । यह ही बस मेरी आपसे अपील है । वैसे तो बहुत बड़ी योजना हमारे राजस्थान में लागू करने का प्रयास किया है । तो मैं आपको फिर बधाई देता हुआ यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में आदिवासी और हरिजनों का ख्याल तो आप रखें । लेकिन हजारों और लाखों की तादाद में ऐसे कुएं हैं जिनमें काफी पानी है किन्तु उनको मशीनें उपलब्ध नहीं हो रही हैं । यदि उनको मशीनें उपलब्ध हो जाती हैं तो वे अपनी जमीन को एक फसली से दो फसली बना लें । तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन कृषकों का ध्यान भी रखा जाये । वैसे मेरे क्षेत्र में भोपालसागर में शुगर मिल है और उसको डबल किया है वहां के उद्योगपति ने, फिर भी वहां पर गन्ना नहीं खींचा जा रहा है । अभी कुछ दिन पहले माननीय मन्त्री महोदय से उदयपुर डिविज़न के कृषकों का एक डेपुटेशन मिला था और वह गन्ना-माण्डल, भीलवाड़ा जावर मिल को दिया गया । तो मैं आप से निवेदन करूंगा कि हमारा यह शुगरकेन एरिया है और उसमें काफी गन्ना पैदा होता है । मावली, भोपालसागर, और कपासिन, राजसमन्द....

श्री उपाध्यक्ष : भोपालसागर का बिजली से क्या सम्बन्ध है ?

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर आ रहा हूँ । मैं कहता हूँ कि बिजली उन लोगों को मिले जो किसान हैं, गन्ना पैदा करते हैं । उनके कुंए बिना पानी के सूख जाते हैं । तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय का ध्यान शुगरकेन एरिया की ओर दिला रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : आप तो मिल मालिक की वकालत करने लग गए ।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं फिर एक बार मंत्री महोदय को बधाई दूं कि इस उदयपुर डिविजन के पिछड़े क्षेत्र को भूल न जायें ।

श्री उपाध्यक्ष: रावल नरेन्द्रसिंह ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष

Page No 56

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

महोदय, जैसा कि यह प्रश्न है करीब करीब सब ही माननीय सदस्यों ने यह सवाल उठाया है कि नगरों के अन्दर ज्यादा बिजली खर्च होती है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और गांवों के अन्दर कम इसका उपयोग होता है। यह मैं भी अर्ज करूंगा कि एक तरह से शहरों के अन्दर जो आमदनी गवर्नमेंट के खजाने में आती है वह अगर २५ पर्सेन्ट है और जो बाहर को जनता पैदा करके ७५ पर्सेन्ट आमदनी देती है तो नागरिकों को जो सुविधा मेडीकल में, एज्यूकेशन में और दूसरी हर चीजों में होती है वह ज्यादा हो जो कि गांवों में कम होती है। तो इसके लिए निवेदन यह है कि देखा जाये तो हम लोग यह भी नहीं सोचते। वहां भी कई ट्रेड्स हैं, दूसरी चीजें हैं तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि शहर वालों को लॉयन शेयर मिलता है और जो बाकी गरीब जनता है, जो अन्न उत्पादन करती है, इसके अतिरिक्त वहां जैसे छोटे मोटे ट्रेड के साधन हैं वे यां के यों खाली रह जायें और उनको कुछ भी नहीं मिले तो यह बात जरूर विचार करने की है। तो जैसे इस वक्त में पानी के जो बड़े बन्ध हैं और बिजली आदि से संबंधित दूसरी स्कीमें हैं उनमें गवर्नमेंट ने काफी खर्च किया है और कर रही है और इस उद्योग के प्रति आगे प्रभावमान हो रही है।

जो ऐसे मामलों में जैसा कि हमारे माननीय मंत्री महोदय ने इसके ऊपर प्रकाश डाला और इस बात के वास्ते यह फरमाया कि आगे बढ़ने के वास्ते यह उपाय हो रहे हैं तो यह कार्य मैं स्तुत्य समझता हूँ। तो यह जरूरी बात है कि चाहे कुछ भी किया जाय कि सब जनता और प्रत्येक चीज़ का समुदाय है वह कभी भी संतुष्ट होने का नहीं है। यह तो जरूरी चीज है। लेकिन इसके वास्ते इस चीज़ की भी आवश्यकता है कि किसको ज्यादा आवश्यकता है और किस को कम मिला है। सबसे पहले भूखे को देने की ज्यादा जरूरत है बनिस्बत कि धाये हुओं को। यह देखा गया कि जिन हिस्सों के अन्दर पानी की प्रचुर मात्रा हम लोगों को उपलब्ध हुई है वहीं पर ज्यादातर बिजली का भी अड़ंगा होगा। मेरे माननीय सदस्य, बालोतरा से आने वालों ने पहले भी कई दफा कहा है कि बाडमेर में उन हिस्सों में बहुत ही कम पिछले सालों में प्रत्येक प्रकार के साधन उपलब्ध हुए हैं, चाहे वह मेरा भू-भाग नहीं होते हुए भी मैं यह निवेदन करूंगा कि सबसे पहले उनको स्थान दिया जाय; और इसके बाद में जहां पर जिसको जितनी ज्यादा आवश्यकता हो उसके वास्ते व्यवस्था होनी चाहिए।

मेरा निवेदन यह है कि शहरों के अन्दर रोज सेन्सस के अन्दर हम देखते हैं; यही नहीं, परन्तु भारतवर्ष में राजस्थान के बाहर भी शहर काफी बढ़ रहे हैं और इसके अतिरिक्त जो बाहर की कृषक जनता है वह और बाहर के लोग खींचे हुए शहरों के अन्दर जा रहे हैं। इसका कारण ही यह है कि वहां शहरों के अन्दर जो सुभीते उपलब्ध होते हैं और इसके अतिरिक्त कारखाने चलते हैं और दूसरी नाना प्रकार की सुभीते की चीजें हैं उनके ऊपर खींचते हुए आप से आप जा रहे हैं तो कृषकों के वास्ते इस चीज़ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि जहां बहुत से हिस्से इस प्रकार के हैं कि जहां पानी

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

की काफी प्रचुरता है और साधन हैं वहां पर बोरिंग वगैरह लगा कर और जहां बिजली नहीं भी पहुंच सके उन जगहों में दूसरे आयोजन रख कर और इस तरह से वहां पर बिजली पहुंचाने के प्रत्येक प्रकार के साधन होने चाहिए।

मैं मेरे खुद की जो कॉन्स्टीटुएन्सी है उस पर भी आऊंगा। देखा जाता है कि इस बीच के हिस्से के अन्दर दूदू और मौजमाबाद का इलाका एक तरह से ग्रेनरी ऑफ जयपुर स्टेट समझा जाता था और जैसे बाहर के कोटा, बूंदी और बीकानेर की तरफ की जो स्कीमें पुष्पित और फलवती नहीं हुई थीं उस समय वहां यही इलाका बहुत अनाज देता था। तो इस इलाके के अन्दर बोरिंग की बहुत ही आवश्यकता है। यहां पर कालक सागर, इसके अतिरिक्त छापरवाड़ा सागर और टोरड़ी आदि के ३-४ बड़े बन्धे हैं वे बराबर इसको पानी देते हैं, लेकिन इस पानी से वह चीज़ नहीं है। इस चीज़ की आवश्यकता इसलिए हुई है कि वहां पर बोरिंग होकर यह सोचा जाय और जहां पानी की नीची सतह मालूम हो जाय तो बहुत उन्नति और उद्योग को बढ़ाने की परमावश्यकता रहती है।

मैं एक बात यह निवेदन करूंगा इस चीज़ पर कि यह समझा जाता है कि मैं स्वार्थपरता से अपने भू–भाग के वास्ते निवेदन करना चाहता हूँ, लेकिन यह बात नहीं है। बराबर एक प्रांत के अन्दर बैठ कर दुभांत होती है तो इस बात का ख्याल होता है कि इसमें फर्क क्यों होता है? आज १२ वर्ष से जोबनेर का एग्रीकल्चर कॉलेज चल रहा है। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर कॉलेज के अन्दर जितनी बिजली की आवश्यकता होती है, शायद ही दूसरी चीज के अन्दर इतनी आवश्यकता होगी। शहरों के अन्दर और शहरों के आसपास में बिजली वैसे भी उपलब्ध रहती है लेकिन यहां थोड़ा सा खेद होता है कि १२ वर्ष के बाद और १२ वर्ष के समय में आज तक वहां पर बिजली का प्रबन्ध नहीं हो सका है। मैं धन्यवाद दिये बिना भी नहीं रहूँगा कि इस वक्त पर वहां बिजली के वास्ते आयोजन हो रहा है तो इसके वास्ते हम देखेंगे कि कब तक और कैसे वह चीज़ उपलब्ध होती है और इसके वास्ते कितनी आवश्यकता है। इस चीज के वास्ते, बिजली की कमी के वास्ते उस भू-भाग के अन्दर काफी दिक्कत पैदा होती है और यह भी अर्ज करूंगा कि जिस समय ५,००० बीघा और १२५ कुएं इस क्षेत्र को दिये, वह क्षेत्र को दी हुई चीज है वह गवर्नमेंट के सुपुर्द हो गया, तो ५,००० एकड़ भूमि किसी एक जगह और वह भी पानी की प्रचुर मात्रा में मिलना किसी इन्स्टीट्यूशन के वास्ते कठिन चीज है। इसका जब यह सवाल आया और युनिवर्सिटी ने कमीशन भेजा और उस कमीशन ने यह कहा: "Few agricultural colleges in India and few in the world have such extensive potentialities which can be found in Jobner."

तो मैंने अर्ज किया कि उन चीजों की पोटेन्शियेलिटी और साधनों को एवेल किया जाता, वहां के लिए आयोजन किया जाता तो वहां पर जो प्रचुरमात्रा में पानी मिलता है

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

तो उसकी तरक्की होती। मैं किसी भी संस्था की तरक्की करने के खिलाफ नहीं हूँ। राजस्थान में दो ही तो गवर्नमेंट के कॉलेजेज़ हैं। पंजाब और यू० पी० में यह सारी एल्यूवियल साइल है और बराबर एक ही मोनोटोनी है। लेकिन यहां राजस्थान में इंच इंच के बाद मोनोटोनी कटती है। यहां इस जगह कई चीजें इस तरह की हैं कि उसका बढ़ावा हो। इन साधनों के साथ में फर्क करना पड़ेगा। यह देखा जाय तो राजस्थान में दो तरह की ज्यादा जमीनें हैं। एक ब्लैक कॉटन स्वाइल है और दूसरी सेन्डी स्वाइल या सेन्डीलूम है। यह देखा जाय कि १।३ हिस्सा जो राजस्थान का वह ब्लैक कॉटन सोइल का है, वह मेवाड़, कोटा, बूंदी व सवाई माधोपुर में है। दूसरा हिस्सा जो है वह इस प्रकार का है जो सेण्डी सोइल का हिस्सा है। यह बीच के हिस्से के अन्दर यह स्थिति है तो बाज दफा जैसा कि मैंने कई दफा अर्ज किया है, मेरी इस बात की शिकायत नहीं है किसी इन्स्टीट्यूशन के वास्ते यह चीज हो कि वहां युनिवर्सिटी स्थापित की जाय अगर उदयपुर और दूर भी युनिवर्सिटी हो....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इलेक्ट्रिसिटी का है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इलेक्ट्रिसिटी और इसमें थोड़ा ही फर्क है। एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए इस चीज की सबसे पहले जरूरत होती है। मैं इस बात के वास्ते अर्ज कर रहा था कि मैं ज्यादा अच्छा समझता हूँ। मैंने थोड़ा बहुत इसी विषय में, एज्यूकेशन के विषय में और ज्यादातर एग्रीकल्चर एज्यूकेशन के विषय में थोड़ा अनुभव भी मैंने प्राप्त किया है....

श्री उपाध्यक्ष : विशाल अनुभव है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह तो नहीं है महाराज; लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि देखने के वास्ते वहां पर कोई जाते नहीं हैं। लेकिन, खैर, छोड़ा जाय लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा....

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : आपने लोगों को इन्वाइट नहीं किया, नहीं तो जाते।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने खर्चे पर जाइये ना।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : जिस वक्त आप मिनिस्टर थे, डिप्टी फाइनेन्स मिनिस्टर थे, उस वक्त भी नहीं पधारे।

लेकिन बात यह है कि वहां पर पॉवर मिलने की आवश्यकता है। अगर वहां पर पॉवर मिलती है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि चारों तरफ के हिस्से के जो काश्तकार हैं उनको भी बराबर का भाग दिया जाय। टाउन के लिए भी बिजली का प्रावधान हो गया है, संस्था के वास्ते भी हो गया है लेकिन बाहर के हिस्से में काश्तकार हैं, काफी कॉलेज की जमीन है और दूसरी जमीन की भी प्रचुरता है वहां यह होता है कि वहां अगर कोई ले जाना चाहे तो बिजली को अपने तरीके से ले जा सकता है या व्यवस्था कर

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

सकता है। तो मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे तो वहां जरूर पधारें, दूसरे मिनिस्टर्स ने तो कभी वहां पधारने का कष्ट नहीं किया। माननीय सदस्य कहीं यह न सोच लेवें कि मैं राजपूत हूँ और मिनिस्टर महोदय भी राजपूत हैं इसलिए पधारने का कह रहा हूँ........

श्री उपाध्यक्ष : दावत देने का काम तो चेम्बर में हो जाय।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : एक माननीय सदस्य ने फरमाया था, राजपूत लोइन शेयर ले जाते हैं लेकिन यहां लोइन शेयर का सवाल नहीं है........

डॉ० बहादुरसिंह : आज फर्स्ट अप्रेल है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : खेती न की जाय। खैर, इस चीज को छोड़ दिया जाय, अप्रासंगिक चीज है। वहां जो साधन उपलब्ध हो रहे हैं, उन्हें पहले सुभीता दिया जाय। कम से कम एक हजार बीघा कॉलेज की जमीन ऐसी है जिसमें शुगर केन, राइस और कुष्टा हो सकता है........

श्री चन्दनमल वैद : कुष्टा क्या होता है ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : कुष्टा सण को कहते हैं। कुष्टा यहां बराबर पैदा हो सकता है। शायद बंगाल और आसाम में ६ महीनों तक पानी पिलाने की जरूरत रहती है लेकिन यहां इतनी जरूरत नहीं है........

श्री उपाध्यक्ष : I am on this side, Sir.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह: माननीय मन्त्री महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय हैं वे भी जाकर देखने की कृपा नहीं करते हैं। खैर, यह बात तो हुई सो हुई। इसके अलावा बाड़मेर का इलाका है वहां दी जाय। बाड़मेर और दूसरे इलाके हैं वहां भी दी जाय। ये जिन्दा सुबूत हैं, वैसे जिस जाति में मैं पैदा हुआ हूँ और जो प्रोफेशन रहा है, यह स्वार्थी तबका नहीं होता है। हम नहीं चाहते हैं कि स्वार्थी रह कर हम पहले ले जाय। जो सबसे ज्यादा दुःखी हैं उनको पहले पिलाया जाय। एक तरफ देखा जाय तो मंत्री महोदय को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रहूँगा। वे किसी प्रकार इस चीज को करें। अब भी समय साल भर का है। तो यह बार बार सवाल उठता है कि आज इतना अनाज पैदा होता है, इतना सुभीता होते हुए भी तीन सेर या ढाई सेर से अधिक भाव नहीं बढ़ रहे हैं। सप्लाई और डिमान्ड का सवाल है, जिसके लिए सिवाय काश्तकारी के अलावा गरीब तबका त्राहि-त्राहि करता है। इन सब चीजों को सोचते हुए सबसे पहले सिटी वाले बड़े भाई छोटे भाइयों के लिए यह कह देंगे कि पहले छोटा भाई खाये, हम बाद में खा लेंगे। यह कह कर मैं माननीय........

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मन्त्री महोदय

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

से निवेदन करूंगा कि वे जल्दी से जल्दी इस सवाल को हल करें । दोनों–तीनों उपयोगी डिपार्टमेन्ट्स आपके ही पास हैं; तो इसके लिए जरूर कुछ होना चाहिये ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक बार सारे बजट को पढ़ा । कुछ आंकड़े देखे शायद ठीक तरह से नहीं कह सकता, लेकिन यह मालूम होता है कि राजस्थान में आप इतने बिजलीघर चलाते हैं, उनसे आपको मुनाफा होता है या नहीं । मैंने सारे आंकड़े देखे और रिपोर्ट देखी तो मालूम हुआ कि आपके जितने बिजलीघर चलते हैं उनमें घाटा उठाते हैं । सवाल यह है कि हमारे पास दो–तीन साधन हैं; जैसे ट्रान्सपोर्ट, बिजली, रेवेन्यू जिनसे हमको रेवेन्यू होती है या नहीं । एक बात यह हो सकती है कि हम नया काम ले रहे हैं । लेकिन मैं कहूँगा कि पाली का बिजलीघर है, उसका जो मैनेजमेन्ट है उसको मुनाफा होता है और जो शेयरहोल्डर्स हैं उनको दो-तीन साल में मुनाफा के तौर पर बोनस मिलता है । मैंने यह देखा है कि जितने बिजलीघर आप चलाते हैं और जितने साधन आप काम में लाते हैं उन साधनों को काम में लेने के बाद भी क्या बिजली विभाग सरकार को कुछ आमदनी देता है, जब कि हम इस विभाग को सरकार को रेवेन्यू देने का साधन बनाते हैं ट्रान्सपोर्ट और रेवेन्यू विभाग की तरह ? आपने जो अपना बजट पेश किया है उसमें एक्सपेन्डीचर ही एक्सपेन्डीचर बताया है, २७४.३२ लाख का खर्चा बताया है, इन्क्लूडिंग डेप्रिसिएशन अमाउन्ट; २७४.३२ लाख और आपने जो आमदनी बताई है उससे मालूम होगा कि आप कितना नफा उठा सकते हैं । मैं यह समझता हूँ कि मैंने कुछ जगह के....

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मन्त्री): इन्कम २०३.७९ लाख है ।

श्री मूलचन्द डागा : फिर भी आपको ज्यादा लाभ नहीं है । एक पॉवर हाउस में मेनेजिंग एजेन्ट्स काम करते हैं उनके जो शेयरहोल्डर्स हैं उनको मुनाफा मिलता है और आपके इतने पॉवर हाउसेज़ में मुनाफा क्यों नहीं मिलता है ? हम चाहते हैं कि मेनेजिंग एजेन्ट्स को खत्म किया जाय, बीच के लोग नहीं हों । मैंने पहले भी कहा था कि पाली औद्योगिक क्षेत्र बनता जा रहा है, केन्द्रीय मन्त्री श्री मनुभाई शाह ने भी इसकी तारीफ की थी । पाली के लोग अपने छोटे छोटे उद्योग बना रहे हैं लेकिन वहां पर थरमल पॉवर स्टेशन नहीं होने से, बिजली नहीं होने से, कुछ काम नहीं कर सकते । पाली, रानी, फालना आदि ऐसे स्थान हैं जहां उद्योग पनप सकते हैं........

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : पाली में बिजली की रेट क्या है ?

श्री मूलचन्द डागा : साढ़े नौ आने प्रति युनिट ।

श्री चन्दनमल वैद : लाइट एण्ड फ्यूल के लिए ?

श्री मूलचन्द डागा : जी हां । साढ़े नौ आने पर युनिट देने पड़ते हैं । मैंने कई

(श्री मूलचन्द डागा)

बार कहा कि आप आखिर करते क्या हैं ? पाली ऐसी जगह है जहां बिजली की बहुत आवश्यकता है। आप बिजली ऐसी जगह दीजिये जहां उत्पादन हो सकता हो। पाली डिस्ट्रिक्ट में फालना, रानी, पाली आदि चार औद्योगिक बस्तियां बस गई हैं जहां लोगों ने अपना इन्वेस्टमेन्ट किया है, सरकार की तरफ मुंह नहीं देखा है, लेकिन उनके विकास में दिक्कत है क्योंकि वहां बिजली नहीं मिल रही है। दूसरी जगह तो बिजली आई है, लेकिन पाली जिले में नहीं आई है। मैंने कई बार कहा कि पाली के बिजली-घर को आप लीजिए और उद्योगों को बिजली देने की व्यवस्था करनी चाहिये। पाली में पेकर्स प्रोग्राम १५ करोड़ रुपयों की लागत की योजना बन रही है लेकिन बिजली के बिना बड़ी भारी दिक्कत है। हम पानी कूओं से खींचना चाहते हैं और उपज बढ़ाना चाहते हैं, उद्योग स्थापित करके राजस्थान को मालोमाल करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि आपको कुछ दें, लेकिन आप उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप छोटे छोटे शहरों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कीजिए........

(२. म० प०)

लेकिन पहले जो हमें प्रायोरिटी देनी है वह देनी है पाली जिले को। सरकार पन्द्रह करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है, ज्यादा औद्योगिक बस्ती बनाने जा रही है, बस्तियां बनाई जा रही हैं तो उसके लिए प्रायोरिटी देने की आवश्यकता है। मैंने बताया आपको कि बिजली घरों में सबसे बड़ी बात यह है....

श्री चन्दनमल बैद : औरों को वोट नहीं लेने हैं, आपको ही वोट लेने हैं।

श्री शंकरलाल (रायपुर): वोट के आधार पर बात नहीं करते हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : पाली से आप भी आते दिखते हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : जी हां।

श्री मूलचन्द डागा : एक बात यह मैंने रखी....

श्री श्रीभानसिंह : पाली में पानी आ रहा है ?

श्री शंकरलाल : भीलवाड़ा में पानी आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : Don't feel yourself disturbed.

श्री मूलचन्द डागा : मैंने यह देखा कि अभी माननीय मंत्रीजी ने एक बात बड़े ढंग से कही, उन्होंने बार बार कहा, भाषण में चार बार कहा होगा कि हम सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं, हम समाजवाद बनाना चाहते हैं। मुझे इस बात को सुन कर बहुत खुशी हुई, आपकी भावना बिल्कुल ठीक है। लेकिन बजट में आप ३१ पेज पर देखिये। जो फिटर्स और और लोग काम करते हैं उनके लिए आप खर्चा क्या करते हैं ? आप कहते हैं, लेबरर्स के लिए काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ आप मशीन मंगा रहे हैं, उसके लिए रुपया खर्च

(श्री मूलचन्द डागा)

कर रहे हैं। ऑफिसर्स को लोन दे रहे हैं, कन्वेयेन्स के लिए लोन दे रहे हैं। मुझे यह बतायें कि आपने कितने मजदूरों को लोन दिया है और कितनों को लोन देने के लिए आपने उसमें व्यवस्था की है ? मुझे बतायें कि फोर्थ क्लॉस सर्वेन्ट का एक पैसा भी बढ़ाया है ? क्या उनकी तनख्वाह बढ़ा दी है ? फिटर्स की तनख्वाह २५-१-४० है। वहां जो काम करता है उसकी तनख्वाह वही की वही है। उसमें डिस्पेरिटी कितनी है ? वहां इन्जीनियर काम करता है, टैक्निशियन काम करता है। जो मजदूर है उससे काम ज्यादा लेते हैं। वे अपनी जिन्दगी को जोखम में डाल कर, खतरे में डाल कर खम्भों पर चढ़ कर काम करते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह क्या है ? आपने क्या किया है ? आपने एक लाख रुपया वैलफेयर बोर्ड के लिए खर्च करने के लिए मांगा है, लेकिन आपने खर्च क्या किया ? आप देखेंगे कि कुछ भी खर्च नहीं किया है। लोन्स एण्ड एडवान्सेज़, अदर आइटम्स, एमेनिटीज़, फॉर वैलफेयर ऑफ लेबरर्स, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज़, मेरी समझ में बिल्कुल खर्चा नहीं किया है। आपने ३०,४०० रु. एस्टेब्लिशमेंट के लिये रखा है १९६०-६१ के अन्दर। जब लेबर एण्ड वैलफेयर का सवाल आता है, ज्यादातर....

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मंत्री) : आपका क्या इन्टरप्रिटेशन है, यह बता दीजिये सोशियलिज्म का ?

श्री मूलचन्द डागा : जी ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपका क्या इन्टरप्रिटेशन है....

श्री शंकरलाल : क्या इन्टरप्रिटेशन है सोशियलिज्म का ?

श्री मूलचन्द डागा : जो टैक्निशियन्स काम करते हैं उनकी तनख्वाह में बढ़ोत्तरी होनी आवश्यक है। जो फिटर्स हैं, जो खूब काम करते हैं, जिनको आप इन्जीनियर बताते हैं उनकी तनख्वाह वही है। आप कहते हैं कि लेबर वैलफेयर के लिए आप लोन दे रहे हैं। हमने देखा है कि ४०,००० रुपया रखा है, कन्वेयेन्स के लिए लोन के लिए दो लाख, डेढ़ लाख रखा है कर्मचारियों के लिए अच्छे मकान बनाने के लिए लोन के लिए। मैं समझता हूँ कि फोर्थ क्लॉस गवर्नमेंट सर्वेन्टस हैं, जिनकी संख्या तीन गुनी कम कर दी है। आपके बजट से मालूम होता है, जहां १०० थे वहां ३३ रख दिये हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए सुविधा के लिए जो बजट रखा था उसमें एक पैसा भी रखा है ? एटेब्लिशमेंट चार्जेज़ के लिए खर्चा नहीं हुआ। बिजलीघरों की आये दिन हड़ताल होती है। पाली में एक मजदूर ने क्या काम किया, जब फंक्शन हो रहा था तो आधे घंटे के लिए ठीक टाइम पर बिजली बन्द कर दी। मैं प्रोटेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से। तो जो मजदूर को पगार मिलती है, जो काम वे करते हैं, उसको देखते हुए उसमें बढ़ोत्तरी करनी पड़ेगी। आप उनके वैलफेयर का काम करते हैं तो क्या काम आपने किया, आप बतलायें। मैं कहता हूँ कि रिपोर्ट....

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि पाली में बिजलीघर

(श्री चन्दनमल वैद)

प्राइवेट है। अब कह रहे हैं कि सरकार ने बिजली बन्द करा दी।

श्री मूलचन्द डागा : मैं जानता हूँ कि माननीय मंत्री की आप वकालत कर सकते हैं, माननीय मंत्री की वकालत करते हुए मैंने कई दफा देखा है; पर वे सोचें, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो मजदूर काम करते हैं बिजली घरों में, जो अपनी जान को जोखम में डालते हैं उनकी तनख्वाह में बढ़ोत्तरी नहीं की जाती है, उस हालत में पूरी नहीं की जा सकती है, जब कि सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को कायम करना आपका उद्देश्य है। वह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब उनके पास ज्यादा पैसा हो, उनको पैसा ज्यादा लेने का हक है; यह भावना जब तक नहीं जमती है तब तक सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। आप देखें, जोधपुर में हड़ताल हुई, पाली में....

श्री श्रीभानसिंह : डिप्टी मिनिस्टर जोधपुर से हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह सवाल नहीं है, सवाल यह है कि वे लोग जानते हैं कि जो सुविधायें हमें मिलनी चाहिए वे नहीं मिलती हैं। इसलिए हमें दो बातें सोचनी होंगी। अगर हमारी आमदनी बिजली घरों से नहीं होती है, यह रिपोर्ट बताती है, यह क्यों है? यह रिपोर्ट है, मैं कहता हूँ, बहुत ठीक है। इसमें आपने एक आइटम बताया, जिसमें लिखा हुआ है, हमने लेबर के लिए यह काम किया। यह दस पेज या पन्द्रह पेज की किताब है, उसमें बताया है आपने। जो लेबर काम करते हैं उनको ये सुविधायें दी हैं। आप लाखों रुपयों का बजट बनाते हैं, आखिर इसमें मजदूरों की सुविधाओं....

श्री चन्दनमल वैद : करोड़ों का है।

श्री मूलचन्द डागा : करोड़ों का है, उसमें भी क्या कुछ अंश मजदूरों की भलाई के लिए रखा गया है? तो इसको देखना होगा। मुझे मालूम हुआ, मैंने इसके पांच-सात कागज देखे हैं, उसमें कहीं है कि मजदूरों के लिए इतनी धनराशि खर्च की है या मजदूरों को इतना लोन दिया है? आपने मकानों के लिए लाखों रुपया गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिए रखा, लेकिन किन किन मजदूरों को लोन मिला? अभी मजदूरों की हड़तालें हुई। जो फैक्टरी एक्ट बनाया है, उसका उपयोग क्या है? इतने लेबर लॉज हैं, उनका उपयोग क्या है? बिजली घरों के लिए बतायें कि आपने इतने मजदूरों के लिए लोन्स दिये हैं? आखिर मजदूर भी चाहते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उनको बोनस दें। किसी भी मजदूर को, जो बिजलीघर में काम करता है, आपने बोनस दिया है, मुनाफा दिया है, उसकी तनख्वाह में एक पैसे की भी बढ़ोत्तरी की है? आखिर वे भी काम करते हैं। मेरी अर्ज थी कि जहां तक बिजली की बात है, मैं समझता हूँ, कि चाहे भाखरा से आये, चाहे चम्बल प्रोजेक्ट से आये, बिजली आये और काम बढ़े। लेकिन सवाल यह है कि जहां बिजली नहीं दे सकेंगे तो जो उस एरिया के लोग हैं वे क्या करेंगे? आप चाहते हैं कि उत्पादन बढ़ना चाहिए। आप टार्गेट्स बनाते

(श्री मूलचन्द डागा)

हैं। औद्योगिक क्षेत्र बनाते हैं, लेकिन उन्हें बिजली उपलब्ध न हो तो क्या फायदा ? आज जो लोग बाहर से आते हैं, आप जिन लोगों का आव्हान करते हैं, बड़े बड़े सन्देश भेजते हैं वे लोग बाहर से आयें और औद्योगिक बस्ती में लाखों रुपया लगा दें और उनको बिजली नहीं उपलब्ध हो, तो आप बताइये वे क्या काम करेंगे ? तो सवाल यह है कि बिजली वहां देनी चाहिए जहां उसका फायदा उठा सकें। मैंने जन–लेखा समिति की रिपोर्ट १९५९–६० की पढ़ी। उसमें साफ लिखा है, सारे बिजली घरों में जो अनियमिततायें हुई हैं उनको सरकार के ध्यान में आये हुए करीब चार साल और जांच का कार्य प्रारम्भ किये हुए भी करीब एक साल का समय हो चुका है; किन्तु अब तक समिति को यह सूचना नहीं मिली है कि इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है या नहीं और यदि निर्णय लिया गया है तो क्या ? उन्होंने यह लिखा है । उसके अलावा रिपोर्ट पढ़ी। १९५८–५९ की रिपोर्ट है, उसमें जो अनियमिततायें बताई हैं उन सब बातों की डिटेल्स में जायें तो मालूम होगा कि हर बिजली घर में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। जन लेखा समिति की १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८–५९ की रिपोर्ट पढ़ें तो उससे मालूम होगा कि बिजली घर में कितनी अव्यवस्था है। उसका कारण क्या है ? एक बनिया या एक महाजन एक बिजली घर चलाता है। मैं समझता हूं कि कम से कम मुनाफा बचा सकता है। आपके कितने बिजली घर चलते हैं ? राजस्थान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बिजली घर ले लिये हैं –फलोदी का बिजली घर ले लिया है, भवानी मंडी का ले लिया है, आपने सब बिजली घर ले लिये हैं अपने कब्जे में....

श्री चन्दनमल वैद : पाली का नहीं लिया है।

श्री मूलचन्द डागा : पाली का नहीं लिया है। उसे मैनेजिंग एजेन्ट काम करते हैं वे कमाते हैं, दस हजार का भत्ता मिलता है। कहां गये थे, बम्बई गये थे। क्या करने गये थे, एंजिन खरीदने गये थे। फिर भी मुनाफा कमाते हैं । जो मैनेजिंग एजेन्ट मुनाफा कमाता है वह बम्बई जाता है, पैसा लेता है। मीटिंग करते हैं और कुटुम्बी मैनेजिंग एजेन्ट बन जाते हैं और मुनाफा लेते हैं। आपने जो बिजली घर कब्जे में लिये हैं उनमें फायदा नहीं उठाते। आखिर हमें इन बातों पर सोचना होगा। मैं चाहूंगा, जब कभी विवरण दिया जाय तो यह बताया जाय कि बिजली घरों इतना में काम हुआ है, इतना बिजली घरों में फायदा हुआ है। जो आंकड़े आते हैं उनमें टोटल बता देते हैं, जैसे कृषि में होता है, इतना अनाज बढ़ गया। लेकिन जब प्रति एकड़, प्रति बीघा देखते हैं तो आमदनी कम मालूम होती है। राजस्थान के आंकड़ों से मालूम होता है कि बहुत खाद्य उत्पन्न कर दिया, लेकिन आंकड़े कम होते हैं। हम चाहते हैं कि इतने बिजली घर लेने के बाद में आपको मुनाफा बतलाना चाहिए था, लेकिन आप मुनाफा नहीं बतलाते हैं, आपका खर्चा बढ़ रहा है। सवाल यह है, मैं इन बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपके बिजली घरों की व्यवस्था है उस पर कुछ अंकुश तेज करना

(श्री मूलचन्द डागा)

होगा और लेबर की ओर ज्यादा ध्यान देना होगा। आप बतायें कि कितने मजदूरों को बोनस दिया, कितनी तनख्वाहों में बढ़ोत्तरी की है ? आप उनको तनख्वाह देते हैं ४० रुपया, जो स्टोर कीपर है, जिसके पास सारा सामान रहता है, लेबरर्स के काम का सारा सामान, फावड़े, तगारी वगैरह जिसके पास रहता है उस स्टोर कीपर को तनख्वाह देते हैं ४०) रुपया वे चेयरमैन को तनख्वाह देते हैं ढाई हजार। जिसके पास इतना सामान है जिसके ऊपर रेस्पोन्सिबिलिटी है उसको आप केवल ४०) रुपया देते हैं, यह उचित नहीं है।

मैं यही बताना चाहता था कि हम इन बातों पर विचार करें।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री माथुर !

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष, हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये जैसा कि पूरा पूरा मन्त्री महोदय ने बताया है ४५ करोड़ की धनराशि थी, वहां कटौती का प्रभाव हुआ और वह घट कर ३३ करोड़ रह गई। और किसी विभाग में कटौती होती तो विशेष दुःख की बात नहीं थी, पर जिस विभाग को हमारी भावी योजनाओं का आधार बनाया है उस विभाग में कटौती की है तो इससे स्पष्ट यह अर्थ लगाया जा सकता है कि इस विभाग के कार्यकर्त्ता, अधिकारी इस प्रकार का कार्य नहीं कर सके जिससे कि लोगों के दिलों में यह भावना घर कर जाय कि यह विभाग अच्छी तरह कार्य कर रहा है। अतः इसमें कटौती नहीं होनी चाहिये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वयं मन्त्री महोदय के कहने के अनुसार कोई उल्लेखनीय प्रगति इसके कार्य में दिखाई नहीं देती है। आज एक पुस्तिका सदन में बांटी गई है जिसका नाम है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड; राजस्थान में पॉवर की तरक्की, उसमें यह दिखाया गया है कि ५३ ऐसे कस्बे हैं जहां भाखरा से आई हुई बिजली दी है। मेरी यह मान्यता है कि इसका श्रेय बोर्ड को नहीं है क्योंकि इनमें से ३।४ कस्बे ऐसे हैं जहां ऑल-रेडी बिजली थी। तो उसमें श्रेय इस विभाग को नहीं, वहां, पहले से ही बिजली थी, पहले पॉवर हाउसेज़ चलते थे उनको बन्द कर दिया है और उनके स्थान पर भाखरा की बिजली देना शुरू कर दिया है नये कितने स्थानों पर भाखरा की बिजली दी है ? नये स्थानों में आपने बिजली दी हो वह उल्लेखनीय है, ज्यादा, और और स्थानों के लिये तो मैं नहीं कह सकता पर मेरे जिले के, मेरे आसपास के जो स्थान हैं उनके बारे में मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ जिनके लिये पुस्तिका में लिख दिया है कि उन कस्बों में अक्टूबर से बिजली दे दी है। इसमें लक्ष्मणगढ़ के लिये लिखा गया है कि अक्टूबर से बिजली दे दी है, पर वास्तविक स्थिति यह है कि लक्ष्मणगढ़ में पिछले महीने में सारे कस्बे में केवल एक बल्ब जलता था, जब कि लक्ष्मणगढ़ के लिये इस पुस्तिका में कह दिया गया है कि अक्टूबर में बिजली दे दी गई। तो इस तरह गलत सूचना दी गई है विभाग की ओर से। कहा गया है कि फतहपुर में बिजली दे दी है, वहां पर भी

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

एक बल्ब जलता है। ऐसी दशा में इस विभाग को इसके लिये किसी तरह का श्रेय दिया जाय, यह गलत बात है।

भाखरा से ४,६०० किलोवाट बिजली दी गई है उसका उपयोग आज तक हम ठीक ढंग से नहीं कर पाये हैं। इसका कारण यह है कि ट्रान्समीटर लाइन ठीक तरह से नहीं बिछा पाये हैं। ११,००० किलोवाट बिजली और मिल रही है, इसका भी हम ठीक तरह से उपयोग नहीं कर सकेंगे क्योंकि लाइनें ठीक नहीं हैं। इस ६१-६२ में बताया गया है कि ११ हजार किलोवाट बिजली हमें और मिलने वाली है। इसका भी उपयोग विभाग आने वाले वर्ष में कर सकेगा, इसमें शक है। इसका कारण यह है कि हमारे विभाग के पास कोई योजना नहीं है, पूरी लाइनें तैयार नहीं हुई हैं। ऐसी दशा में पंजाब से, भाखरा से जो बिजली आने वाली है उसका उपयोग कर सकेगा, इसमें शक है।

चम्बल के लिये लिखा है कि इतनी बिजली मिली और इतनी बिजली ६१-६२ में और मिलने वाली है, पर इसके उपयोग के लिये भी लाइन वर्क अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कोटा–सवाई माधोपुर लाइन तैयार नहीं है, जब तक टॉवर नहीं बनेंगे, लाइन तैयार नहीं होगी; तब तक इस बिजली का भी यह विभाग पूरा उपयोग नहीं कर सकेगा। इसका मतलब यह है कि इस विभाग को जो धनराशि दी है उसका यह विभाग पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सका है। यही कारण है कि इसके खर्च में, इसके बजट में कटौती की गई है।

प्लानिंग एडवाइज़री कमेटी ने भी इस विभाग की इसीलिये आलोचना की है। हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में उत्पादन बढ़ाने के लिये बिजली का उपयोग करना चाहते थे, घरों में लाइट लगा देना, गलियों में, स्ट्रीट्स में लाइट लगा देना, इसको हम सही माने में बिजली का उपयोग नहीं मानते। इसके लिये हम नहीं कह सकते कि बिजली का सही माने में उपयोग किया गया है। बिजली का सही माने में उपयोग करना तो उसी दशा में कहा जा सकता है जब कि गांवों में औद्योगीकरण के लिये, कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये बिजली दी जाय, छोटे छोटे उद्योगों के लिये, गांवों में उत्पादन बढ़ाने के लिये बिजली दी जाय। बिजली की उपयोगिता का सही मापदण्ड यही है कि कितनी बिजली हम गांवों को औद्योगीकरण के लिये दे सके हैं। प्लानिंग कमीशन ने इस विभाग को लतेड़ा था कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यहां तक तो असफल रहा है। तो आखिर इस हिसाब से इस विभाग पर खर्चा कर रहे हैं उसका रिटर्न नहीं दिखाई देता है। इसके लिये एक ही निर्णय हो सकता है कि विभाग के बजट में कटौती की जाय और वही किया गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसमें कटौती की गई है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि विभाग अपने कार्य में असफल रहा है।

मन्त्री महोदय ने हमें पहले बताया था कि सारे प्रान्त में जो बिजली आयेगी उसको एक जगह एक्युमुलेट करके समान दरें सब जगहों के लिये करेंगे, पर अभी तक हमारा यह विभाग समान दरें करने में असफल रहा है। बिजली जयपुर को मिले या जोधपुर को, बीकानेर को मिले या उदयपुर को, किसी को

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

भी मिले पर सब जगह दरें समान होनी चाहिये, सारे खर्च को जोड़ कर केल्कुलेशन निकाल कर सब जगहों के लिये समान रूप से दरें मुकर्रर करनी चाहिये, यह हमारा विभाग आज तक नहीं कर सका है।

इसके बाद मुख्य बात यह है कि भाखरा से, चम्बल से हमें बिजली मिलने वाली है वह हमें सीमित बिजली मिलेगी। उसका ज्यादा एक्सपेन्शन नहीं कर सकते तो हमारे प्रान्त के अधिकांश क्षेत्र हैं वहां पर यह बिजली नहीं पहुंच सकेगी। दो नये थर्मल पॉवर हाउसेज़ आप कायम करने वाले है। उनसे राजस्थान की कमी पूरी नहीं हो सकती। पंजाब में, देहली में और उन स्थानों में जहां भाखरा, चम्बल से ज्यादा बिजली मिल रही है, वहां अणु शक्ति का उपयोग, अणु-शक्ति से बिजली बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। थर्मल बिजली के लिये टर्बाइन्स आदि खरीदने के लिये फोरन एक्सचेन्ज पर आधारित रहना पड़ता है, पर हमारे राजस्थान में ऐसे खनिज पदार्थ बहुतायत में हैं जो कि अणु शक्ति के उत्पादन के उपयोग में आ सकते हैं। जिस दृष्टि से राजस्थान में मिनरल डेव-लपमेंट हो रहा है, तांबे की खान खेतड़ी में दिखाई दी है जो हिन्दुस्थान की सबसे बड़ी खान होगी, इसके लिये बिजली का प्रबन्ध नहीं किया है और इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है। खेतड़ी की इतनी बड़ी खान है वहां ज्यादा अणु शक्ति की बिजली पैदा करने के लिये प्रयास करें तो स्मेल्टिंग प्लान्ट भी खेतड़ी में लगा सकते हैं। इन उद्योगों के लिये भी बिजली नहीं मिल सकेगी।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मन्त्री): आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या फर्मा रहे हैं, जरा धीरे बोलें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : खेतड़ीकी तांबे की खान है, उससे सम्भावनाएं हैं। वहां यदि अणुशक्ति का बिजली घर कायम करें तो अधिक उपयोग हो सकता है।

इस दृष्टि से अब तक खेतड़ी में जहां तांबे की खान है उसका किस प्रकार से विकास होगा, इस बारे में विभाग के पास कोई योजना नहीं है। वहां अगर बिजली नहीं दी गई, बिजली का प्रबन्ध नहीं किया गया तो खेतड़ी से जितना तांबा निकलता है वह सब बाहर एक्सपोर्ट होगा।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जब ओपनिंग स्पीच दी थी उस समय पोज़ीशन को क्लेरि-फाइ कर दिया था, शायद आप उस समय थे नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : खेतड़ी के बारे में कुछ कहा था, लेकिन अणु शक्ति के आधार पर आप वहां क्या करने जा रहे हैं इस सम्बन्ध में आपने कुछ भी नहीं किया और न कहा। आपने तो सिर्फ तांबे की खानों के सिलसिले में कहा था। मैं अणु शक्ति के बारे में निवेदन कर रहा हूँ।

श्री बरकतुल्लाखां (उप-मंत्री विद्युत) : मैं माननीय सदस्य को निवेदन कर दूं, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्तर्गत अणुशक्ति नहीं आती है। इसका ताल्लुक राजस्थान सरकार से नहीं है, भारत सरकार

(श्री बरकतुल्लाखां)

से हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को इम्प्रेस किया है हमारे यहां एटोमिक पॉवर स्टेशन होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को इम्प्रेस आप अधिक शक्ति के साथ करें, यही माननीय सदस्य का निवेदन है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को आपने प्रेस किया है लेकिन एटोमिक स्टेशन कहां स्थापित किया जायेगा, इस संबंध में मेरा आग्रह है कि वह खेतड़ी के आसपास किया जाय।

श्री बरकतुल्लाखां : यह तो भारत सरकार तय करेगी कि वह कहां लगा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान सरकार से सुझाव मांगेगी। उसमें आप खेतड़ी का नाम बता दें।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : श्रीमाधोपुर के लिये नहीं ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : खेतड़ी में लगाने के लिये मेरा इसलिये आग्रह है कि वहां तांबा प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। अगर वहां स्मेल्टिंग प्लान्ट वगैरह नहीं होता है तो तांबा बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। राजस्थान का जहां हम इन्डस्ट्रियल डेवलंपमेन्ट करना चाहते हैं वहां हमारे लिये आवश्यक है कि हमें खेतड़ी की तांबे की खानों की ओर भी ध्यान देना होगा। राजस्थान का इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट खेतड़ी की तांबे की खानों पर ज्यादा निर्भर है। वहां यदि हम बिजली की शक्ति नहीं देते हैं तो हमें वहां से तांबा बाहर एक्सपोर्ट करना होगा। नहीं तो हम वहां पर स्मेल्टिंग प्लान्ट लगा सकें तो जितने ताम्बे का उत्पादन होगा उसका सारा का सारा प्रोसेस वहां हो सकेगा। राजस्थान का हम विकास करना चाहते हैं तो हमें एटोमिक स्टेशन की यहां स्थापना करनी होगा। मेरा आप से निवेदन है कि आप इसके लिये शीघ्रातिशीघ्र सैंक्शन दें और भारत सरकार पर विशेष रूप से जोर डालें और उसमें आप लोकेशन खेतड़ी के लिये दें।

अब मैं बिजली के उपभोग के बारे में कहना चाहूँगा। हमें इसमें भी लाइन बिछाने के काम में प्राथमिकता देनी चाहिये। लाइन बिछाने का काम नहीं किया तो बिजली हमें मिल नहीं सकेगी और किसी प्रकार से बिजली का उपयोग नहीं हो सकेगा। केवल घरों में कुछ रोशनी दे दें या स्ट्रीट लाइट दे दें, इसे इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट नहीं कहा जा सकता। हम देखते हैं, बिजली की खपत हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नहीं हो रही है। उसमें सरकार असफल रही है। विभाग की इस बारे में तत्परता कितनी है, यह तो इसी बात से पता चल सकता है कि सन् ५० से जयपुर से लाइन बिछाने का काम था, लेकिन चौमूं से वह आगे नहीं बढ़ रहे हैं। रींगस, श्रीमाधोपुर, नीम का थाना वहां तक पहुंचाने की सरकार की योजना थी, लेकिन सात, आठ वर्ष हो गये अभी तक केवल खम्भे ही खम्भे खड़े हैं, उस पर लाइन नहीं पड़ती। शायद

Page No 69

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

सरकार श्रीमाधोपुर में बिजली इसलिये भी नहीं पहुंचाना चाहती होगी कि वहां से दो दफा भी जो माननीय सदस्य आये वे विरोधी दल के थे और इस बार आने वाले माननीय सदस्य सरकार के आलोचक हैं इसलिये भी सरकार श्रीमाधोपुर में बिजली की लाइन डालना नहीं चाहती होगी।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु.): बराबर पहुंचायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो इधर बैठते हैं, उधर कैसे पहुँच गये ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वह क्षेत्र हमेशा उपेक्षित रहा है क्योंकि दोनों चुनावों में उस क्षेत्र से विरोधी दल के सदस्य आये हैं। इसलिये माननीय मंत्री महोदय का ध्यान श्रीमाधोपुर की ओर नहीं गया। इसलिये वह उपेक्षित क्षेत्र है।

श्री बरकतुल्लाखां : श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य खुद ही अपना केस प्लीड कर सकते हैं उनको वकील की जरूरत नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मैं सवाई माधोपुर से नहीं आया हूँ, श्री माधोपुर से।

श्री बरकतुल्लाखां : मैंने भी श्रीमाधोपुर ही कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : शायद अब श्रीमाधोपुर से आने वाले सदस्य नहीं बोलेंगे।

श्री चन्दनमल वैद : पैरवी वकालतन हो रही है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसके अन्दर दो लाख रुपये का प्रावधान रखा है। इस प्रकार की योजना बनाई गई है कुओं के लिये। अगर हम उन कुओं के लिये बिजली दे देते हैं तो एग्रीकल्चरल आउट पुट अधिक हो सकता है। इससे अनाज की समस्या को सुलझाने में सहयोग मिलेगा। इसलिये निवेदन है कि इस तरफ लाइन डालने का कार्य प्रारम्भ करें ताकि वहां की जनता को इससे लाभ हो सके और अनाज के उत्पादन में वृद्धि हो सके।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एन्युअल फाइनेन्शियल स्टेटमेंट इस सदन में प्रस्तुत हुआ है उस पर राय देने की दृष्टि से कि बोर्ड का पिछले साल का पर्फोर्मेन्स कैसा रहा, इस पर हम विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पिछले साल का पर्फोर्मेन्स को नापने के लिये हमें उसके या उसके पिछले तीन, चार सालों के पर्फोर्मेन्स को कम्पेयर करके अन्दाज लगा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सेकन्ड फाइव इयर प्लान में स्टेट की जो प्रोग्रेस है उसके इलेक्ट्रिक सेक्टर की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जो किताब पब्लिश की गई है उसमें दिया हुआ है पेज नम्बर ४ पर:—

५६—५७ में	५५ लाख
५७—५८ में	८८ लाख

(श्री पी० के० चौधरी)

५८—५६ में	३. ३३
५६—६० में	२. १२
६०—६१ में	१०. ५७

यानी आउट ऑफ दी टोटल प्लान एलोकेशन ६० प्रतिशत जो हमारे सेकन्ड प्लान का पर्फोर्मेन्स रहा है वह करीब ८७ पर्सेन्ट एक्सपेन्डीचर की दृष्टि से पर्फोर्मेन्स रहा है। इस पर्फोर्मेन्स के अन्दर जब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपने हाथ में काम लिया, एक्सपेन्डीचर की काफी प्रोग्रेस हम देखते हैं। फुल स्विंग में बोर्ड का काम १६५८-५६ में शुरू हुआ। इससे पहले के एक्सपेन्डीचर के हम नॉर्मल सा रहा कह सकते है। प्लान्स स्कीम के अन्तर्गत ५८-५६ में ३. ३३ लाख और यह आगे जाकर ६०-६१ में जो इन्डीकेट करता है that the Minsiter in charge has also contributed to electrify the department.

क्योंकि मैं देख रहा हूं ६०-६१ का जो एक्सपेन्डीचर है वह पिछले चार सालों के एक्सपेन्डीचर से लगभग १७० पर्सेन्ट अधिक है।

Current year's expenditure is 170% more than the last four years expenditure.

मैं समझता हूँ सैकन्ड प्लान का पर्फोर्मेन्स अच्छा रहा है। इसके लिये मैं बोर्ड को जो उन्होंने पिछले साल के दौरान में किया उसके लिये मन्त्री महोदय को और बोर्ड के कर्मचारियों को, जिन्होंने इस स्टेट को इलेक्ट्रिफाई करने में सहयोग दिया, उनका धन्यवाद करता हूं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : डिप्टी मिनिस्टर साहब को नहीं।

श्री बरकतुल्लाखां (उप-मन्त्री, विद्युत) इन्डिवीन्युअल का नाम लेने से क्या ? श्री पी० के० चौधरी के दिल में क्या मोहब्बत है वह सब को मालूम है।

श्री पी० के० चौधरी : अब हम थर्ड प्लान में आते हैं। थर्ड प्लान में एलोकेशन है ३५ करोड़ का। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये स्टेट गवर्नमेंट का प्रोपोज़ल था वह लगभग २५ करोड़ का प्लानिंग कमीशन के सामने था। लेकिन इसमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और ट्रान्समिशन के लिए लगभग ३५ करोड़ रुपये का प्रावधान था उसमें से प्लानिंग कमीशन ने काटकर ६.६८ करोड़ रखा यानी अबाउट दस करोड़ के प्रोपोजल्स मन्जूर किये। उसी टाइम की बात है, प्लानिंग कमीशन ने जो ऑल इन्डिया टार्गेट रखा था इन्सटाल केपेसिटी ११।८ पर्सेन्ट फॉर होल दी कन्ट्री इसके बाद सेन्ट्रल वाटर पॉवर कमीशन ने प्लानिंग कमीशन को टार्गेट्स रिवाइज़ करने के लिये कहा था, थर्ड प्लान में कम से कम १४ मिलियन किलोवाट का होना चाहिये। उसी आधार पर मुझे ऐसा मालूम हुआ प्लानिंग कमीशन ने उनका जो एलोकेशन था उसको रिवाइज किया। और ११.८ की जगह पर आज १३.५ मिलियन किलोवाट किया है और प्रोपोर्शनेट इन्क्रीज़ के लिये किया है। तो मैं इस बात की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान

(श्री पी० के० चौधरी)

आकर्षित करना चाहता हूँ कि ऑल इन्डिया का टार्गेट लगभग १० प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे यहां का टार्गेट जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का है there must be a proportionate increase in it, a proportionate revision in it.

(२. ३० म. प.)

(श्री बी. एन. जोशी, सभापति, पदासीन)

तो इसलिये यह एलोकेशन ऑल इन्डिया पर बढ़ता है। पहले पब्लिक सेक्टर में ६२५ करोड़ था, अब इससे बढ़ कर ११०० करोड़ का कर दिया है। जब इसमें बढ़ोतरी हुई तो मैं समझता हूँ कि हमारे स्टेट के टार्गेट ५.३ करोड़ का रखा है उसमें भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ोतरी होनी चाहिये। प्रोप्रोर्शनेट इन्क्रीज नहीं हुआ लेकिन रीजनल डेवलपमेंट का दूसरों से राजस्थान के हिस्से में जो बढ़ोतरी हुई है उसके हिसाब से लार्जर प्रोपोर्शन आना चाहिये और इसलिये आना चाहिये कि आज राजस्थान के सन् १९५९-६० के फीगर्स एवेलेबल हैं उनके हिसाब से ट्रान्समिशन के लिये इन्सटाल्ड केपेसिटी per capita consumption comes to 3·97 units जब कि ऑल इन्डिया का उस समय का एवरेज कन्जम्शन था २३.८ युनिट्स ro something like that जहां राजस्थान का कन्जम्पशन १।४ या १।५ से भी कम आता है। इस दृष्टि से राजस्थान का पॉवर कन्जम्शन का शेयर है वह दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में ज्यादा हो सकता है और इस बेसिस पर हमारा प्लानिंग कमीशन से लार्जर शेयर इन दी एलोकेशन के लिये एप्रोच करना चाहिये।

जैसे पहले माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सोशियलिज़्म के लिये इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है। यह सही है और मैं, माननीय सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रीसिटी की इम्पोर्टेन्स के संबन्ध में पार्लियामेंट में भी प्राइम मिनिस्टर ने जब बजट का डिस्कशन हो रहा था तो दोहराया था कि material basis of socialism is electricity. आप पॉलिटिकल सोशियलिजम को, पोलिटिकल कन्सेप्शन की दृष्टि से एक रूप देना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम यह कह दें कि everything should be distributed equally, then poverty will be distributed. सोशियलिज़्म का मतलब यह है कि इक्वल डिस्ट्रिब्युशन के साथ साथ amenities of life, conditions of life, कितने आगे बढ़ते हैं और हम इम्प्रूव करते हैं। इसलिये लेनिन ने कहा था material basis of socialism is electricity. इस प्रकार १९१७ के रिवोल्यूशन में, in the year 1920 में, उन्होंने जो रिवीजन इस प्रकार किया था, जिस प्रकार आज हम प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पास करके करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने plan for electrification of all Russia, सारे रूस के लिये प्लान किया था, उसमें उन्होंने कहा था give me electricity and I will bring revolution to the hearths of Russian peasants. यानी वे यह मानते थे कि बगैर बिजली के हम चेन्ज इन दी मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं ला सकते और मजदूरों

(श्री पी० के० चौधरी)

के जीवन में प्रगति नहीं ला सकते । अगर हम मजदूरों में प्रगति लाना चाहते हैं तो हमें मोड ऑफ प्रोडक्शन को बदलना होगा। अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं बदलते हैं या कन्ज़म्प्शन नहीं बदलते हैं तो हम स्टैन्डर्ड ऑफ लिविंग में कोई चेन्ज नहीं ला सकते क्योंकि इस बात को सभी मानते हैं कि समाज में जो स्टैन्डर्ड ऑफ लिविंग होता है वह मोड ऑफ प्रोडक्शन पर ही निर्भर करता है । अगर हमें स्टैन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और इसके लिये change in the mode of production करना पड़ेगा और उसको बढ़ाना होगा। हम एग्रीकल्चर में यह न समझें कि केवल हल ही चलाना होता है । एग्रीकल्चर में modern methods of production adopt करने चाहिए । एग्रीकल्चर में जब तक इलेक्ट्रिसिटी एवेलेबल नहीं करते हैं तो कुएं जहां दो-दो चार-चार बैल पानी निकालने के लिये लगाते हैं उससे कहां तक प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं जब कि यदि इलेक्ट्रिसिटी हो तो वहां पर एक पम्प लगा कर काम कर सकते हैं । वहां पर एक क्रशिंग मशीन लगाकर ऑयल सीड या शुगर केन को क्रश कर सकते हैं । बिजली की मशीनों के द्वारा फसल खेतों में खड़ी होती है उसको काटने का भी काम कर सकती हैं । अगर देश के जीवन में सोशियलिज़म लाना है तो उसके लिये इलेक्ट्रिसिटी एक जीवन है, pivot है, मेन प्लैंक है, जिसको चाहे सोशियलिज्म कहिये या बैटर सोसाइटी कहिये इसलिये मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि ऑल इन्डिया बेसिस पर जो इन्क्रीज़ हुआ, उसमें से हिस्सा हमको भी मिलना चाहिये । मैं चाहूँगा कि माननीय मन्त्री इसके लिये कोशिश करेंगे ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो एलोकेशन हमने रखा था, इस साल हमारी जो प्लान्ड स्कीम है, उसका एलोकेशन है ऑल इन्डिया बेसिस पर, if I am not mistaken, रखा है; ४॥ करोड़ रुपया इस साल के बजट में हम राजस्थान पर शायद खर्च कर रहे हैं । तो ४॥ करोड़ का इस साल का बजट एलोकेशन है । सभापति महोदय, यह ४॥ करोड़ प्लान्ड स्कीम की दृष्टि से इन-एडीक्वेट है । वह इसलिये है कि यह प्लानिंग कमीशन ने तय किया है । हमारा फेजिंग कैसा हो ? उन्होंने यह प्रेस्क्राइब किया था । इसको आप तय करें । That is an average for including everything. इसको सोशियल सर्विस कहिये या कोई दूसरा कहिये, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कृषि के लिये बहुत इम्पोर्टेन्ट चीज़ है, जिसको हम बेसिक चीज़ मानते हैं । जब इसमें एलोकेशन होगा तो इसमें अन्दर प्लान्ड स्कीम्स जो हैं on the development of electricity; जैसे कि agriculture में electrically driven machines से water lifting है, आदि । ये सारे के सारे डेवलपमेंट हैं वे सब इस पर निर्भर करते हैं । The first condition is supply or availability of electricity. तो इस दृष्टि से मैं यह मानता हूँ कि ऑल इन्डिया का एलोकेशन में जो पर्सेन्टेज है वह ज्यादा होना चाहिये । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज १२.८ पर्सेन्ट ही आता है । वह १४.५ पर्सेन्ट भी नहीं आता, वह १२.८ पर्सेन्ट ही आता है ।

तो मैं इस बात की तरफ स्टेट इलेक्ट्रि-

(श्री पी० के चौधरी)

सिटी बोर्ड का और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि कम से कम जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी के लिये एलोकेशन हो, पिछली दफा जैसा सेकन्ड प्लान में हुआ उस समय ऐसी सर्कमस्टान्सेज़ रहीं, जो कुछ काम हुआ वह लास्ट थ्री ईयर्स में ही हुआ उसके हिसाब से कम से कम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एफर्ट्स यह रहने चाहिये कि हमारे जो प्लान के टार्गेट्स हैं पिछले साल के उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें, जितना जल्दी से पूरा करेंगे उतना ज्यादा we push the State ahead in development for two years. आज जो एलोकेशन हुआ है उसको पूरा करना, यह आपके एफर्ट्स पर निर्भर करता है whether you are in a position to push the State ahead जो फेज़ स्टेट डेवलपमेन्ट का रखा है उसके अनुसार हम चला सकें, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके लिये कम से कम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और माननीय मंत्री महोदय के एफर्टस होने चाहिये कि जो फन्डस का एलोकेशन है उसका जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करके टार्गेट्स को एक साल पहले,दो साल पहले अचीव कर लें। हमने रशिया में देखा है, चाइना में देखा है कि जो दस सालाना प्लान होते हैं वे सात साल में ही समाप्त कर देते हैं,जो सात साल के प्लान होते हैं उन्हें पांच साल में ही खतम कर दिया जाता है। तो हमें जहां तक उनकी अच्छी बातों का सम्बन्ध है,चाहे वह कम्युनिस्ट कन्ट्री की हो या फासिस्ट कन्ट्री की हो, जो भी उनकी अच्छी बात हो उसको एडॉप्ट करना चाहिये, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

Few minutes, Sir.

सभापति महोदय, अब मैं ६०–६१ का एक्सपेन्डीचर और ६१–६२ का एक्सपेन्डीचर इन दोनों का कम्पेरिजन करके कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। केपिटल बजट में ६०–६१ में राणा प्रताप सागर बांध के डेवलपमेन्ट के लिये पचास लाख रुपये का एलोकेशन था, लेकिन रिवाइज्ड में वह पांच लाख का कैसे हो गया ? ६१–६२ में इस साल का जो एलोकेशन रखा है वह ३० लाख का रखा है। मैं समझता हूँ, राणा प्रताप सागर बान्ध के लिये जहां पचास लाख रुपये का अलग एस्टीमेट रख सकते हैं तो इस साल के लिये कम से कम एलोकेशन होने चाहिए एट पार विथ दी प्रीवियस इयर। मैं इतना कह सकता हूँ कि जितना जल्दी राणा प्रताप सागर का डेवलपमेन्ट होगा उतना ही जल्दी उससे बेनीफिट्स मिल सकते हैं।

दूसरी बात, सभापति महोदय,जिसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह है एक्सपेन्डीचर आन डाइरेक्शन। इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। एक्सपेन्डीचर ऑन डाइरेक्शन है वह केपीटल बजट में अलग बताया गया है और रेवेन्यू बजट में अलग बताया गया है। अकाउन्ट्स की दृष्टि से यह ठीक हो सकता है, लेकिन सदन के माननीय सदस्यों के समझने के लिये हमको सब पिक्चर एक ही जगह मिल जाय, मैं चाहता हूँ चाहे वह अलग से क्यों न दिया हो, उसके साथ ही उसका एब्सट्रेक्ट रहता तो हम आसानी से उसे समझ सकते थे यानी एक जगह हमें इसकी सारी पिक्चर मिल जाती। केपीटल अकाउन्ट में डाइरेक्शन का जो

(श्री पी० के० चौधरी)

एक्सपेन्डीचर हो रहा है, ६०–६१ का बजट एस्टीमेट है ३.५५ हजार का, रिवाइज्ड एस्टीमेट है ३.६३ हजार का। इस साल का ६१-६२ का डाइरेक्शन केपीटल अकाउन्ट में एक्सपेन्डीचर रखा है ३.७० हजार, रेवेन्यू अकाउन्ट में ६०–६१ का बजट एस्टीमेट १७.६ हजार था, रिवाइज्ड में जाकर कम हुआ १६.६६ हजार। इस साल में लगभग वह चार लाख के बढ़ गया है। इस प्रकार से सभापति महोदय, डाइरेक्शन और सुपरविजन में हमारा खर्चा बीस लाख से बढ़ कर २४ लाख हो गया है, यानी चार लाख का खर्चा बढ़ा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस खर्चे के सम्बन्ध में फिर से स्क्रुटिनी होनी चाहिये। क्योंकि जो हम रेवेन्यू बजट में ५९-६० का खर्चा देख रहे हैं वह ८.४६ हजार था, और वही खर्चा आज जाकर २४ लाख होता है। इसमें मैं समझता हूँ कुछ लेकुना रह गया है इसलिये दिमाग में शक पैदा होता है कि प्रोपर कन्ट्रोल नहीं रखा जा रहा है। इस बात की तरफ मैं माननीय मंत्री महोदय और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

One minute, Sir,

इसी बजट के दौरान में पिछले साल माननीय मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि जयपुर से एक लाइन फुलेरा ले जाई जायेगी, लेकिन इस साल का बजट देखा, उसमें बहुत तलाश किया, जयपुर से फुलेरा लाइन का कहीं जिक्र नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि इसके लिये क्या स्कीम है ? क्या फुलेरा में इस साल लाइट आयेगी या नहीं ?

श्री बरकतुल्लाखां (उप-मन्त्री,विद्युत): मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि साल के खतम होने तक फुलेरा में लाइन चली जायेगी।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यही बात आप श्रीमाधोपुर के लिये भी कहते।

श्री बरकतुल्लाखां : उसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री पी० के० चौधरी : माननीय उप-मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ उनके इस आश्वासन के लिये। बजट में इसका कुछ भी जिक्र नहीं था इसलिये मुझे कहना पड़ा। आप दस हजार रुपया भी रख देते तो भी ठीक था। जो आपने आश्वासन दिया है वह मन्त्री महोदय भी अपने उत्तर में दोहरा दें तो उचित रहेगा।

श्री बरकतुल्लाखां : यकीन नहीं आता है, एक ही बात है।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री पी. के. चौधरी: Half a minute, Sir, इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो रेट्स हैं वहां रिवाइज कर दिये गये हैं। डोमेस्टिक कन्ज़म्पशन के लिये २५ नये पैसे रेट्स में कमी करके रेट्स की युनिफॉर्मिटी ले आये हैं। मेरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से निवेदन है कि वे हमारे यहां के भी रेट्स रिवाइज़ करें और जल्दी से जल्दी रिवाइज़ करके उसका फाइनल शेप दे दें और वे रेट्स कम से कम

(श्री पी० के० चौधरी)

मध्यभारत से कम्पेयर करके रखे जाय, यही मेरा निवेदन है ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल का सन् ६१–६२ का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उस पर सदन में वाद-विवाद चल रहा है और जिस गंभीरता से इस बारे में बातें कही जा रही हैं कि यह समाजवाद का प्रतीक है आदि इस प्रकार से कई आशायें लगाई जा रही हैं । इस सम्बन्ध में राजस्थान की प्रगति को हम देखें तो मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं, लेकिन यह मेरी मान्यता है कि इस दिशा के अन्दर हम बहुत ही धीमी प्रगति कर रहे हैं । जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनसे विदित होगा कि हमारे राजस्थान के अन्दर टोटल नम्बर ऑफ कन्ज्यूमर्स ७५ हजार बताये गये हैं ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि यह रिपोर्ट सही है और हमारे राजस्थान के अन्दर जहां कि नई जनगणना के अनुसार करीब चार करोड़ होते हैं....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): नयी में दो करोड़ है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : पाली में सघन खेती हो रही है इसलिए वहां पर संख्या भी बढ़ रही है ।

श्री सभापति : Order ! Order. !!

श्री शंकरलाल : जहां राजस्थान में दो करोड़ से अधिक जनसंख्या है वहां पर केवल ७५ हजार कन्ज्यूमर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के । तो इससे अन्दाज लगा सकते हैं कि राजस्थान में विद्युत के बारे में जहां तक जनता का प्रश्न है, विद्युत मंडल ने कहां तक प्रगति की है । इसलिए निवेदन करूंगा कि राजस्थान में इस सम्बन्ध में आशातीत सफलता नहीं मिली है । अगर इस बजट को विभिन्न पहलुओं से देखें तो इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह वास्तव में घाटे का बजट है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : लाभ का बताया है ।

श्री सभापति : No direct talks please.

श्री शंकरलाल : यह जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें २.५१ लाख का सरप्लस बताया है । लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि यदि व्याज की रकमों को जोड़ें तो करीब १७ लाख का घाटा हो जाता है । रिपोर्ट के पेज १२ पर यह बताया गया है, "व्याज प्रभार व कुछ उद्योगों की शक्ति पूर्ति में स्वीकृत दरों में छूट के लिए आर्थिक सहायता, दोनों को ध्यान में रखते हुए वास्तव में हानि सन् १९६०–६१ व सन् १९६१–६२ के लिए क्रमशः रु० ८.९७ लाख व रु० १९.८९ लाख आती है जैसा कि आय–व्ययक विवरण नं० ३ में दिखलाया गया है ।" इस प्रकार से जो व्याज देंगे, छूट देंगे वह भी बजट में गिनना होगा और उस दशा में स्पष्ट कह सकता हूँ कि यह घाटे का बजट होगा, इसलिए इसको सरप्लस बजट कहना बिल्कुल एक भूल होगी । यह सरप्लस बजट नहीं है किन्तु एक घाटे का बजट है । तो यह स्थिति भी बिल्कुल स्पष्ट है ।

(श्री शंकरलाल)

जहां तक युटिलिटी का सवाल है राजस्थान के विभिन्न विकास क्षेत्रों में मैं निवेदन करूंगा कि भाखरा और चम्बल और दूसरों के आंकड़े हैं उनको देखने से स्पष्ट होगा कि राजस्थान की ग्रामीण जनता में थरमल योजना है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको संतोषजनक प्रगति नहीं कह सकते। जहां हम तेजी से राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि देश की हर बात में राजस्थान अगुवा होना चाहिये। राजस्थान विकास योजनाओं में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन विकास के लिए मूल चीज़ जो है वह है बिजली। बिजली के लिए राजस्थान में कुछ प्रगति की है। यदि इसका ६०-६१ और ६१-६२ के आंकड़ों से मिलान करें तो वास्तव में कुछ प्रगति की है। लेकिन उसी से संतोष नहीं कर सकते। यदि राजस्थान के सर्वांगीण विकास को देखते हुए इन आंकड़ों को देखें तो उस दृष्टि से हमको असंतोष का ही अनुभव होगा। ६१-६२ का बजट बनाया गया। ४५० लाख की योजना है। यदि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए देखें तो मालूम होगा कि २४ लाख २१ हजार का प्रावधान रखा है। इस बजट की मेन क्वालिफिकेशन है कि आगामी साल में विद्युत् योजना को गांवों में लागू करेंगे। जहां ४५० लाख की योजना बनाते हैं तो फिर यह समझ में नहीं आता है कि केवल २४ लाख रुपया ही ग्रामीण विद्युत् योजना के लिए किस दृष्टि से रखते हैं ? तो हम कैसे मान लेंगे कि ग्रामों में हमारी योजनायें सफल हुई हैं ? काश्तकार और दूसरे लोग गांवों में बसते हैं, यदि वहां पर बिजली का प्रादुर्भाव नहीं होता है तो वहां पर जो खेती आदि की विकास योजनायें हैं वे अच्छी तरह से नहीं चल सकती हैं और साथ ही छोटे २ उद्योग भी नहीं चलाये जा सकते हैं और विकासशील ग्राम हम उनको नहीं कह सकते। २४ लाख रुपया ग्रामीण योजना के लिए आप रखते हैं और आप इससे यह कहना चाहते हैं कि योजना से हम खूब लाभान्वित हो जावेंगे ? मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ; और कोई भी माननीय सदस्य इसको स्वीकार नहीं करेगा कि इस छोटे से प्रावधान से ग्रामों में बिजली पहुँचाई जा सकेगी, फिर चाहे आप किसी प्रकार का भी आश्वासन दें।

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान विद्युत मण्डल की जो नीति है, जो प्राइवेट पॉवर हाउसेज़ हैं उनको लेने के लिए उसने क्या कार्यवाही की है। कुछ उस दिशा में कदम उठाया है ? विद्युत जैसी शक्ति को राज्य सरकार के हाथ में ही रखना चाहिये और प्राइवेट लोगों को नहीं चलाने देना चाहिये। पूर्व वक्ता ने पाली का उदाहरण देते हुए बताया कि पाली की बिजली की दशा यह है कि जब उनका जी चाहे उसको बन्द कर दें, दरें जो उनकी मर्जी के माफिक हों उसको वे रखें। जब कार्यकर्त्ता मन्त्री महोदय से मिले थे तो उन्होंने स्वीकार किया था कि पॉवर हाउस को हम टेक ओवर कर लेंगे लेकिन वह आज तक नहीं किया गया है।

• **श्री हरिश्चन्द्र** (विद्युत मन्त्री) : मैंने यह कब एश्योरेन्स दिया था ?

श्री शंकरलाल : आपने एश्योरेन्स दिया था जब कार्यकर्त्ता आपसे मिले थे।

श्री हरिश्चन्द्र : मुझसे कोई कार्यकर्ता नहीं मिला था।

श्री शंकरलाल : मैं खुद मिला था।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने क्या कहा था ?

श्री शंकरलाल : अब आप भूल गये होंगे। आपने यह कहा था कि पहले टेक ओवर कराने के लिए जांच करा लेंगे कि इसको ले सकते हैं या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने यह कहा था कि प्रश्न विचाराधीन है।

श्री शंकरलाल : विचाराधीन तो हमेशा रहता है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : गलत अर्थ लगा लिया आपने।

श्री शंकरलाल : तो मैं कह रहा था कि राजस्थान में जहां जहां पर प्राइवेट पॉवर हाउसेज़ हैं उनको विद्युत मंडल को ही चलाना चाहिये, बंटवारा करने की योजना है वह जन-हित में बनानी चाहिये और समाजवाद का नारा देना चाहते हैं तो फिर व्यक्तिगत पूंजी-पतियों का कतई ख्याल नहीं रखें और राज्य सरकार को इन प्राइवेट पॉवर हाउसेज़ को हाथ में ले लेना चाहिये। लेकिन राज्य सरकार एक तरफ तो इनको हाथ में न लेवे और दूसरी तरफ समाजवाद का नारा लगावे ये, विपरीत बातें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए जितने भी प्राइवेट पॉवर हाउसेज़ हैं उनको सरकार को हाथ में लेना पड़ेगा।

तीसरा निवेदन करना चाहूँगा कि सर्वे और इन्वेस्टिगेशन, अन्य कार्य का सवाल है जहां तक, उसके लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि छोटी २ योजनाएं हैं, डिज़ल स्टेशन्स हैं उनके बारे में विचार करेंगे। उनके लिए १.८५ लाख का प्रावधान रखा गया है। गत वर्ष का भी हिसाब लगाया। पाली जिले का मैं निवेदन करूं कि सुमेरपुर की बहुत पुरानी योजना शुरू हुई थी, तिलाड़ा से सोजत तक लाइन खींची गई। उसके अलावा फालना, सादड़ी, राणी, जैतारण के जो लोग हैं वे स्वयम् लाइनें बनाना चाहते हैं, सरकार अलग अलग छोटी २ योजनायें उनको बना कर दें। वे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। वे चाहते हैं कि उनके एरिया में बिजली आवे जल्दी से जल्दी, लेकिन राज्य सरकार ने कोई इस ओर ध्यान नहीं दिया है।

श्री हरिश्चन्द्र : This is contradictory.

एक तरफ तो आपने कहा कि प्राइवेट इन्डिविजुअल्स को पॉवर हाउसज़ नहीं लगाने देना चाहिये और दूसरी तरफ आप यह कहते हैं।

श्री शंकरलाल : मैं प्राइवेट पार्टीज़ के लिए नहीं कहता हूँ। जो लोग इन चीजों को अपने यहां लगाना चाहते हैं और वे सरकार की मदद करने के लिए तैयार हैं, वे गवर्नमेंट के शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हैं, यदि गवर्नमेंट कहे कि हमारे पास पैसा नहीं है तो वे पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि पाली में ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपयों का यदि सरकार

(श्री शंकरलाल)

पॉवर वहां पर पहुँचाये तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।

(३ म० प०)

इस बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि विद्युत मंडल के चेयरमैन पाली जिले के कलेक्टर रह चुके हैं, उनको पूर्ण जानकारी है कि पाली जिले के अन्दर पोटन्शियेलिटी इन्वेस्टमेंट की कितनी है !

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): एक तरफ तो आप पब्लिक सेक्टर की बातें करते हैं तो उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर किस प्रकार से चलेगा ?

श्री शंकरलाल : गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कुछ इनीशियेटिव ले तो वहां की पब्लिक तैयार है। पाली से आये हुए माननीय सदस्य जब पाली की बात कर रहे थे उस बात पर कहा गया कि पाली ही राजस्थान में एक ऐसा जिला है जहां पांच औद्योगिक बस्तियां कायम हो रही हैं। अगर हम विद्युत का वहां प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं तो जो उद्योग धंधे हैं और आगे होंगे वे पनप नहीं सकेंगे। पाली जिला एक ऐसा जिला है जहां भारत सरकार ने पेकेज स्कीम लागू की है। राजस्थान के किसी भी जिले में सघन खेती की योजना लागू नहीं की, केवल पाली जिले में ही यह कार्य शुरू किया गया है। इस पर ११ करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है। तो जहां इस प्रकार की योजना है वहां यदि विद्युत सप्लाई की गई तो बिजली के जरिये उसका बहुत जल्दी विकास हो सकता है। जहां किसानों के लिये करोड़ों रुपया राज्य सरकार द्वारा खेती के लिये खर्च किया जायेगा वहां इस चीज़ के लिये भी सर्वे इन्वेस्टीगेशन करवाना चाहिये ताकि पाली जिले के खेतीहर किसानों को किस प्रकार से बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है। पाली जिले में औद्योगिक बस्तियां हैं, राणी, फालना, सादड़ी में लगाई जा रही हैं। इस बारे में जो इन्डस्ट्रियल स्टेटस होगा अगर वहां बिजली नहीं मिलेगी तो जो लोगों ने उद्योग धन्धे वहां लगाये हैं वे किस प्रकार सफल हो सकते हैं ? वहां की जिलापरिषद् ने भी एक योजना बना कर राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत की है। इस बारे में मेरा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि जो योजना जिला परिषद् द्वारा प्रस्तुत की गई है उसकी जांच करायेंगे और जांच के पश्चात् पाली जिले के अन्दर बिजली के विकास के साथ साथ यह योजना बिजली की कहां तक सफल हो सकती है, इस बारे में पता लगायेंगे।

जहां तक बिजली के कनेक्शन देने का सम्बन्ध है राजस्थान के अन्दर, उसके लिये मैं यह कह सकता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में हमें बिजली पहुंचानी है, तभी वास्तविक रूप से विकास हो सकेगा। मौजूदा बजट में उसके लिये बहुत कम प्रावधान रखा गया है, उसको हमें बढ़ाना होगा। हमारे जो अनुमान होते हैं वे भी गलत होते हैं। हमने सन् ६० और ६१ का बजट देखा। अनुमान जो रिवाइज्ड बजट में आते हैं जिस वक्त बजट बनाया जाता है वह एक प्रकार से अनुमान ही होता है। वास्तविक खर्चे का तो तब पता चलता है जब कि उसके सम्बन्ध में ऑडिट रिपोर्ट आती है। वास्तविक खर्चे में और अनुमानित खर्चे में काफी अन्तर होता है। सन् ६० और ६१ में

(श्री शंकरलाल)

६८ लाख का बजट था, उसके बाद १०.५७ लाख का बजट आया। इस तरह से ४४८ लाख का डिफरेन्स पड़ा। इस समय मैं यह निवेदन करूंगा, जो अनुमान करते हैं, जो हमने इस साल का बजट बताया है और जिस प्रकार की धनराशि रखी है, वास्तव में वह गलत बजट है। उसके अन्दर जो अनुमान लगाये गये हैं वे गलत हैं और इसी तरह से रिवाइज्ड बजट में अन्तर पड़ता है। जब इसकी ऑडिट रिपोर्ट हमारे सामने होगी तभी हम कह सकते हैं कि राजस्थान की प्रगति और विकास में जन समुदाय और ग्रामीण क्षेत्र में कितना काम हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट आज सदन में विचारार्थ है। जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि कहां कहां किस किस प्रकार का खर्चा किया गया है एवं किया जायेगा। इन सारे आंकड़ों को देखने से ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि हमने, जहां तक खर्चे का सवाल हैं उसमें काफी खर्चा किया है। अभी फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बोर्ड की कार्य कुशलता के लिये धन्यवाद दिया है। लेकिन हम बजट देखते हैं उसके अन्दर कार्य कुशलता का परिचय क्या केवल इसी से लगाया जा सकता है कि बजट में ज्यादा खर्चा दिखाया गया है? इसमें जो खर्चा दिखाया गया है भाखरा, नांगल और चम्बल हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम के अन्दर जहां ६०-६१ में १.३७ लाख का एस्टीमेट था खर्चे का वहां २.८१ लाख के आसपास हुआ है। चम्बल हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिये २.६४ लाख का प्रोविज़न था वहां ५.६३ के आसपास खर्चा हुआ। उसी प्रकार थर्मल इलेक्ट्रिक स्कीम्स के लिये ७५ लाख का प्रोविज़न था वहां १ करोड़ १६ लाख ६८ हजार हुआ है। इन आंकड़ों के आधार पर यह जरूर कह सकते हैं कि गत वर्ष काफी तेजी के साथ काम हुआ, लेकिन जब तक इस बजट के साथ में ऑडिट रिपोर्ट नहीं होगी हम यह महसूस नहीं कर सकते कि वाकई इतना खर्चा हुआ है या नहीं। कार्य कुशलता की वजह से ज्यादा खर्च हुआ, या गफलत की वजह से ज्यादा हुआ यह तो हम ऑडिट रिपोर्ट के आने के बाद ही कह सकते हैं। फिर भी जहां तक कार्य का सवाल है इस सम्बन्ध में, जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, कार्य कुशलता की दृष्टि से इतना खर्च हुआ है, यदि यह सही है, तो यह कार्य सराहनीय है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : क्वालिफाइड करेंज?

श्री मुरलीधर व्यास : सवाल इस बात का है कि खास तौर से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बनने से पहले किस प्रकार की बिजली की व्यवस्था थी और किस तरह से खर्च हुआ? मैं ज्यादा आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर महसूस करता हूँ कि पहले भी जब इस बोर्ड की रिपोर्ट आई उसमें भी सरप्लस दिखाया गया था। ५६-५७ में करीब ६ लाख का सरप्लस बताया गया था, उससे पहले भी ऐसा मौका आया है। बोर्ड के बनने के बाद में यह स्थिति है, इसके अन्दर भी सरप्लस बताया गया है। मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आखिर जो हम इसको

(श्री मुरलीधर व्यास)

एक व्यवसायिक कन्सर्न के रूप में देखते हैं तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से इस बारे में सोचना होगा। कुल खर्चा राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी के लिये जितना किया, चाहे वह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर हो या अन्य प्रकार का पॉवर हो उसके अन्दर जब हम जाते हैं तो, जहां हमारा खर्चा बढ़ता है वहां हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि जिस अनुपात में खर्चा हुआ है उस अनुपात में प्राप्ति भी हुई या नहीं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाय तो यह संभव नहीं। यह इसलिये संभव नहीं आज के जमाने में जिस प्रकार का प्लानिंग चलता है उसके अन्तर्गत बहुत कम आज के दृष्टिकोण में क्या लाभ होने वाला है, यह देखते हैं, बल्कि यह होता है कि आगे जाकर ये स्कीम्स कितनी लाभप्रद हो सकती हैं, इस दृष्टिकोण से देखा जाता है। जिस प्रकार से खर्चा बढ़ा है उस अनुपात से काम भी बढ़ा है। थर्मल पॉवर स्टेशन का ख्याल है, उसमें हमें यह भी देखना है कि जितना खर्च किया गया है क्या उतनी आमदनी हो जायेगी। इसका भी एस्टीमेट बांधा था। थर्मल से इसका एस्टीमेट ६.६० हजार का था और इसके बाद रिवाइज्ड ४.६३ हजार का आया। इसमें तो कमी हो गई। पर उधर खर्चे में बढ़ोतरी रही। तो यह सोचने का सवाल है। खर्चा तो ज्यादा बताते हैं, पर जब आमदनी की बात आती है तो उसे कम कर दिया जाता है। इससे ऐसा लगता है, कहीं अव्यवस्था है। इसकी खोज की जावे।

जो आमदनी होती है थर्मल स्टेशन से वह बहुत ज्यादा है। दूसरी ओर हाइड्रो इलेक्ट्रिक से बिजली तो ज्यादा पैदा की, ज्यादा भी देने की बात करते हैं और आगे भी ज्यादा होगी, ऐसा भी मानता हूँ पर जब देखते हैं तो सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, खास कर भाखरा-नांगल से ३६४ हजार का एस्टीमेट था। भाखरा की तीन लाख की जगह ५.६१ लाख। चम्बल का २६३ हजार और थर्मल का करीब १ करोड़, ७२ लाख, इस प्रकार से है। तो जो बिजली जनरेट होती है वह तो हम देखते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान्ट से ज्यादा है और आमदनी उसके मुकाबले में बहुत कम है। इससे यह अन्दाज लगा सकते हैं कि इसमें हमारा खर्चा बहुत ज्यादा है। पर इसके साथ ही साथ आमदनी बहुत ही कम है। नगण्य सी है। इस स्थिति से स्पष्ट होता है कि जो बिजली हम जेनरेट करते हैं तो इस कारण या तो हम उसको पूरा उपयोग में नहीं ला पाते और अगर इस्तेमाल होता है तो लाभ मिलना चाहिये। तो ये दो बातें हमारे सामने हैं। सवाल यह है कि इस्तेमाल कैसे किया जावे ? मैं महसूस करता हूं कि इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा तब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। इसका ज्यादा इस्तेमाल कैसे हो, इसके लिये खास कर मेरे इलाके में मैं देखता हूं कि यह ठीक है, काफी गांवों में बिजली पहुंच गई है पर उससे लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं या उसका रुपये में दो पैसा भी इस्तेमाल करते हैं या नहीं ? तो मेरा उत्तर यह है, दो पैसा भी वे उपयोग में नहीं ले रहे हैं, मेरा ऐसा दिमाग है। इसके लिये न सरकार के पास कोई योजना है न हमारे ध्यान में कोई आई है कि किस प्रकार इसका उपयोग बढ़ सकता है। शहरों में उपयोग जरूर हो सकता है। जैसे बीकानेर में इन्डस्ट्रियल एरिया कायम हुआ। पर गांव

(श्री मुरलीधर व्यास)

का किसान किस तरह से उसका उपयोग करेगा, मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आती कि क्या उपयोग वह लेगा क्योंकि वहां के कुंए बहुत गहरे हैं। उसमें किसी ने बिजली से निकालना भी शुरू किया तो दिवाला पिट जावेगा। तो बिजली के प्रोडक्शन के बारे में हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली, भाखरा से यहां तक ले आये। बहुत बड़ा भारी काम हमने कर लिया। पर पूछता हूं कि इस सारी बिजली का लाभ जनता को किस प्रकार से मिलेगा और सरकार को इस सारे से आमदनी किस प्रकार से होगी ताकि जो बड़ा भारी खर्चा सरकार ने इस पर किया है वह मीट हो सके ? अगर इसकी जांच के लिये और रास्ता निकालने के लिये कमेटी बैठाई जावे तो कुछ हो सकता है। कोई प्लान सामने आ सकता है वर्ना सिवाय किसी गांव में दो-चार लट्टू लगा दिये इसके सिवाय और कोई दूसरा लाभ मेरी नजर में नहीं आता। गंगानगर में मान लेता हूँ फर्टीलाइजर फैक्टरी लगने पर २५ हजार किलोवाट वहां खप जावेगी, अन्यथा तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। मन्त्री महोदय इसकी सफाई करेंगे, ऐसी आशा है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : सारे बीकानेर-चूरू जिले में इसका कोई उपयोग नहीं है आपके खयाल से ?

श्री मुरलीधर व्यास : औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा पांच पैसे का भी लाभ हो रहा है, यह आप भी बता देंगे तो मान लूंगा। मेरे दिमाग में तो नहीं है। अब मैं खास करके इस बात के लिये इसलिये आलोचना नहीं करना चाहता....

श्री चन्दनमल वैद : आलोचना तो आप कर चुके। अब घबराते क्यों हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : घबराता कहां हूँ ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : वे यह चाहते हैं कि बीकानेर में बिजली नहीं ले जाई जावे ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो यह कह रहा हूँ कि उसका इस तरफ दिवाला पहुँचा हुआ है, आज उसका कोई उपयोग वहां नहीं है और उससे कोई आमदनी नहीं हो रही है।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सदस्य करवट बहुत जल्दी बदल रहे हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आगे चुनाव आ रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह सोचता था कि लिग्नाइट के बिजलीघर की जैसी योजना थी बीकानेर में १० हजार किलोवाट का प्लान्ट लगाने की, वह अगर होता तो सस्ती बिजली जेनरेट होती और सस्ती बिजली सारे जिले में चल सकती थी। दूसरा, तीस हजार किलोवाट का प्लान्ट लगाने की योजना की सरकार ने घोषणा भी की पर वह भी व्यवस्था अगर नहीं होती है तो जो पहले सोचा था कि यह सस्ती बिजली गांवों में जावेगी और इसका उपयोग कुओं में भी लाभ दे पावेगा सस्ता होने की वजह से तो वह उपयोग भी हम कर पावेंगे या नहीं, मेरे खयाल से....

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

मैंने तो अभी प्रारम्भ ही किया है।

श्री सभापति : You have taken 12 minutes. Please conclude within two minutes.

श्री मुरलीधर व्यास : तो मैं कह रहा था कि भाखरा-चम्बल आदि की बिजली जब तक हम सस्ती रेट पर नहीं दे पावेंगे तब तक इन्डस्ट्रीज़ भी पनप सकेगी, मैं नहीं समझ पाता। रेट के आधार पर ही इन्डस्ट्री पनपती है, क्योंकि वे दूसरे प्रान्तों की रेटों से तुलना करते हैं चूंकि उनको कम्पीटीशन में टिकना है। ऐसी हालत में बहुत से लोग इन्डस्ट्री में इस्तेमाल करने में भी ऊंची रेट होने से घबराते हैं। तो सरकार को अगर राजस्थान में इन्डस्ट्री का विकास करना है तो दूसरे प्रान्तों की रेट्स के तुलनात्मक दृष्टिकोण से सोचना होगा और उसी तरह से रेट्स फिक्स करनी होंगी।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि हो सकता है बिजली का इस्तेमाल वहां हो जहां कुए बहुत ही गहरे नहीं हों, वहां पर किसान बिजली का उपयोग कर सकते हैं। गांवों में बिजली के उपयोग के बारे में सुझाव देना चाहता हूँ चूंकि यह व्यवसायिक कन्सर्न है, तो इस विभाग की तरफ से ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि गांवों के अन्दर बिजली का उपयोग किस प्रकार से किया जाये, इस बात को समझाये। इस प्रकार की योजना आपको बनानी चाहिए। आपके पास बिजली ज्यादा है और उसको निकालनी है और उसका फायदा उठाना है तो यह योजना बनानी चाहिए कि गांवों में अपनी तरफ से प्रचारक भेज कर बिजली का उपयोग समझायें, नहीं तो गांवों में बिजली का उपयोग लोग नहीं कर सकते, इस प्रकार की स्थिति आज भी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ा सा मैं ट्रेड यूनियन के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। वह इसलिए कहना चाहता हूं कि यह जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है इसका दृष्टिकोण मजदूरों के सम्बन्ध में क्या होना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि जहां तक यह बोर्ड एक व्यवसायिक कन्सर्न है उसमें हमारा दृष्टिकोण व्यवसायिक होना चाहिए, दूसरे, क्योंकि यह कल्याणकारी राज्य है इसलिए यह दृष्टिकोण भी रहना चाहिए कि हम शोषण न करें, बल्कि जो काम करने वाले हैं, जो मजदूर हैं उनको लाभ पहुँचे। तीसरे, यह भी दृष्टिकोण होना चाहिए कि जो व्यवसायिक दृष्टिकोण है जिसमें काम करने वाले हैं, जैसा कि नन्दाजी कहते हैं कि हर कन्सर्न के अन्तर्गत उसकी देखरेख में, उसके कार्य संचालन में मजदूर संगठन का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए। तो मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी एक प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए ताकि वह मजदूरों के विषय में बातों को बोर्ड के सामने रख सके और अपने यहां की जो दिक्कतें हैं उनको मजदूरों के सामने और उनके बीच में रख सके। तो यह मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्रीमती गंगादेवी डाटा।

(विराम)

समय का ध्यान रखते हुए आगे बोलने वाले माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा

(श्री सभापति)

कि कृपया अपनी स्पीच को १० मिनट में ही समाप्त कर दें।

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) : सभापति महोदय, क्या यह मेरे ऊपर ही लागू होता है, पहले तो लागू नहीं था ?

श्री सभापति : आप आरम्भ रखिये।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : सभापति महोदय, विद्युत मण्डल के १९६१–६२ के बजट पर जो वाद–विवाद हो रहा है उस वाद-विवाद को देखते हुए मैं यह जरूर कहूंगी कि जिस तरह से विद्युत मण्डल ने अपना कार्य किया है और जिस मेहनत और कार्य–क्षमता से अपने कार्य को पूर्ण करने की कोशिश की है, मैं समझती हूं कि उन्होंने काफी इसके अन्दर दिलचस्पी ली है। साथ ही यह बात जरूर है कि विद्युत मण्डल के जो पिछले दो पंचवर्षीय योजना के टार्गेट्स थे उनको उन्होंने पूरा किया है और तृतीय पंचवर्षीय योजना के जो टार्गेट्स हैं उनको देखते हुए यह आशा होती है कि वह राजस्थान में बहुत जल्दी ही चकाचौंध बिजली द्वारा करने जा रहे हैं।

एक प्रश्न पैदा होता है कि जैसे शहरों के लिए बिजली के टार्गेट्स हैं उस तरह से गांवों में अन्दर भी क्या उतनी ही तेजी से बिजली दे सकेंगे ? इसके लिए मुझे शंका अवश्य हो रही है। इस तरह से जैसे पिछले कार्य चल रहे हैं उनको मैं देखती हूँ, मैं आशा भी करती हूँ कि जितने सुयोग्य और कमर्ठ हाथों में यह काम चलता रहा और जिस तरह से अभी चल रहा है तो आशा बंधती है कि गांवों में बिजली माननीय मंत्री महोदय देने की शीघ्र ही कृपा करेंगे। साथ ही साथ यह बात भी मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो अलवर जिला है वह सौभाग्य से या दुर्भाग्य से ऐसी जगह स्थित है कि जहां पर बिजली कई वर्षों पूर्व बराबर दिखाई दे रही है और बराबर कार्य कर रही है, लेकिन अलवर ही एक ऐसी जगह रही जहां विकास के कार्य अभी तक नहीं के बराबर से हैं। अलवर जिला बिजली पर जरूर निर्भर है। कोई वहां बड़े बांध या नहर आने की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि वह कुछ ऊंचाई पर है।

जो भाखरा की बिजली है वह अलवर की एक तहसील तिजारा है उसके बीच में से गुजर रही है। उसको देख कर सब लोगों को अफसोस होता है कि जब भारतवर्ष की स्कीम है कि हम गांव–गांव में बिजली पहुंचाने का इरादा रखते हैं तो क्या यह इरादा पूरा होता है ? एक जिले की एक तहसील में से कई मीलों की दूरी तक बिजली के पोल गुजर रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य से भाखरा की बिजली वहां नहीं आई और जो कोशिश की जा रही है न उससे ही ऐसा लगता है कि आगे कुछ और टाइम निकल जाये उसमें बिजली आ जायेगी। भाखरा की बिजली के जो यूनिट के चार्जेज़ हैं वे इतने कम होते हैं कि अलवर में जो छोटे छोटे उद्योग चल रहे हैं वह महसूस करते हैं कि हमें भाखरा की बिजली मिलती तो कितनी आसानी से हम कार्य कर सकते थे। मैं, सभापति महोदय, आप से निवेदन करूंगी कि यह जो भाखरा की बिजली है यह अलवर का जो बोर्डर है उससे केवल ६ मील

(श्रीमती गंगादेवी डाटा)

के फासले से ही पास होती है। फिर क्या कारण है कि अलवर इतने पास होते हुए भी उसको बिजली नहीं दी जाती है? अलवर बोर्डर है वहां तक भी ले आयें और उसके आस-पास करबों में भी बिजली आ जाये तो काफी आसानी हो सकती है।

दूसरी बात यह जरूर है कि जो चम्बल की बिजली हमें जल्दी ही मिलने वाली थी ऐसी उम्मीद थी और ऐसा सुनने में आ रहा है कि चम्बल की बिजली जो गांधी डैम से मिलने वाली थी वह १९६१–६२ में मिलने वाली थी हम ऐसा समझते हैं कि १९६१–६२ में अवश्य ही मिल जायेगी। इसे मैंने १९६१–६२ के बजट में देखा तो कहीं नजर नहीं आया और १९६१–६२ में जो अलवर पर बिजली की मद में पैसा खर्च किया जायेगा वह भी दिखाई नहीं दिया। सभापति महोदय, यह बात है कि वह जो जिला है वह बिजली पर निर्भर करता है। उस जिले को आर्थिक उत्थान बिजली के द्वारा ही मिल सकेगा और बिजली एक ऐसी आवश्यक चीज़ हो गई है कि उसके बिना आज का जीवन नीरस सा दिखाई देता है। अभी वहां पर २९ गांवों में बिजली आ रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अलवर का जो स्टीम टर्बाइन पॉवर हाउस चल रहा है वह भी १०–१० मील तक बिजली दे सकेगा, ऐसा सुनने में आया है। तो इसके लिए कौन से आसपास के कस्बे हैं जिनको इसमें लेने का प्रोग्राम है, वह इसमें मुझे देखने को नहीं मिला। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इसमें मुझे देख कर उत्तर देने की कृपा करेंगे।

दूसरे जो अभी बिजली के स्टीम पॉवर हाउस या उसके डिज़ल स्टेशन्स हैं इनके जो बिजली की रेट्स हैं उन रेट्स को जांचने के लिए जो कमेटी बैठी है वह पता नहीं अपनी रिपोर्ट कब तक दे, लेकिन यह बात जरूर होती है कि एक जिले से दूसरे जिले में बिजली के चार्जेज़ मे २–३ आने का अन्तर मिलता है प्रति युनिट में। यह एक बहुत ही दिक्कत की बात है। नजदीक से नजदीक में फर्क मिल जाय तो अच्छा नहीं लगता है, जैसे जयपुर के अन्दर ६ आना हैं और अलवर के अन्दर ८ आने प्रति युनिट चार्जेज़ हैं। तो जल्दी से कम हो जाय तो बहुत अच्छा हो।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): सभापति महोदय, विद्युत मण्डल के सन् ६१–६२ के आय-व्ययक पर विवाद कर रहे हैं। सभापति महोदय, जहां तक बिजली की वर्तमान स्थिति का संबंध है इसको तो हम संतोषपूर्वक कह सकते हैं कि विद्युत की प्रगति हमारे राज्य में विद्युत वेग से ही बढ़ रही है। राजस्थान बनन के अवसर से लेकर अब तक उसमें निरंतर प्रगति हुई है। एक ओर जहां यह संतोष का विषय है वहां सभापति महोदय, हमें यह भी कहने में संकोच नहीं होता कि जितनी प्रगति इन दिनों में होनी चाहिये थी राजस्थान बनने के बाद, अब ११–१२ साल के अन्दर तुलनात्मक दृष्टि से जहां और राज्यों ने इतने दिनों में प्रगति की है उतनी प्रगति हमारे राज्य में नहीं हो पाई है। हो सकता है कि इसके अनेक प्रकार के कारण हों, लेकिन स्थिति यह है।

अब जो भी वर्तमान में स्थिति है उसके

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

संबंध में भी हमको इस बात से अधिक से अधिक लाभ हमारी जनता को पहुंचे, इसकी ओर विशेष प्रयत्नशील होने की आवश्यकता है। जैसा कि, सभापति महोदय, प्राय: सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि आज के युग में बिजली की आवश्यकता केवल शहरों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिये, बल्कि इसका उपयोग अधिक से अधिक गांवों में भी होना चाहिये। गांव वालों की कृषि की उपज बढ़ाने की दृष्टि से और साथ ही साथ छोटे २ उद्योग धन्धों की दृष्टि से, सभापति महोदय, हमारा सबसे पहला उद्देश्य क्या हमारे देश और राज्य का है कि हम अपने यहां के हजारों और लाखों बेरोज़गार लोगों को धन्धा दिलायें ? उन बेरोजगार लोगों को हम समय समय पर भी अनुभव करते हैं, कि हमारी सेवाओं में चाहे हम कितनी ही वृद्धि करते चले जाय, वह उतनी नहीं हो सकती। जितने लोग, पढ़े-लिखे लोग निकलते हैं, जितने आज भी अपढ़ लोग मौजूद है और जिस गति से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है इन तमाम चीजों को देखते हुए हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम अधिक से अधिक लोगों को कृषि में लगायें। लेकिन कृषि और उद्योगों में यदि हम पुराने तरीकों से खपाना चाहें, तो उन लोगों को इस तरह से अपने आपसे एडजस्ट करें, कि जिससे आज दुनिया के अन्दर प्रगति चल रही है उसमें भी उनके पीछे रह जाने की संभावना न रहे। आज तो किस तरह से एक जमाने में यूरोप के अन्दर इन्डस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था जिसने सारे के सारे यूरोपीय महाद्वीप में क्रान्ति मचा दी थी उसी तरह से बिजली हमारे देश में क्रान्ति ला रही है। जिन जिन राज्यों में बम्बई, मद्रास, मैसूर और जहां जहां बिजली सस्ती और शीघ्र बनने वाली है जिस जिस स्थान पर पहुंची है वहां के लोग कई प्रकार से विशेष प्रगति कर चुके हैं। क्या शिक्षा की दृष्टि से, क्या उद्योग की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से वे हमारे इस पिछड़े राज्य से कहीं आगे हैं। आज हम राजस्थान का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो बिजली को एक महत्वपूर्ण स्थान दें। इसलिए जहां तक भी कुछ प्रगति हुई है उसके बारे में संतोष व्यक्त करते हुए भी मैं संबंधित मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि उनका यह प्रयत्न होना चाहिये कि वे इस बिजली को अधिक सस्ती और अधिक सुलभ बनायें और इसके साथ साथ इसका इस प्रकार से उपयोग हो कि यह जल्दी से जल्दी गांवों में पहुंच सके।

उदाहरण के तौर पर अभी जैसा कि इस रिपोर्ट में भी बतलाया है कि हमारे यहां चम्बल की तरफ से आने वाली जो बिजली है वह कोटा से सवाई माधोपुर आती है। और सवाई माधोपुर से जयपुर आती है, और जयपुर से ही राजगढ़, अलवर या भरतपुर को जाती है। तो मैं समझता हूँ कि शायद हमारे संबंधित अधिकारियों ने इस बात को अवश्य अपने ध्यान में रखा होगा कि उस बिजली की लाइन को ऐसे स्थानों पर होकर ले जाया जाय जो कि अच्छे कस्बे हों, बड़े गांव हों और जहां उसका अधिक से अधिक उपयोग करें। उदाहरण के तौर पर मैं जयपुर से भरतपुर की बिजली

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

के बारे में बतलाऊंगा कि जयपुर से राजगढ़ तक बिजली जाती है। मैं समझता हूँ कि इसका मार्ग निश्चित किया होगा तो किया होगा, और राजगढ़ और भरतपुर के बीच में खेड़ली और नदबई जैसे बड़े कस्बे आते हैं। वे व्यापारिक कस्बे हैं और अच्छे कस्बे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लाइन भरतपुर और राजगढ़ को जोड़नेवाली होगी वह इसी प्रकार से अलयगढ़ आदि कई ऐसे बीच के गांव और कस्बे हैं, उन कस्बों को ध्यान में रखते हुए आपके टॉवर्स और तार जायेंगे वे उनके ऊपर से जायेंगे जिनसे वहां के लोग भी लाभ उठा सकें।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहूँगा कि जिस प्रकार भरतपुर से डीग तक स्टीम स्टेशन से बिजली पहुँचाई गई है तो मैं समझता हूँ कि डीग से बिजली पहले से ही अच्छी है। डीज़ल एन्जिन किसी प्रकार का रहा हो और वहां पर कस्बे के लिए कुछ न कुछ काम देता रहा है। लेकिन डीग को यह जाने वाली बिजली है यह करीब २३ मील का रास्ता है। उस रास्ते के गांव वाले इस बात की आशा और आकांक्षा किए हुए बैठे हैं कि उस बिजली का उनको लाभ पहुँच सके। तो माननीय मन्त्री यह बतलायेंगे कि वहां बिजली की लाइन जो निकलेगी तो उसके आसपास के गांव कितने कितने फासले तक किस तरह से लाभ उठा सकेंगे? साथ ही साथ डीग के इर्द-गिर्द नगर का अच्छा कस्बा है और कामा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थान है वहां के लिए भी बिजली मिले। उसके लिए एक दफा प्रश्नोत्तर काल में बतलाया गया था कि भरतपुर के बाद में कहां कहां कितनी बिजली पहुँचेगी, यह तब बतलाया जा सकेगा जब कि लोड सर्वे हो चुकेगा। मैं समझता हूँ कि लोड सर्वे हो चुका होगा, और आज माननीय मन्त्री महोदय इस स्थिति में होंगे कि वे यह बतला सकेंगे कि भरतपुर के थर्मल की जो केपेसिटी है और चम्बल की इसमें बिजली पहुंचेगी उसके बाद में बिजली का कहां कहां तक लोगों द्वारा उसका उपयोग करा सकेंगे।

इसके साथ साथ मैं और सुझाव इस प्रकार का दे रहा हूँ, जैसा कि अलवर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा था भरतपुर से भी गुड़गांव जिला लगा हुआ है और खास तौर से कामां तहसील का एक कस्बा जुरहरा रहता है और गुड़गांवा का एक कस्बा बोमा है वह शायद ६, ७ मील है वहां तक पंजाब की तरफ से हाइड्रोइलेक्ट्रिक आती है और २—३ मील पर पंजाब का एक हिस्सा रहता है और २—३ मील राजस्थान का रहता है गांव। वहां के पंचों और सरपंच ने इस प्रकार की मांग की है जो कि मन्त्री महोदय के पास पेश की होगी। वे कहते हैं कि चम्बल से भरतपुर को पहुंचने वाली बिजली जब पहुंचेगी तब पहुंचेगी लेकिन राज्य सरकार पंजाब सरकार से लिखा-पढ़ी करके बिजली के खम्बे ३—४ मील तक आ चुके हैं लेकिन बिजली उस कस्बे तक नहीं पहुँचेगी, उसको पहुँचाने के लिए प्रयत्न करना चाहिये। तो इस प्रकार के सुझाव यू० पी० स्टेट और पंजाब से जहां कि जल्दी सुलभ हो सकती है, जहां तक

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

पहुँच सकती है उसको लिया जाय और अपने यहां की है वह तो पहुँचेगी ही ।

एक और सवाल है, सभापति महोदय, जहां कि हम समय समय पर सुनते हैं कि कोई भी भाग्यशाली स्थान है जहां भाखरा और नांगल से बिजली आती है या वह चम्बल से संबन्धित होने वाला इलाका है, लेकिन इनकी दरों में अवश्य अन्तर है, क्योंकि जो बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होगी वह स्वभावतः कुछ सस्ती होगी बनिस्पत उसके जो कि थर्मल या दूसरे प्रकार के उपकरणों से उत्पन्न की जाती है। तो मैं यह समझता हूँ कि राज्य सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करेगी, विद्युत मंडल खासतौर से विचार करेगा कि यह बिजली की रेटों में जो असमानता है वह किस प्रकार से दूर हो, क्योंकि सारे का सारा कन्सर्न तो एक ही है। थोड़ा बहुत कहीं ज्यादा लाभ मिलता है तो कहीं पर कम लाभ लेकर दरों में इस प्रकार की समानता लायें कि हर एक स्थान पर चाहे वह चम्बल से दूर हो, चाहे वह भाखरा नांगल से दूर हो, जिस वक्त बिजली मिले उसको उन्हीं रेट्स पर मिले, क्योंकि इसमें हर एक की पोज़ीशन में थोड़ा सा ही अन्तर है; जिससे वे भी यह समझ सकें कि राजस्थान में जो बिजली की सुविधा दी गई है उसमें हम भी उतनी ही सस्ती कीमत पर साझेदार हैं, जैसे वे लोग। ये कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनसे हमारे यहां के लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा और उसमें सबसे अधिक प्रयत्न यह किया जाय कि जो हमारी लाइनें निकाली जा रही हैं उनसे अधिक से अधिक गांवों को और बीच के रास्तों को बिजली पहुँचाई जाय। इस सम्बन्ध में विद्युतमन्डल की या राज्य सरकार की क्या नीति है, उस पर मैं समझता हूं, मन्त्रीजी प्रकाश डालेंगे।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय सभापति महोदय, इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता कि बिजली किसी भी प्रान्त के औद्योगीकरण के लिये, उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये तथा एम्पलॉयमेंट देने के लिये सबसे बड़ी चीज़ है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि राजस्थान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिये और इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिये आज तक सबसे बड़ी बाधा कोई रही है तो वह यह है कि बिजली उपलब्ध करने में हम हमेशा पीछे रहे हैं; इस बात में दो राय नहीं हो सकती। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ९ साल तक हम बहुत पिछड़े हुए रहे। लेकिन यह संतोष की बात है कि पिछले साल हमने काफी प्रगति की है। पहली बार ऐसा मालूम हो रहा है कि राजस्थान में हमारा डिपार्टमेंट विद्युत बोर्ड पहली बार, हम समझते हैं, जो पीछे कमी रही थी उस पर हावी हुए हैं। हम कह सकते हैं कि आज तक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट या इस बोर्ड की वजह से राजस्थान इस क्षेत्र में पीछे रहा है आज हमारा बोर्ड उस कमी पर हावी हुआ है और सारी चीजें हमारे भिंप में हैं और हम आशा कर सकते हैं कि हमारा भविष्य उज्ज्वल है। इस बात के लिये मैं बधाई मन्त्रीजी को और बोर्ड को दूंगा। लेकिन साथ ही साथ उन सारी बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जो हमें भविष्य में करनी चाहिये।

Page No 88

(श्री चन्दनमल वैद)

सभापति महोदय, इस बात की खुशी है कि पिछले साल वे सब काम किये जो करने चाहिये थे और पहली और दूसरी योजना में, जिसको हम कहते हैं बैक लॉग या एरियर रह गया था उसको पूरा किया। जो आंकड़े दिये हैं उनसे मालूम होगा कि पहली पंच-वर्षीय योजना शुरू होने से पहले जितनी बिजली उपलब्ध थी उससे ८ गुनी ज्यादा तीसरी योजना शुरू होने से पहले हमारे पास है और दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होने से पहले जितनी बिजली हमारे पास थी उससे आज तिगुनी बिजली हमारे पास है। यह सचमुच संतोष की बात है कि हम मेहनत करके इतनी बिजली उपलब्ध कर सके हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें यह ध्यान देना जरूरी है कि इसका उपयोग कहां होना चाहिये और कहां कर रहे हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि गांवों में बिजली ले जाइये। मैं भी इससे सहमत हूँ और चाहता हूँ कि जितनी बिजली गांवों में ले जा सकें ले जानी चाहिये। मैं भी चाहता हूँ कि गांवों में बिजली के पंखे और बिजली के बल्ब लगने चाहिये? लेकिन हमको यह भी समझना चाहिये कि आज हमारे पास जितनी बिजली उपलब्ध है वह सीमित मात्रा में है, हमारे साधन सीमित हैं। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि तीसरी योजना के अन्त तक जितनी बिजली हम उपलब्ध कर सकते हैं वह सब की सब आज की तारीख में बुक्ड है। भाखरा और चंबल से जो बिजली हमको तीसरी योजना में मिलने वाली है वह सारी इन्डस्ट्रीज़ और दूसरे लोगों के लिये बुक कर चुके हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि हमारे साधन सीमित हैं। कोई यह इच्छा करे कि जितनी चाहें उपलब्ध कर सकते हैं तब तो हम बिजली के पंखों और रेफरिज-रेटर्स के लिये भी दे सकते हैं। लेकिन जब साधन हमारे पास सीमित हैं, इच्छानुसार उत्पादन नहीं कर सकते तो हमें सोचना पड़ेगा कि जितनी बिजली उपलब्ध कर सकते हैं उसका उपयोग किस में करेंगे? पिछले साल जितनी बिजली हमने तैयार की है उसको एक साथ इस तरह से खर्च कर दें जिस तरह से एक आदमी जो उम्र भर गरीब रहा है उसको अचानक ५० हजार रुपये मिल जाय और वह पार्टीज वगैरह में खर्च कर दे उसी तरह से खर्च कर दें....

एक माननीय सदस्य : हार्ट फेल हो जाय।

श्री चन्दनमल वैद : हार्ट फेल तो मन्त्री महोदय का नहीं होगा। हमें देखना चाहिये कि जितनी रिज़र्व कर सकते हैं उतनी रिज़र्व करनी चाहिये, बिना इस बात की परवाह किये कि रूरल या अर्बन एरिया रह जायेगा। हमें देखना यह चाहिये कि औद्योगीकरण या उत्पादन में हम किस तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं? बिजली ले जाने से जहां ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है वहां उस जगह ले जाना चाहिये।

एक बात की ओर मैं मन्त्रीजी का ध्यान और आकर्षित करूंगा। इस रिपोर्ट में यह बात है कि तारानगर में बिजली लगेगी। भाखरा से नोहर को जा रही है उसमें से तारानगर को भी देंगे। मुझे खुशी है कि तारानगर में बिजली देंगे, यह मेरी कॉन्स्टी-ट्यूएन्सी में है और मुझे वहां के लोग धन्यवाद

(श्री चन्दनमल वैद)

दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके धन्यवाद से न तो मेरा भला होने वाला है न मन्त्री महोदय का....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : वोटर्स का।

श्री चन्दनमल वैद : I don't care all the time for voters. I also care for the State.

श्री श्रीभानसिंह : Then please withdraw all the electricity...

श्री जगदीशप्रसाद : (अश्रव्य)

श्री चन्दनमल वैद : Thank you, if you were in the Election Board, but I am glad you are not.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : You are glad that Shri Nathu Ram is in the Election Board.

श्री चन्दनमल वैद : I am glad that he is not your friend.

मैं यह बताना चाहता हूँ कि जहां तारानगर को बिजली देंगे वहां तारानगर और नोहर के बीच जो लाइन जा रही है उसके बीच में ऐसा स्थान है जहां पानी ५०-६० फीट गहरा है। वहां अगर पानी उपलब्ध कर सकते हैं तो रबी की फसल पैदा कर सकते हैं। मैंने पता लगाया है, वहां अगर ज्यादा बरसात होती है तो लोग उपज करते हैं और लाखों मन अनाज हो सकता है। आज भी हजारों बीघा जमीन वहां पर जोती जाती है। मैं चाहता हूँ कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करें तो यह हो सकता है कि गांवों में जहां दो फसलें हो सकती हैं और जहां के खेतों को उपजाऊ कर सकते हैं और लाखों मन अनाज पैदा कर सकते हैं वहां पहले बिजली देनी चाहिये। जहां नहर आती है वहां पैदावार वैसे ही बढ़ जाती है लेकिन जहां नहर नहीं आती है और बिजली के जरिये से कुओं से पानी निकाल सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं वहां बिजली पहले देनी चाहिये ताकि खाद्यान्न का उत्पादन ज्यादा हो सके। इसी तरह से, मान लीजिये ऐसी जगह बिजली ले जा रहे हैं जहां माइन्स या इन्डस्ट्रीज़ हैं, वहां पहले ले जानी चाहिये। जैसे श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया था कि खेतड़ी में कोपर माइन्स हैं और उसका वहां काफी स्कोप है, हमें खुशी है कि वहां कोपर का काफी स्कोप है। जहां माइन्स, इन्डस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं वहां बिजली पहले ले जानी चाहिये बनिस्पत इसके कि सेन्टि-मेन्टल, भावनाओं के कारण गांवों में ले जावें। जहां तक हमारे साधन सीमित हैं वहां तक एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन या इन्डस्ट्री को बढ़ा सकते हैं वहां पहले ले जानी चाहिये बिना इस बात का ख्याल किये कि लोग क्या कहेंगे। हमारे पास जितने सीमित साधन हैं उनसे अधिक से अधिक उत्पादन शक्ति कैसे बढ़ सकती है, इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं इस बात की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को चम्बल से

(श्री चन्दनमल वैद)

बिजली मिलती है। उसी तरह से पंजाब और राजस्थान को भाखरा से बिजली मिलती है। मध्य प्रदेश को चम्बल से जो बिजली मिलती है उसकी रेट्स उन्होंने अनाउन्स कर दी हैं और पंजाब के बारे में जहां तक मालूम है भाखरा से मिलने वाली बिजली के सिलसिले में कन्सेशनल रेट्स अनाउन्स कर दी हैं। लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है। जो रेट्स मध्य प्रदेश सरकार की देखने को मिली हैं उनसे मालूम हुआ है कि वहां जो इन्डस्ट्रीज हैं उन इन्डस्ट्रीज को ५ से ११ नये पैसे में देते हैं, इसी तरह एग्रीकल्चर के लिए देते हैं। जिस तरह जिनकी खपत होगी उसका एक ग्रेडेशन बना दिया है। इसी तरह एग्रीकल्चर और इन्डस्ट्रीज के लिए पांच पैसे से साढ़े ग्यारह पैसे तक देनी है। इसके अलावा लाइट एन्ड फेन, डॉमेस्टिक यूज़ के लिए जो लाइट ले रहे हैं, उनको २८ नये पैसे के हिसाब से दे रहे हैं। राजस्थान में भी आप रेट्स का रेशनलाइज़ कर सकते हैं, जो भाखरा और चम्बल से बिजली आये उसमें आप कन्सेशन दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्रीजी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि पाली के प्राइवेट पॉवर हाउस को मुनाफा है। उसका क्या कारण है कि राजस्थान सरकार बिजली देगी, उसमें मुनाफा न हो। मैं समझता हूँ कि पाली में साढ़े नौ आने चार्ज कर रहे हैं और वह प्राइवेट पार्टी इस दृष्टिकोण से पॉवर हाउस चला रही है कि पाली में जो इन्डस्ट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट हो या नहीं, उनको तो मुनाफे से मतलब है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाली में एक प्राइवेट आदमी कर रहा है, यह काम राज्य सरकार नहीं कर सकती। यह जरूर देखना होगा कि जो बिजली उपलब्ध कर रही है राज्य सरकार उससे इन्डस्ट्रियल प्रोड्यूस कितना हो सकता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। इस तरह मैं अर्ज कर सकता हूँ कि हमें निश्चित रूप से कन्सेशनल रेट्स अनाउन्स करनी चाहिए और मैं समझता हूँ वे रेट्स किसी भी हालत में मध्य प्रदेश और पंजाब से ज्यादा नहीं होनी चाहिए; क्योंकि अगर ज्यादा करेंगे तो निश्चित रूप से एग्रीकल्चर और इन्डस्ट्रीज़ पर असर पड़ेगा। इतना कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : सभापति महोदय, आज बिजली विभाग का जो बजट पेश हुआ है उस पर बहस हो रही है। उसके सम्बन्ध में एक-दो शब्द निवेदन करना चाहता हूँ। दौसा से लालसोट तक बिजली देने का प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया था, लेकिन अब तीसरी पंचवर्षीय योजना चालू होने वाली है, वहां बिजली अभी तक नहीं दी गई है।

हमारे सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय से एक 'आजकल' नाम से किताब निकली है....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : कब की है?

श्री प्रभुलाल पुरोहित : "आजकल।"

डॉ० बहादुरसिंह : किताब कब की है ?

श्री प्रभुलाल पुरोहित : १५–५–६० ।

श्री सभापति : आप भाषण आरम्भ रखिये ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : उसके अन्दर बताया गया कि दिसम्बर ६० से जयपुर में ५,००० किलोवाट का एन्जिन चालू हो जायेगा और उससे बिजली दौसा और लालसोट को दे दी जायेगी । वह एन्जिन चालू हो गया लेकिन अभी तक बिजली नहीं दी गई । मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में मन्त्री महोदय ने बताया कि बिजली माधोपुर से दी जायेगी । गंगापुर में पांच से ११ इन्जिन काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक खम्भे भी नहीं गाड़ सके हैं । ऐसा सुना था कि १९५९ में बिजली मिलेगी, फिर कहा १९६० में मिलेगी । अब कह सकते हैं कि अक्टूबर १९६१ तक मिलेगी । ऐसी धीमी रफ्तार से काम चल रहा है तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अक्टूबर १९६१ में भी बिजली दे दी जायेगी ? मैं बताऊं कि मैं दिल्ली में प्रदर्शनी देखने गया था। वहां पर राजस्थान की स्टाल में एक बोर्ड लगाया हुआ था, उसमें बताया था कि लालसोट से गंगापुर तक बिजली दे दी गई है । ऐसा झूठा प्रचार करते हैं, वहां पर बिजली आज तक नहीं दी गई है....

डॉ० बहादुरसिंह : कांग्रेस हार गई होगी ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : वह विरोधी क्षेत्र है, इस वजह से बिजली नहीं दी जाती है, सरकार सौतेला व्यवहार करती है । मैं बताऊं कि लालसोट की नौ हजार जनसंख्या है, वहां पंचायत समिति है, थाना है और चौकियां लगी हुई हैं । इसके अलावा वहां बेकारी काफी है । अगर वहां बिजली पहुँच जाय तो बहुत से लोग काम पर लग सकते हैं । मैं बताना चाहता हूँ कि लालसोट से दौसा और गंगापुर तक खम्भे लगे हुए हैं लेकिन तार नहीं खींचे गये हैं । जब हम कहते हैं तो वे कहते हैं कि तार चोरी चले जाते हैं । अब सुनने में आ रहा है कि माधोपुर से बिजली हमारे गंगापुर में दी जायेगी, लालसोट में बिजली नहीं दी जायेगी । मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है ? जब दूसरे क्षेत्रों में सब तरह की सहूलियतें दे सकते हैं तो लालसोट क्षेत्र तथा और क्षेत्रों ने ऐसा क्या किया है कि उनको बिजली नहीं मिल सकती ? इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि एक मोरी बांध बना हुआ है, उस पर ४२ लाख का खर्चा किया गया है । योजना यह थी कि २५ हजार एकड़ की पिलाई करेंगे लेकिन उससे केवल ५ हजार एकड़ की पिलाई होती है । जहां सरकार को इससे ३० हजार की आमदनी हो सकती थी वहां केवल ५ हजार की इन्कम है । इस तरह इस क्षेत्र को न पानी दिया जाता है न बिजली वहां लगाई जाती है, जब कि बिजली लगाने से कितनी ही इन्कम हो सकती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्दी ही बिजली लगाई जाय ।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : पंचायत का उल्लेख नहीं आयेगा ।

श्री सम्पतराज जैन : अच्छा । सभापति महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का १९६१–६२ का बजट इस सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है । उसको देखने से पता लगता है कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुदृढ़ होती जा रही है । १९५८–५९ में जहां राजस्व लेखे में १३५.८५ प्राप्त हुए वहां इसमें १९६१–६२ में २७६,८३ लाख का अनुमान किया गया है । कार्यवाहक व्यय में जहां १९५८–५९ में १५४.४३ लाख का प्रावधान किया गया वहां १९६१–६२ में २७४.३२ लाख कूंता गया है । इसी तरह से १९५८–५९ में १८.५८ का घाटा था वहां १९६१–६२ में २.५१ लाख का मुनाफा बताया गया है । यह स्थिति बताती है कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती जा रही है और प्रगति पथ पर है ।....

श्री श्रीभानसिंह : बधाई दे दें ।

श्री सम्पतराज जैन : आप बोलने दें । अभी से क्यों गड़बड़ी करते हैं ?

श्री श्रीभानसिंह : बधाई दे दें ।

श्री सम्पतराज जैन : बधाई दे दूंगा । वैसे यह बधाई है और क्या है ?

माननीय सभापति महोदय, यह जो राजस्व आय में, राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है इसका मुख्य कारण है कि भाखरा नांगल और चम्बल परियोजनायें पूरी हो जाने के कारण बिजली मिलने लग गई है । यह वृद्धि का कारण है । मैं निवेदन करूंगा कि जहां पर हमें इस रिपोर्ट के अन्दर बताया गया है कि चम्बल परियोजना से, हमें गांधी सागर से ३४,५०० किलोवाट बिजली प्राप्त हुई है, और भाखरा–नांगल से ४,६०० किलोवाट बिजली प्राप्त हुई है । इसकी जो आमदनी दी गई है, १९६०–६१ का जो संशोधित बजट है उसमें भाखरा की ४,६०० किलोवाट बिजली का ७,९८,०४० की आय बताई है और चम्बल प्रोजेक्ट, गांधी सागर की ३४,५०० किलोवाट बिजली से २,९७,५०० की आय हुई है । मैं समझता हूं कि जब हमें भाखरा-नांगल से चम्बल परियोजना के द्वारा करीब आठ गुनी बिजली प्राप्त हुई है तो उससे आमदनी चौथाई भी क्यों नहीं प्राप्त हुई ? इसका खास कारण यही हो सकता है कि चम्बल परियोजना गांधी सागर से नवम्बर से बिजली प्राप्त हुई । अगर ३४,५०० किलोवाट बिजली की खपत कर सकते तो निश्चित तौर पर आमदनी अधिक होती, राजस्व में प्राप्ति २,९७,५०० की बताई गई है, वह बढ़ी हुई होती । इससे साफ प्रगट है कि जितनी बिजली उपलब्ध गांधी सागर से हुई उसकी खपत नहीं कर सके । अगर कर सके होते तो निश्चित रूप से आमदनी चौगुनी, पचगुनी होती । इसका खास कारण है कि जितनी बिजली प्राप्त हुई वह खपत नहीं हुई । खपत न होने का मुख्य कारण यह है कि पहले तो हम लाइन न बिछा सके । दूसरा कारण यह है कि छोटे–मोटे उद्योग–धन्धे, जब गांधी सागर बन रहा था, उस समय हम तैयार नहीं कर सके, लगा नहीं सके ।

तीसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर का ठीक तरह से सर्वे नहीं कर सके हैं । यदि इन

(श्री सम्पतराज जैन)

तीन बातों की तरफ ध्यान देते तो जो बिजली गांधी सागर से प्राप्त हो रही है उसकी निश्चित रूप से खपत हो जाती, राजस्व में भी हमें ज्यादा प्राप्ति होती और राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो आज स्थिति है उससे अधिक सुदृढ़ होती। यह नहीं हुई है। इसके कारण मैं अर्ज कर चुका हूँ। यह जो स्थिति हमारे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है उसको निश्चित रूप से सुधारा जा सकता है। मैं आशा करता हूँ मन्त्री महोदय से और संचालक महोदय से कि वे इसमें सुधार करेंगे। जहां तक बिजली की खपत होने का सवाल है हमारे शहरों में पहले से ही पॉवर हाउसेज लगे हुए हैं। ऐसी दशा में शहरों में जहां तक हाइड्रो इलेक्ट्रिक देने का सवाल है इतना ही है कि यह बिजली थर्मल पॉवर हाउसेज से सस्ती पड़ेगी। पर हमें यह देखना होगा कि हमारे राजस्थान की ८० फी सदी जनता देहातों में बसी हुई है और देहातों का मुख्य धंधा कृषि है। ऐसी दशा में कृषि की उन्नति जब तक नहीं होती हमारे प्रान्त की, हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकती। फिर हमें यह भी देखना होगा कि देहातों की आमदनी से शहरों की आमदनी १३ गुना अधिक है। देहात में यदि १ रु० आमदनी है तो वह शहर में १३) रुपया है। जब शहरों में रहने वालों की इतनी आमदनी है और गांवां में रहने वालों की उनसे इतनी कम आमदनी है तो इस लिहाज से भी बिजली के पाने के लिए गांवां वाले शहर वालों से पहले हकदार हैं।

आज हमारे देश को यदि सबसे अधिक किसी चीज की आवश्यकता है तो वह है उत्पादन बढ़ाने की। उत्पादन बातों से नहीं बढ़ाया जा सकता, उत्पादन तो कृषि को बढ़ाने से, इन्डस्ट्रीज को बढ़ाने से ही बढ़ेगा और जब तक गांवों में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये, छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज से, और और उत्पादन बढ़ाने के लिये गांवों को बिजली नहीं मिलेगी तब तक हमारे प्रान्त का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। गांवों में गरीब पब्लिक बसती है। जब तक गांवों को बिजली नहीं मिलती तब तक गांवों की गरीबी दूर नहीं हो सकती। आज सारे देश की जन-संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे राजस्थान की भी करीब २५ या ३० लाख आबादी बढ़ी है। ऐसी दशा में केवल कृषि से हो हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकतीं। हमारी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये गांवों में छोटे छोटे उद्योग धंधे खोलने की आवश्यकता है। हमें छोटे छोटे उद्योग–धंधे देहातों में खोलने पड़ेंगे और यदि यह सब किया जाय, उत्पादन को बढ़ाने के लिये गांवों में बिजली दी जाय तो गांवों में बिजली की काफी खपत हो सकती है। एग्रीकल्चर और छोटे छोटे उद्योग–धंधों में गांवों में बिजली की काफी खपत हो सकती है। पहले से जो बिजली हमें मिल रही है उसके अलावा अतिरिक्त बिजली गांधी सागर से हमें प्राप्त होने वाली है। कुल मिला कर ४६ हजार किलोवाट बिजली हमें मिलने लग जायेगी। जब मौजूदा बिजली ही नहीं खप रही है तो गांव वालों का पहला नम्बर है कि उनको सबसे पहले कृषि व छोटे छोटे उद्योग धंधों की तरक्की के लिये बिजली दी जाय। मद्रास में कुल २४ हजार गांव हैं। उनमें से १२ हजार गांवां में बिजली लगा दी है। तो

(श्री सम्पतराज जैन)

इस तरह मद्रास में ५० प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है। राजस्थान में देखा जाय तो ५ प्रतिशत गांवों में भी बिजली नहीं पहुँची है। यह राजस्थान का और खास तौर से ग्रामीण जनता का दुर्भाग्य है कि वहां बिजली नहीं पहुंच रही है। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार और मंत्री महोदय कृत संकल्प हो कि गांवों में बिजली पहुंचा कर गांवों के कृषि उत्पादन और इन्डस्ट्रीज की तरक्की करें। इस बजट में २४.१० लाख रुपया देहातों में लगाने के लिये रखा है। कुल बजट २. ७४ करोड़ का है उसमें से केवल करीब २५ लाख रुपया देहातों में विद्युतीकरण के लिये रखा जाय, यह नगण्य है।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि देहातों को बिजली देने के मामले में प्राथमिकता दी जायेगी तो हमारा कृषि उत्पादन बढ़ेगा, छोटी २ इन्डस्ट्रीज से और उत्पादन बढ़ेगा, हमारे देहातों की गरीबी मिटेगी और राजस्थान दिन–ब–दिन तरक्की करेगा।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : सभापति महोदय,....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : एक ही जगह के दो दो....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आप भी झालावाड़ की ही बात कहेंगे ?

श्री रामचन्द्र : झालावाड़ की आंखों देखी बातें कहूँगा, आप सुनी सुनाई कहते हैं।

सभापति महोदय, यह राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का तीसरा बजट है। आज से तीन वर्ष पहले का वह दिन याद है जब राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपना बड़ा घाटे का बजट पेश किया था और उस समय विधान सभा के प्रत्येक सदस्य ने वेहिमेन्टली उसको क्रिटिसाइज किया था। वह तो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की ही शक्ति थी कि उस क्रिटिसज्म को उन्होंने सहन किया। इसके दूसरे बजट में पहले के घाटे से ५० प्रतिशत कम घाटा दिखाया गया तो उस समय आशा हुई कि यह बोर्ड आगे जाकर घाटे के बजाय मुनाफे में बदल जायेगा। तो आज इस बात की खुशी है कि हम जिस दिन की आशा कर रहे थे कि हमारे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट घाटे की बजाय नफे का हो वह दिन आज आ गया है। इसके लिये राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी हैं उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।....

श्री चन्दनमल वैद : मंत्रीजी को दें।

श्री रामचन्द्र : ठीक है, मंत्रीजी की तो कृपा है।

श्री चन्दनमल वैद : यह धन्यवाद उनको मंत्रीजी की मार्फत ही जायेगा।

श्री रामचन्द्र : चम्बल की और भाखरा

(श्री रामचन्द्र)

की बिजली आ गई, पर इस वक्त वह उसी स्टेज पर है जैसे कि चम्बल की सिंचाई को नहरें बन कर गांवों में होकर निकल गईं, पर गांव के लोगों ने उनके जल से खेतों को फायदा पहुंचाने का प्रयत्न नहीं किया। ठीक वही हालत आज बिजली की धारा की है। गांधी सागर डेम से भवानी मंडी, झालावाड़ रोड़ होती हुई झालावाड़ के गांवों में से गुजर कर आई है, तो जिन गांवों में से गुजर कर आई है उन गांव वालों को अभी तक फायदा नहीं पहुंचा है। इसका कारण यह है कि बिजली तो आई पर बिजली विभाग ने इस बात का सर्वे कराने का प्रयत्न नहीं किया कि गांव वालों को किस तरह इसका फायदा पहुंचावें। अब इस बात का प्रयत्न जिला परिषद् और पंचायत समितियों के स्तर पर किया गया है और इस बात की सर्वे कराई जा चुकी है कि गांव वालों को बिजली की कितनी आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा कि बिजली आ जाने से किसानों के हृदय में बिजली की लहर जैसी पहुंची है....

डॉ० बहादुरसिंह : बिजली की लहर हृदय में पहुंचने से तो बड़ी गड़बड़ हो जायेगी।

(४. म० प०)

श्री रामचन्द्र : इसी तरह वे बराबर इस बात की इन्तजार में हैं कि कब यह बिजली उनके कुओं तक पहुँचे। पर कुछ ऐसी टैक्निकल बात आ जाती है कि बिजली विभाग बड़े असमंजस में पड़ा हुआ है कि कैसे यह बिजली कुओं में पहुँचाई जाय। गांव वाले इसको समझने में बड़े अशक्त रहते हैं और बिजली विभाग गांव वालों को समझाने में असफल रहा है कि कैसे बिजली का उपयोग करें। गांव वालों में बिजली को लोकप्रिय बनाने के लिये विभाग को चाहिये कि जिन-जिन गांवों में से बिजली गई है उतने ही सब स्टेशन्स बनाकर वहां बिजली पहुँचायें, ताकि गांव वाले देखेंगे कि बिजली आ जाने से कितनी सुगमता सिंचाई में आ गई है और समझ जायेंगे कि सब–स्टेशन से कुएं तक ले जाने में कितना खर्चा आयेगा। तो मैं चाहूँगा कि बिजली के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये सब–स्टेशन प्रत्येक जिले में कायम किये जायं ताकि किसान वहां जाकर देखें और अनुभव करें कि बिजली से सिंचाई में कितनी सुगमता होती है। इस तरह किया जाय तो सिंचाई क्षेत्र में काफी लाभ हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं इस बात का निश्चित रूप से विश्वास कर चुका हूँ कि राजस्थान में जिन जिन भागों में बिजली पहुँच रही है उन गांवों में सिंचाई और इन्डस्ट्रीज़ के लिये बिजली का प्रयोग किया जायेगा और इसके लिये आगे जाकर इस विभाग को बहुत टैक्निकल आदमियों की आवश्यकता होगी। क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है और निश्चित रूप से मानने की बात है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और सार्वजनिक निर्माण विभाग ऐसे विभाग हैं जो टैक्निकल कहे जा सकते हैं। किसी हद तक इर्रिगेशन डिपार्टमेंट को भी टैक्निकल मान सकते हैं पर इन विभागों में जो काम करने के लिये रखे जाते हैं वे टैक्निकल हैं्स नहीं होते, साधारण आदमी होते हैं, उनको अनुभव

(श्री रामचन्द्र)

नहीं होने के कारण मशीनों में गड़बड़ हो जाती है और सरकार जितनी अपेक्षा फायदे की करती है उसके बदले नुकसान हो जाता है। तो आगे जाकर ऐसे टैक्निकल आदमियों की बिजली विभाग और राजस्थान सरकार को बड़ी तादाद में आवश्यकता होगी। तो प्रत्येक जिले में या प्रत्येक डिविजन में इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट खोलने चाहिये, ताकि गांव गांव में बिजली फैले तो गांवों के लोगों को इस प्रकार का शिक्षण दे सकें।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक बात और कहना चाहता हूं। वह यह है कि जिस प्रकार और और विभाग खर्च की ओर विशेष ध्यान नहीं देते उसी तरह इस विभाग को भी इस मामले में मैं उतना ही लापरवाह समझता हूं।

प्रायः हम देखते हैं कि बहुत से रुपये गलत खर्च कर दिये जाते हैं और कुछ चीजों का जितना फायदा उठाना चाहिये नहीं होता। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बारे में विभाग बराबर ध्यान रखे और हर एक काम में इस बात का पूरा ध्यान रखा जावे कि कम से कम खर्च हो और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हमको मिल सके।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विद्युत बोर्ड का १९६१–६२ का बजट सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है। इस सम्बन्ध में मैं भी अपने थोड़े से विचार रखना चाहती हूं। निश्चय ही राजस्थान विद्युत मंडल का निर्माण हमारी सरकार का एक दूरदर्शितापूर्ण कदम है। इसको अब बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं। इस विद्युत मण्डल ने इस थोड़े से समय में जिस प्रकार का कार्य किया वह अवश्य ही इसकी सफलता का सूचक है। लेकिन मैं इस बजट को हानि या लाभ की दृष्टि से देख कर विद्युत् मंडल को सफलता नहीं आंकती हूं। हमें इसमें यह देखना होगा कि विद्युत् मंडल ने ज्यादा से ज्यादा बिजली जनता को देने का प्रयास किस तरह से किया है और वह उसमें कितना सफल हुआ है क्योंकि विद्युत् के विकास पर ही राजस्थान के विकास का सवाल है। मैं यह कहूंगी कि हम इस दिशा में बहुत कम आगे बढ़े हैं और इसको हम अच्छी तरह से महसूस करते हैं फिर इसमें अभी और ज्यादा से ज्यादा विस्तार की आवश्यकता है। सदन में बहुत अच्छी तरह से पहले बताया जा चुका है कि विद्युत् की कितनी आवश्यकता है। हम सब यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि विद्युत् का उपयोग और लाभ अपेक्षाकृत दृष्टि से हमारी योजनाओं को सफल बनाने में कितना सिद्ध होगा। हमारे छोटे बड़े उद्योग–धन्धों और खनिज आदि का विकास इसी विद्युत् पर आधारित है। इसलिये हमारे यहां इस विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें किस प्रकार से अपने विकास में योग दे सके।

जहां तक इसके उत्पादन और वितरण का सवाल है, उत्पादन में अच्छी गति हुई है, लेकिन इसमें और अधिक गति लाने आवश्यकता है, क्योंकि जो चम्बल से बिजली मिलनी चाहिये थी उसका इस समय तक हम उपयोग नहीं कर पाए हैं। इसके

(डॉ० चन्द्रकला)

समय पर उपलब्ध नहीं होने से हमारी कठिनाइयाँ रही हैं।

इसके साथ ही बिजली की दरों की असमानता का उल्लेख यहां किया गया है। सभापति महोदय, जितना जल्दी इसको दूर कर सकें, इसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। भले ही जिनको आराम के लिये बिजली की आवश्यकता हो, जैसे रेफरीजरेटर या हीटर या फैन्स आदि के लिए जरूरत हो, उनके लिये दरें थोड़ी अधिक रखी जावें तो भी कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कृषि के लिये यदि बिजली सस्ती दर पर नहीं दी जा सकेगी तो बिजली का ज्यादा लाभ नहीं होगा, यह हमें मानना पड़ेगा। इस दृष्टि से देखें तो यह विभाग कृषि की मांग को पूरा नहीं कर पाया है और मुझे इसका अनुभव है। जयपुर से थोड़ी दूर पर कुएं हैं। उनको पहले रात को पानी निकालने के लिये बिजली मिलती थी, मगर आज–कल इनको दिन में बिजली मिलती है इसलिये कुछ वृद्धि तो इसमें हुई है और किसानों को थोड़ी राहत मिली है लेकिन हमें देखना होगा कि उनको बिजली सब को समय पर मिलती है या नहीं और वे अपने खेतों को पानी समय पर दे सकते हैं या नहीं।

माननीय मन्त्री महोदय ने समाजवादी समाज व्यवस्था के लिये बिजली के साधनों में वृद्धि का होना आवश्यक बताया लेकिन, जब हम वितरण करते हैं तो हमें यह देखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा जनता को बिजली का लाभ देते हैं या नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो कह सकते हैं कि समाजवादी समाज की व्यवस्था पूरी हो रही है। लेकिन हम बिजली के वितरण में असमानता पाते हैं। अगर माननीय मन्त्री जरा सिविल लाइन्स से आगे टहलने जावेंगे तो उन्हें महसूस होगा कि ग्रामीणों की ऐसी बस्तियें हैं, बड़ी बड़ी बस्तियें हैं जहां बिजली का नाम निशान भी नहीं है। उनके क्षेत्र से होकर हजारों बड़े बड़े खंभे जाते हैं मगर गांव वालों को बिजली नहीं मिले, यह बड़े दुःख की बात है।

मैं यहां अब एक बात की ओर विद्युत् मंडल का ध्यान, सभापति महोदय, आपके द्वारा आकर्षित करना चाहती हूँ कि इसका काम बहुत धीरे–धीरे चलता है और रेड–टेपिज्म इसमें बहुत है। ढीलम ढाल की जो नीति चल रही है वह उचित नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगी कि बहुत सी नगरपालिकाओं ने विद्युत् के लिये बहुत समय हुआ पैसे जमा कर दिये हैं और अन्य दूसरे उपभोक्ताओं ने भी पैसे जमा करा दिये हैं और उनको आज साल और छः महीने का समय हो गया है मगर फिर भी बिजली नहीं मिल रही है। यह बड़े अफसोस की बात है। इस सम्बध में विद्युत् विभाग ने कोई तत्परता नहीं दिखाई है। हां, यह विभाग बिजली का कनेक्शन काटने में बहुत तत्परता दिखाता है। कनेक्शन देने में तत्परता नहीं करता, कनेक्शन काटने में वह इस बात का भी ध्यान नहीं रखता कि कुएं पर फसलें खड़ी हैं और बिजली के कनेक्शन काट देने से फसलों को नुकसान हो जावेगा। इसलिये मैं यह कहूंगी कि हमारा एक मात्र बिजली उत्पादन का ही लक्ष्य नहीं होना चाहिये, इसके साथ साथ वितरण का भी ध्यान होना चाहिए।

Page No 98

(डॉ० चन्द्रकला)

हमको हमारे यहां जयपुर शहर का खराब अनुभव है। जयपुर शहर में व्यक्ति ही सब कुछ कार्यवाही कर देते हैं और हमारा विभाग शांत रहता है। जहां पर नगरपालिकाएं पैसे जमा करा चुकी हैं और फिर भी कार्यवाही नहीं होती है, यह बड़े दुःख की बात है। जब जयपुर शहर का यह अनुभव है तो मैं समझती हूँ कि दूसरी जगह का भी यही हाल होगा। यह हमारे माननीय मन्त्री महोदय का उत्तरदायित्व है। विद्युत मन्डल के वे मन्त्री हैं, वे देखें कि जो बिजली पैदा होती है और उसमें जितना रुपया लगता है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ जनता को मिले और प्रान्त को उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, जिससे हमारे प्रान्त में उद्योग–धन्धों का विकास हो।

अब मैं सदन का अधिक समय न लेती हुई विद्युत मण्डल को पुनः बधाई देती हुई यही कहूंगी कि उत्पादन के साथ ही समुचित वितरण की ओर भी अधिक से अधिक ध्यान दिया जायेगा। इसी आशा के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–मु०) : सभापति महोदय,

श्री सभापति : आप कितना समय लेंगे ?

श्री लादूराम सुलाणिया : १५ मिनट।

श्री सभापति : आप ४ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री लादूराम सुलाणिया : सभापति महोदय, आज हमारे सामने विद्युत् विभाग का बजट है। सरकार हर साल इस पर मोहर लगाती आई है और आज भी लगावेगी। ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ कमी करें या कुछ तरमीम करें या टालम–टोल करें, यह बात नहीं है, लेकिन....

एक माननीय सदस्य : शिड्यूल्ड कास्ट के लिये कोई बात कहते हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया : होता यह है कि इसमें जो खराबी होती है, उसको माननीय सदस्य सरकार के सामने रखें। इस मौके पर रखें और माननीय मन्त्री महोदय इस पर विचार करें कि माननीय सदस्य जो सुझाव देते हैं वे दरअसल उपयुक्त हैं या नहीं और उनकी जांच होने के बाद में प्रबन्ध हो तो कार्य अधिक सफलता से हो सकता है, पब्लिक को अधिक लाभ हो सकता है, ऐसा मेरा विचार है। मैं इसके साथ साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली विभाग से जितना मुनाफा होना चाहिये नहीं हुआ है। सरकार को जो मुनाफा होना चाहिये उससे अधिक खर्चा करने का मौका मिलता आया है। पिछले दिनों में यह देखने में आया है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि आगे भी इसमें इसी प्रकार की बात मिलती रहेगी....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इसमें तो मुनाफा ही इस साल में है।

श्री लादूराम सुलाणिया : यह गलत बताया गया है।

डॉ० बहादुरसिंह : आपका कौनसा बजट है जिससे आप बतावेंगे ?

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं आपको नहीं बताऊंगा !

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : यह आपको कैसे बतावेंगे । वह तो गृहिणी को बताया जाता है ।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं यह निवेदन करूंगा कि फिर भी घाटा होता है तो राजस्थान के भाग्य की बात है और मैं यह कहूंगा कि यह घाटा क्यों होता है और मुनाफा क्यों नहीं होता है । इसका छोटा सा कारण है, इसका बड़ा कारण नहीं है जिससे हम घाटे में जा रहे हैं ।

मैं थोड़े शब्दों में निवेदन करूंगा कि हमारे विभाग में जितने कर्मचारी काम करते हैं उसमें दो तीन श्रेणियें हैं ! काम करने वाले लोग इंजीनियर और उनके नीचे लेबर हैं । लेबरर्स इतने कम रखते हैं कि वे काम पूरा नहीं कर पाते । ८ घंटे जहां काम उनसे लेना चाहिये बजाय उसके उनसे दस दस और बारह बारह घंटेकाम लिया जाता है । उनको उसका ओवर टाइम मिलता नहीं है और विशेष भत्ता भी नहीं मिलता है ! ऐसे मजदूर होते हैं....

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मन्त्री) : आपके पास ऐसा कोई प्रमाण है क्या ?

श्री लादूराम सुलाणिया : सुझाव इसलिए दे रहा हूँ कि इसकी जांच की जाय तो आपको इसका पता चल जायेगा और यदि माननीय मन्त्री चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो तो जैसे पुराने जमाने में राजा–महाराजा वेश बदल कर रात्रि को जाते थे उसी प्रकार से आप भी जावें....

(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र : मौका दें ।

श्री लादूराम सुलाणिया : रात को मेरे साथ चलिये और वेश बदल कर चलिये और फिर आप जाकर वहां पर टाइम नोट कर लीजिये और फिर देखिये कि उनको मिलता है या नहीं ।

(शोरगुल)

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री लादूराम सुलाणिया : तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि....

डॉ० बहादुरसिंह : ये तो वेग चार्जेज़ हैं, माननीय सदस्य को इसके लिए प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिये ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सदस्य महोदय कहते हैं कि ले जावेंगे....

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा : रात के वक्त कहां ले जावेंगे ?

(शोरगुल)

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री लादूराम सुलाणिया : तो मैं निवेदन कर रहा था कि जिस जगह एक इन्जीनियर का काम है वहां पर चार चार इन्जीनियर लगाये गये हैं और वे उस ढंग के होते हैं कि जो खंभे पर भी नहीं चढ़ सकते। एक ले मैन को उन खम्भों पर चढ़ाया जाता है। मजदूरी का तो डेढ़ रुपया देते हैं लेकिन कई ऐसे केसेज़ हुए हैं कि गरीब लोग इस तरह से खंभों पर चिपक कर मर जाते हैं।

(शोरगुल)

इसलिए मैं कह रहा था कि बजट घाटे का है लेकिन बताते हैं मुनाफे का और वह कैसे हो जाता है, मजदूर १॥) रु. के लेने वाले रखे जाते हैं, कम रखे जाते हैं और जो ५००) रु. के माहवार के लेने वाले इन्जीनियर्स हैं वे अधिक रखे जाते हैं। कम तो वे काम करते हैं और खर्चा अधिक करते हैं। इसलिए बिजली के अनुपात में खर्चा तो अधिक होता है और आय कम होती है।

इसके साथ साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार की ढिलाई है और उसके लिए एक–दो उदाहरण देना चाहता हूं। सन् ५८ में विद्युत् मन्त्रीजी ने बताया था कि जमुआ रामगढ़ लाइन को सन् ६० तक तो पूरा कर दिया जावेगा। वह लाइन वैसी की वैसी है सन् ६१ तक भी। माननीय मन्त्रीजी बदल गये। यदि आप स्वयम् चाहें तो जाकर मुआयना कर सकते हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): लाइन आपके शायद घर पर से होकर जाती है।

श्री लादूराम सुलाणिया : खतरे की चीजों को भी हटाने की व्यवस्था नहीं है। जिन चीजों से हर समय खतरा हो सकता है उसके लिए मन्त्री महोदय आश्वासन दें और फिर भी उसको पूरा न कर पायें, यह एक बड़ी समस्या है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापतिजी, अभी तो दो मिनट ही नहीं हुए।

श्री सभापति : ७ मिनट ले लिये हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया : पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री सभापति : दो मिनट और मिलेंगे।

श्री लादूराम सुलाणिया : मेरा टाइम तो इन लोगों ने ले लिया।

श्री सभापति : You have already taken 7 minutes. Please conclude within 5 minutes.

श्री लादूराम सुलाणिया : सरकार दुहाई देती है कि भाखरा और चम्बल से बिजली मिलेगी। हमको इस बात का विश्वास है कि मिलेगी।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मिल गई है, मिलेगी क्या ?

श्री लादूराम सुलाणिया : आज नहीं; दो साल, पांच साल में मिलेगी।

(श्री लादूराम सुलाणिया)

इसका हमको विश्वास है। मुझे एतराज नहीं है कि नहीं मिलेगी। मिलेगी। जिस मौके पर बिजली चाहिये उस मौके पर तो बिजली मिलती नहीं है।

(शोरगुल)

मिलती है बहुत मेहनत करने के पश्चात्। जब खर्चा करते हैं उस वक्त तो बिजली मिलती नहीं। जयपुर-दूदू में पॉवर हाउस बनाने की योजना सन् १९५० से चल रही है, लेकिन आज तक एक इंजिन तो क्या एक पत्थर तक माननीय मन्त्री महोदय ने जाकर नहीं लगाया होगा। ब्रिटेन की महारानी के आने पर माखरोटा में तीन दिन में बिजली मिल गई। रातों रात काम कराया गया। एक एक लाख रुपया खर्चा हुआ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आप भी महारानी को बुलायें।

श्री लादूराम सुलाणिया : मुझे इसमें आपत्ति नहीं है कि वहां पर बिजली क्यों दी गई ? लेकिन आपत्ति यह है कि बिजली की योजना तो पहले होती नहीं और जब किसी विदेशी मेहमान को बुलाया जाता है तो इस प्रकार से खूब खर्चा करके यह बताया जाता है कि राजस्थान में इस प्रकार की बस्तियां बना रहे हैं, लेकिन वैसे कुछ नहीं। इस पर एक लाख का खर्चा कर दिया। सांगानेर के लोग पम्पिंग सेट के लिए कह रहे थे, मिलने चाहिये थे, पंचायत समिति से मिलेगा, यह कहा गया लेकिन उनको नहीं मिला रुपया। इसके लिए अर्जेन्ट ऑर्डर्स हुए।

श्री बरकतुल्लाखां (उप-मंत्री, विद्युत): What this has got to do with the Electric Department ?

श्री सभापति : He is showing the promptness of the Department.

श्री लादूराम सुलाणिया : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक रात में इतना खर्चा कर दिया जावे और लाइनें खींच कर बाहर के लोगों को यह दिखा दिया जाता है कि राजस्थान में कैसी सुन्दर बस्तियों का निर्माण कर रहे हैं। आज मंत्रीजी वहां जाकर देखें कि क्या वहां पर बिजली जल रही है ? बटन लगाते ही टूंटियों से जहां पानी निकलता था वहां अब पानी निकलता है क्या ? अफसोस इस बात का है कि सरकार दुहाई तो देती है कि बिजली से प्रगति हो रही है। यह केवल दिखावा मात्र है, वास्तविक कुछ नहीं है। बोर्ड बनने के बाद सुविधायें मिली होंगी, लेकिन जिनको सुविधायें मिलनी चाहिये थी उनको तो नहीं मिलीं और जिनको नहीं मिलनी चाहिये थीं उनको मिल गई अधिक। ऐसे प्रमाण मौजूद हैं। विशेष अर्ज न करके यह निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्य बोल रहे थे। जयपुर से दौसा होकर गंगापुर तक लाइन खींची गई। तारों की नहीं, खंभों की। जहां मंत्री लोग बसते हैं वहां तो बिजली भी पहुंच जाती है और आगे नहीं।

एक शब्द कह कर मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जब डिपार्टमेन्ट की व्यवस्था बदली और यह विद्युत् मंडल बना तो ज्यादातर होटलों में यह गय

(श्री लादूराम सुलाणिया)

और उत्साह होता था कि राजा साहब के हाथ में आवेगा तो सस्ती बिजली मिलेगी। लेकिन मैं बताऊं कि उल्टा अब होटलों, बाजारों और गलियों में सुनेंगे कि कुछ नहीं हुआ। जैसा पहले था वैसा ही और आगे भी चलता जावेगा। इस राज्य में भला नहीं मिलने वाला है।

डॉ० बहादुरसिंह : किस होटल की बात है, यह तो बता दें ?

श्री लादूराम सुलाणियां : कहीं जाकर सुन लीजिये। होटलों में वह उत्साह नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति : The Hon'ble Minister for Power to please reply.

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान विद्युत् मंडल के बजट पर माननीय सदस्यों ने जो जो विचार प्रगट किये हैं उसके लिये मैं उनको मेरी ओर से तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कई सुझाव भी बहुत अच्छे आये हैं। उनके बारे में सदन के सामने जैसे जैसे मैं कहता जाऊंगा कुछ हल निकाल कर ही अर्ज करूंगा।

जैसा कि मैंने पहले कहा राजस्थान ने करवट बदली है और करवट बदलने के साथ साथ इस बात की भी आशा लेकर राजस्थान चल रहा है, राजस्थान की जनता चल रही है कि आगे चल कर हमारी तरक्की हो और हमारी माली हालत ठीक हो, हमारा एग्रीकल्चरल और इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़े। जहां तक इन मसलों का सवाल है विद्युत् का बहुत बड़ा हाथ इसकी उन्नति में रहेगा और आज भी है और आगे चल कर भी रहेगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मेम्बरान, इन्जीनियर्स और उनके कर्मचारी एक आर्मी की तरह से डिसीप्लिन्ड तरीके से राजस्थान का फेट हल करने जा रहे हैं और मैं यह कहना चाहूंगा कि हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा और उनके कर्मचारियों द्वारा कि राजस्थान की दिन प्रति दिन तरक्की हो। यह जरूर है कि हमारे सामने कई ऐसी रुकावटें आती हैं जिनसे प्रोग्रेस, जैसी कि माननीय सदस्य चाहते हैं, शायद दिख नहीं पाती। लेकिन इस बात का सन्तोष हमें है कि जितना भी कार्य हमने इस डेढ़ साल में किया है उसके लिये आज इस सदन में एप्रिसियेशन है। यह एप्रिसियेशन हमारे कर्मचारियों के दिल को मजबूत करेगा और वे हमेशा इसी तरह से आगे बढ़ने की को कोशिश करेंगे। जहां तक सन् ६०–६१ के अचीवमेंटस का सवाल है जो ओरीजिनल प्रोविजन था वह ६८.५० लाख का था। उसका रिवाइज्ड एस्टीमेंट सन् ६०–६१ में १०,६७. ३५ लाख का हुआ। अब माननीय सदस्य पूछेंगे कि यह इतना रिवाइज्ड एस्टीमेट इन्क्रीज कैसे हुआ ? इन्क्रीज के दो कारण हैं जो कोमन पूल वर्क्स थे–भाखरा और चम्बल के–उनके एडजस्टमेंट के लिये एलोकेशन हुए हैं। २०३. ७६ चम्बल के कोमन पूल २३५. यानी यह जो अमाउन्ट है उनमें एड हुए हैं। यह जो फर्क दिख रहा है उसके लिये कहा गया कि बजट में कुछ गड़बड़

Page No 103

(श्री हरिश्चन्द्र)

है और क्या क्या है, मैं इस बारे में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये फिक्टीशियस फीगर्स पर बेस्ड नहीं है। जो एडजस्टमेंट नहीं हुये थे उसकी इन्क्रीज आपके सामने बताई गई है।

सेकन्ड प्लान के अन्दर जो वर्क्स थे जिसमें भाखरा कोमन पूल में इन्क्लूडेड है। भाखरा कोमन पूल २०३. ७९ लाख बल्कि सप्लाई ६६ किलोवाट एट अत्रा उलाइन ४१.२२ डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ ३३.११ के० वी० लाइन्स।

चम्बल कोमन पूल वर्क्स २३३. बल्कि सप्लाई एन्ड डिस्ट्रिब्यूशन ३६०.९३.

राणा प्रतापसागर ५ लाख.

टोटल ५९८.९३.

थरमल एन्ड अरबन इलेक्ट्रिफिकेशन	२६.
डेवलपमेंट ऑफ थरमल पॉवर स्टेशन	११९.९८.
अदर स्कीम्स इन्क्लूडिंग सर्वे एन्ड इन्वेस्टिगेशन	१७.२१.
रीहेबीलिटेशन ऑफ प्रा० पॉवर हाउसेज़	१०.
इन तीनों का टोटल	१७६.९७.

इसके अलावा जो अचीवमेंट्स फिजीकल टार्गेट्स है भी पेश करना चाहता हूँ:—

सन् १९६०–६१ में कांकरोली में नया स्टेशन।

टोडा भीम में नया स्टेशन।

डीडवाना में डीज़ल सेट चलाया।

कपासन स्टेशन रेडी फोर बीइंग कमीशन्ड।

इसके अलावा डीज़ल सेट इन्स्टाल्ड वर्तमान पॉवर हाउसेज़ में भालावाड़, डूंगरपुर जोधपुर और शाहपुरा में लगे हैं।

स्टीम सेट्स कमीशन्ड:

जयपुर १ सेट पांच हजार का

जोधपुर दो सेट तीन तीन हजार के

अलवर दो सेट वन थाउजेन्ड ईच

भरतपुर में चार सेट हजार हजार के

१७ हजार के. वी. स्टीम टर्बाइन से जनरेट होगा।

ट्रान्समिशन लाइन एन्ड डिस्ट्रिब्यूशन लाइन के ६०–६१ के अचीवमेंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।

गांधीसागर से कोटा–१२५ के. वी. डबल सरकट लाइन। १९ नवम्बर, १९६० को कोटा डेम का और कोटा बैरेज का हमारे प्रधान मन्त्री द्वारा उद्घाटन किया गया। वे उस समय में चालू हुए। इसके साथ साथ माननीय सदस्यों के सामने यह भी पेश करना चाहता हूँ, यह लाइन जहां ४७ मील की है नोर्मली यह लाइन बार फुटिंग पर नही लेते

Page No 104

(श्री हरिश्चन्द्र)

हैं तो कम से कम छः महीने से भी ज्यादा समय लग जाता। कई आदमियों ने यहां तक भी कहा, यह तो एक साल का काम है, हमारे इन्जीनियर्स ने और वर्कर्स ने रात और दिन एक करके इसमें काम किया। आपने देखा होगा उन्होंने यह लाइन रेकॉर्ड टाइम चार महीने में ही कन्स्ट्रक्ट की है। यह ऐसी चीज है जिसका एप्रिसियेशन सदन को करना चाहिये।

चम्बल एरिया में ३३ के. वी. गान्धी सागर से, रामगंज मन्डी-कोटा-बून्दी ६२ माइल्स की की की गई।

भाखरा में राजगढ़ में सब-स्टेशन कम्पलीट हुआ।

गंगानगर से रायसिंहनगर	५२ मील
गंगानगर से सूरतगढ़	७४ मील
राजगढ़ झूंझनूं	५७ मील
सीकर	५२ मील
राजगढ़-तारानगर	२३ मील
	कुल २५७ माइल

११ के. वी.

रायसिंहनगर से विजयनगर	८ मील
हनुमानगढ़ संगरिया	२२ मील
चिड़ावा सूरतगढ़	•
	कुल ७२ माइल।

कई माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति उठाई कि जहां जहां लाइट दी जाती है वहां फिर से लाइट दे दी, यह कहना बिल्कुल सही है। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि लाइट जो भाखरा से दी जा रही है, जो ट्रान्समिशन लाइन है वह सारी की सारी चेन्ज हो रही है। पुरानी ट्रान्समिशन लाइन पर हेवी लोड चलेगा नहीं। इसलिये जो आंकड़े बताये गये हैं वे चेन्ज के हैं इसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नया काम मान कर चलता है।

अलवर से आने वाली माननीय सदस्या ने दो पोइन्टस रखे थे। पंजाब के बोर्डर विलेजेज़ का यहां से लाइन पास होती है इस सिलसिले में मुझे निवेदन करना है कि राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार और मध्य-प्रदेश सरकार ने एग्रीमेंट किया है। जहां जहां उनकी ट्रान्समिशन लाइन हमारे बोर्डर के पास है वहां हमें सप्लाई करेंगे। अगर हमारी ट्रान्समिशन लाइन उनके बोर्डर के पास से गुजरती है हमारा इस प्रकार का रेसिप्रोकल अरेन्जमेन्ट मध्य प्रदेश और पंजाब गवर्नमेंट के साथ है कि हम उनको बिजली सप्लाई करेंगे।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : यह कितने कितने माइल की दूरी तक देंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : आशा करते हैं कि कम से कम इन लाइन्स से दस दस मील की दूरी तक पॉवर सप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ साथ माननीय सदस्यों को यह भी निवेदन कर दूं जहां से हाई टेन्शन पॉवर जहां से गुजर रहे होंगे उनको हम टेप नहीं कर सकते हैं। यहां बिल्कुल आपके समझने की जरूरत है क्योंकि दो-तीन जगह इस तरह की चर्चाएं आईं कि लाइन पास में जा रही है पर लाइट नहीं मिलती है। हाई ट्रान्समिशन लाइन ६६

(श्री हरिश्चन्द्र)

के. वी. और १२२ के. वी. में जहां ट्रॉन्सफॉर्मर्स हैं वहीं बिजली उतर सकती है। बाकी ११ के. वी. और ३३ के. वी. के लिये ऐसा प्रोविज़न है कि ओनली उनके ऊपर ही ट्रान्स-मीटर लगा कर बिजली उतार सकते हैं और वहां से गांव को फीड कर सकते हैं। तो जहां बड़ी लाइन दिखती है वहां से नहीं हो सकता। जहां तक अलवर का प्रश्न है अगर ३३ के. वी. बोर्डर लाइन पर जा रही है, जैसा मालूम हुआ है कि जा रही है तो वहां आपके गांवों में हम जरूर लाइट देंगे।

अब जो कोटा और सवाई माधोपुर की लाइनों का सवाल था और सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात बड़ी जोर से रखी, इसमें दो राय नहीं है कि हमारे यहां इस बात में ढील हुई। पर यह राजस्थान विद्युत् मण्डल ने या सरकार ने की हो, यह नही मानता। दोनों ने इसकी कोशिश की है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट को एक बार नहीं, दस बार रिमाइन्डर दिये हैं और जोर दिया है कि हमारा जो सामान स्टील का आने वाला है वह जल्दी से जल्दी आ जावे और यह जान कर आपको खुशी होनी चाहिये कि वह मैटीरियल सारा का सारा अब आ गया है और कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सवाई माधोपुर से जयपुर की लाइन कल कम्पलीट हो गई है और कोटा से सवाई माधोपुर टॉवर वायर चल रहा है। १०५ टॉवर्स खड़े हैं और इस साल के आखिर तक, यानी अक्टूबर तक हम इस बात का प्रयास करेंगे कि जयपुर में आपके यहां हाइड्ल पॉवर चम्बल का पहुँचा दें।

इसके साथ साथ जब मैंने लास्ट टाइम सदन के सामने बजट पेश किया था तो ट्रान्सफॉर्मर्स नहीं आये थे। इसकी आज हालत यह है कि सारे ट्रान्सफॉर्मर्स रतनगढ़ ,बीकानेर, कोटा, लाखेरी, सवाई माधोपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के आ गये हैं और तीन या चार ऑन दी वे हैं और मैं समझता हूँ, महीने, दो महीने में वे भी पहुँच जावेंगे। तो ऑल दी ट्रान्सफॉर्मर्स हमारे पास इस अवधि में पहुँच जावेंगे।

अब डिफिकल्टी इस वक्त जो है वह यह है कि स्टील जो ट्रान्सफॉर्मर्स के लिये चाहिये अपने ओल्ड सब-स्टेशनों के लिये, इसमें डिले हो रही है। इसके लिये हम कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान इलेक्ट्रिक बोर्ड, सरकार और जो इसमें हमारे कलीग्ज़ हैं वे सभी इसकी कोशिश कर रहे हैं। स्टील आने तक हमारे जो सब स्टेशन्स हैं उनके इक्विपमेन्ट को लगा कर पॉवर युटिलाइज़ करने में दिक्कत है।

अब मैं समझता हूँ कि हमारा जो बजट है सन् १९६१–६२ का, इसमें एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि ३० लाख प्रताप सागर के लिये कम है, ज्यादा बढ़ाना चाहिये। मैं समझता हूँ, हमें बढ़ने में एतराज नहीं है। पर एक साल में लेजिटिमेट एक्सपेन्स, जो वे मानते हैं, वह ३० लाख से ज्यादा नहीं हो सकता और इसमें इन्जीनियरों की राय से हमने इसे रखा है। वैसे तो पचास–साठ लाख भी रख सकते हैं, पर इन्जीनियर्स कहते हैं इतना साल भर में खर्च नहीं होगा, इस वास्ते इसको तीस लाख रखा है।

अब जो मेन ट्रान्समिशन लाइन्स ६१–६२ में हम लोग लाना चाहते हैं वह है कोटा-

Page No 106

(श्री हरिश्चन्द्र)

सवाई माधोपुर पर १३२ के. वी. डबल सर्किट लाइन, सवाई माधोपुर–जयपुर १३२ डबल सर्किट लाइन, नोमच–उदयपुर १३२ सिंगल सर्किट लॉ लाइन, जयपुर-अजमेर वाया फुलेरा १३२ के. वी. सिंगल सर्किट लाइन ।

अब यह जो जयपुर फुलेरा और अजमेर की लाइन है यह ओरीजिनली कोटा–अजमेर लाइन थी । पर इसकी लैंथ उधर से बढ़ जाती थी इसलिये हमने सोचा कि अगर इसे जयपुर से कनेक्ट करते हैं तो कोस्ट भी रिड्यूस हो जाती है और अजमेर को भी फीड कर सकते हैं ।

किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनको डर है, समय पर वहां बिजली पहुँचेगी या नहीं और अगर नहीं पहुँचो तो मिल कैसे चलेगा । तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि जब तक मिल तैयार होगा तब तक हम भी आपके पास पहुँच जावेंगे । इसमें शुबहा करने की गुंजाइश नहीं है ।

साथ ही फुलेरा को भी....

श्री पी. के. चौधरी: दिसम्बर, ६१ तक तो मिल जावेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोशिश यह की जा रही है कि पहुँचा दें ।

एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके लिये मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा वह यह है कि कई माननीय सदस्यों ने इस बात को यहां रखा है कि लोकल डिस्ट्रिब्यूशन लाइन या रूरल इलिक्ट्रिफिकेशन के लिये पैसा बहुत कम है । यहां तक कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक इंगलिश इडियम भी कह डाला कि: "Taste of the pudding lies in its eating" तो यह बिल्कुल ठीक है । लेकिन हमारी डिफिकल्टी यह है कि the same idiom is "cut your coat according to your cloth," तो झगड़ा यहां आकर पड़ता है । पडिंग तो सब खाना चाहते हैं, पर इसका size or taste will be dependent on the financial limitations that we have.

तो इस वास्ते मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जितना पैसा ट्रान्समिशन लाइन पर हमें चाहिये, वह नहीं है । इसके लिये हम उपाय भी सोच रहे हैं । ऐसा नहीं कि हम नहीं सोच रहे हैं । सरकार ने और विद्युत बोर्ड दोनों ने यह विचार किया है कि लोन फ्लोट कर सकते हैं क्योंकि आइन्दा जिस तरह का एक्सपेन्शन आप चाहते हैं उसके लिये और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता । तो अगर लोन फ्लोट किया जाय तो कितना रुपया आ सकता है ? इसके लिये लिखा-पढ़ी चल रही है और प्रोपर वक्त आने पर माननीय सदस्यों के सामने ज्यादा डिटेल रख सकूंगा । तो मैं समझता हूँ कि यही एक ऐसा ऑल्टर्नेटिव है जिसके द्वारा इस मसले को हल किया जा सकता है ।

श्री पी० के० चौधरी : रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में बांदीकुई–राजगढ़ लाइन भी है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्योंकि हमारे चेयरमैन महोदय ऊपर पधारे हुए हैं ।

श्री सभापति : Yes please !

श्री हरिश्चन्द्र : सभापति महोदय, मैं इसके ऊपर कुछ न कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा।

रेट्स के सवाल पर कुछ माननीय सदस्यों ने बातें रेज़ की हैं। तो रेट्स के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि भाखरा एरिया में जहां तक इन्डस्ट्रियल रेट्स का सवाल है उनको हमने लोअर किया है, लेकिन उन एरियाज़ में जहां कि इस समय बीकानेर पॉवर हाउस बिजली सप्लाई कर रहा है उन रेट्स को हमने टच नहीं किया है; वह इसलिए कि जो टोटल पॉवर भाखरा से आ रही है वह ४,६०० किलोवाट आ रही है और वहां पर डिमाण्ड और ज्यादा है। इसलिए जो बीकानेर का पॉवर हाउस है उसको भी चलाना पड़ता है और वह कम से कम १,२०० किलोवाट और सप्लाई करता है। तो इस प्रकार से दोनों पॉवर चालू हैं। बीकानेर का जो सेट है वह इस समय मोस्ट अनइकॉनोमिक सेट है इसलिए हमने सोचा है कि जिस समय हमारे पास ज्यादा पॉवर आयेगी उस समय हम नॉर्मल रेट्स पर ले आयेंगे। मैं समझता हूँ कि साल के आखिर तक कुछ न कुछ तब्दीली दीखेगी। जहां तक चम्बल का प्रश्न है इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि मध्यप्रदेश ने प्रोविज़नल टेरिफ निकाला है, तो हम भी इस फिराक में हैं और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वह इस बात को एग्ज़ामिन कर रहे हैं और राजस्थान भी जल्दी से जल्दी एक प्रोविज़नल टेरिफ अनाउन्स करेगा।

एक सवाल सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है और वह माननीय सदस्य, जो फुलेरा से आने वाले हैं, उन्होंने उठाया और शायद बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने भी उठाया कि एक इन्टीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट्स होने चाहिए। तो उसके लिए भी एक कमेटी हमने सेट–अप की है और उस कमेटी में चेयरमैन राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सेक्रेटरी इरिगेशन एण्ड पॉवर, एडीशनल फाइनेन्स सेक्रेटरी, अकाउन्ट्स मेम्बर ऑफ दी बोर्ड, चीफ इन्जीनियर, मिस्टर के० वी० राव, डाइरेक्टर सी० पी० डब्ल्यू० सी० और मिस्टर एम० आर० राघवेन्द्रम; इस तरह के मेम्बर्स की एक कमेटी फॉर्म की है और इनके अलावा एक–दो मेम्बर्स और हैं। यह कमेटी इस बात को एग्ज़ामिन करेगी कि राजस्थान में क्या हम युनिफॉर्म पैटर्न ऑफ रेट्स कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि आप इस बात को देखेंगे कि हमारे यहां पर तीन किस्म के ऑपरेशन्स हैं। पहला हाइडल ऑपरेशन है, दूसरा स्टीम टर्बाइन ऑपरेशन है और तीसरा ऑपरेशन डीज़ल से है और तीनों में खर्चा अलग अलग तरीके से चलता है। तो इस बात को एग्ज़ामिन किया जा रहा है कि हम क्या ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि यूनिफार्म रेट्स थ्रूआउट राजस्थान कर सकें। इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता कि रेट्स का क्या स्ट्रक्चर होगा। लेकिन यह जरूर है कि केस अण्डर एग्ज़ामिनेशन है और सरकार के पास आते ही उसके ऊपर विचार करेंगे।

सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक आपत्ति प्रस्तुत की थी कि जो भाखरा से हमें पॉवर मिल रही है वह पॉवर हमको दिल्ली और दूसरी स्टेट्स को नहीं देनी

Page No 108

(श्री हरिश्चन्द्र)

चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा उनकी राय से इत्तफाक नहीं करता हूँ क्योंकि हमको एक सीमित दायरे से किसी बात को नहीं देखना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि हमें हमारा बड़ा दायरा करके इसे हिन्दुस्तान के दायरे पर देखना चाहिए कि इससे हमारे दूसरे क्षेत्रों को फायदा होता है या नहीं। अब रहा सवाल इस बात का कि क्या हमारा राजस्थान नुकसान उठा रहा है ? तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वह कॉमन पूल से जायेगा और जो उसके पार्टनर्स हैं उनको प्रोफिट मिलेगा। उसमें माननीय सदस्य को किसी तरह का एतराज नहीं करना चाहिए। जो प्रोफिट होगा that will be divided between the partners of the project, i. e. Punjab and Rajasthan.

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय सदस्य एंग्ज़ाइटी से दुबले हो गये हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : कॉमन पूल से जायेगा तो राजस्थान के शेयर को इफेक्ट करेगा।

श्री हरिश्चन्द्र : आपको प्रोफिट मिलेगा जो आपकी इन्कम होगी....

श्री भैरोंसिंह : इन्कम से मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब पॉवर से है। कामन पूल से जो पॉवर दिल्ली को दी जायेगी और आप कह रहे हैं सब का शेयर होगा तो प्रोफिट में शेयर हो सकता है लेकिन जो पॉवर हम देंगे उसमें भी हमारा शेयर होगा।

श्री हरिश्चन्द्र : तो पॉवर तो हमें शेयर के मुताबिक मिलेगी....

श्री भैरोंसिंह : पॉवर कम पड़ेगी राजस्थान में।

श्री हरिश्चन्द्र : १५.२२ पर्सेन्ट के हिसाब से मिलेगी और वह कॉमन पूल से जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : यही तो मैं अर्ज कर रहा था कि कॉमन पूल में हमारा शेयर है और वह हमें इफेक्ट करेगा।

श्री हरिश्चन्द्र : आपका इन्टरप्रिटेशन ठीक है, लेकिन इस भावना से हम चलने लगेंगे तो मैं समझता हूँ कि वह भावना ठीक नहीं है। मान लीजिए कि इस समय आपको काश्मीर को देनी है तो काश्मीर ऐसी जगह है कि वहां की जनता को आपको मदद करनी चाहिए। अगर वहां की जनता मांगती है और न उनके पास ऐसे फण्ड्स ही अवेलेबल हैं, अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके सामने आते हैं और उनको सप्लाई करते हैं तो कोई बेजा काम नहीं करते। जो सतलज और व्यास की इतनी बड़ी चीज बन रही है और उसमें लाखों एकड़ जमीन डूब में आयेगी और अगर वहां के लोग आपसे कुछ मांगते हैं तो मैं समझता हूँ राजस्थान का फर्ज हो जाता है कि उस प्रदेश को वह बिजली दे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जो दी जायेगी तो उसकी हमारे पास कमी होगी, उसकी पूर्ति किस तरह से की जायेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : उसकी पूर्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्थ फाइव इयर प्लान में

(श्री हरिश्चन्द्र)

जब व्यास का लिंक लग जायेगा तो आपके पास और पॉवर आ जायेगी। जो सी० पी० डब्ल्यू० सी० ने आपको एस्टीमेट दिया है उसके हिसाब से आपके पास पॉवर बेलेन्स करने को है।

श्री सभापति : I hope, I have the leave of the House to prolong the proceedings for half-an-hour.

एक माननीय सदस्य : No, 15 minutes.

श्री सभापति : He may take 15 to 20 minutes.

श्री भैरोंसिंह : The question of Bandikui is still pending.

श्री सभापति : I hope, I have permission of the House to continue for half an hour. Yes...

श्री श्रीभानसिंह : The Chairman says, "I have the leave of the House to..." The Chair should not do this. Firstly, the permission of the House should be asked.

श्री सभापति : I say that in view of the fact that the Hon'ble Minister had to conclude his reply and he required three quarters of an hour, it was only in anticipation of the leave of the Hon'ble members that I permitted the members to continue speeches upto 4.30.

[श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) के खड़े होने पर]

According to the Rules of Procedure, the Hon'ble member is not expected to rise in his seat. while I am speaking as a senior member of the House,he is supposed to...

श्री श्रीभानसिंह : I know the rules very well what the Chair is supposed to do. When the Chair speaks, it should be on its legsand I will resume my seat.

श्री सभापति:Knowledge is one thing & observance is another one. I hope, the Hon'ble member will also care to observe the rules. The matter ends there. The proceedings of the House have been prolonged to 5.30. But he (Minister) has to complete before 5.30. You may kindly resume.

श्री हरिश्चन्द्र : धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बातें कही थीं। एक तो यह थी कि हमारे यहां जो एरियर्स हैं उनकी तरफ कम ध्यान दिया जाता है। वैसे एरियर्स की वसूली करने की हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एरियर्स बाकी हैं वे हमारे पास इस प्रकार के हैं : जैसे म्युनिसिपैलिटी के २१ लाख ४९ हजार रुपये अभी बाकी हैं और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से २६.६२ लाख रुपये बाकी हैं, और सेन्ट्रल गवर्नमेंट से १६.६६ लाख रुपये बाकी हैं, और प्राइवेट पार्टीज़ से २७.८६ लाख और रूलर्स से १५.४९ लाख बाकी हैं। इस तरह से टोटल १०३.१२ लाख का अमाउन्ट आउट स्टेंडिंग है और अगर यह आउट स्टेंडिंग अमाउन्ट किसी न किसी रूप से आता है, क्योंकि

(श्री हरिश्चन्द्र)

हम प्रयास कर रहे हैं और आ जाय तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो डेफिसिट है वह किसी हद तक मेक-अप हो सकता है, और इसकी हम कोशिश कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटीज़, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंटस। और रूलर्स का जो सवाल है अन्डर दी कवेनेन्ट उनको गारण्टी की हुई है ! यह सिर्फ बुक एडजस्टमेंट होगा बिटवीन दी स्टेट गवर्नमेंट एण्ड दी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड।

सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कॉपर स्मेल्टर के लिए कुछ कहा। मैं समझता हूँ कि उनके कहने की जरूरत नहीं है। थर्ड फाइव इयर प्लान में जो टार्गेट्स हमने सी. डब्लू. पी. सी. को भेजे थे उसमें कॉपर स्मेल्टर इन्क्लूडेड था और जो लोड सर्वे हुआ उसमें इस बात को इन्क्लूड करके ध्यान में रख लिया। लोड सर्वे बन गया है और जो थरमल स्टेशन बने हुए हैं उनका उपयोग करेंगे। रहा ऑटोमेटिक स्टेशन का सवाल, जैसा कि माननीय उप-मन्त्रीजी ने कहा कि यह मामला विचाराधीन है, अभी मैं कुछ आपके सामने नहीं कह सकता।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई कि एम्पलाइज़ का जहां तक सवाल है, उन एम्पलाइज़ का जो हक उस सोशलिस्टिक पैटर्न के अन्दर फिट करने का, तो इसके लिए जो उन्होंने कहा उसका मैं स्वागत करता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इस वक्त कानून है, जो फैक्ट्री लॉ से हमारे वर्क्स गवर्न होते हैं और लॉ के तहत जो भी एमीनिटीज़ मिलनी चाहिये उनके लिए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कि वे एमिनिटीज़ उनको मिलनी चाहिये और जहां तक वेजेज़ का सवाल है, मेरे पास यह रिपोर्ट है कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो वेजेज़ हैं वे दूसरी स्टेटों के मुकाबले में कई हद तक अच्छे हैं। दूसरी कुछ ऐसी हो सकती हैं कि ज्यादा अच्छे हों, मगर राजस्थान कोई मिडल में ही आता है; बहुत नीचे भी नहीं है और ऊपर भी नहीं है। और मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि इसके फीगर्स और कलेक्ट करके और कोई मौका आये तो सदन के मामले पेश कर सकूं !

पाली के प्राइवेट पॉवर हाउस के लिए कहा। इसके लिए यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। एक प्रश्न यहां पर भी पूछा था, उसका मैंने उत्तर भी दिया है कि एक कमेटी बना दी गई है। उस कमेटी के सामने प्रश्न विचाराधीन है कि क्या करना है। उसकी रिपोर्ट आने पर कार्यवाही क्या हो सकती है, वह करेंगे।

चौमू-रींगस लाइन के लिए बहुत कुछ कहा गया है। पोल्स खड़े हुए हैं, यह मैं मानता हूँ। लेकिन अगर अभी उनके ऊपर तार लगाते हैं तो यह भी हमारे सामने एक घटना आ जाती है कि तार चले जाते हैं, और इस तरह की घटना, माननीय सदस्यों ने अखबारों में पढ़ी होगी, घट सकती है। इस वास्ते हम इसको अभी नहीं ले रहे हैं। एज़ सून एज़ जयपुर के अन्दर पॉवर, हाइडल पॉवर आ जायेगी, हम इमीजियेटली इस लाइन को कन्स्ट्रक्ट करके चौमू और रींगस को सप्लाई करेंगे। यह प्रोजेक्ट में ले

(श्री हरिश्चन्द्र)

ली गई हैं, इसमें दो राय नहीं है। तब तक खम्भे ही खड़े रहेंगे........

श्री भैरोंसिंह : वह चौमू-रींगस तक ही रहेगी या श्रीमाधोपुर तक जायेगी।

श्री हरिश्चन्द्र : यह प्रश्न विचाराधीन है, जैसा कि माननीय उप–मन्त्रीजी ने कहा विचाराधीन है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में बिजली जाने में ऐसी बात नहीं दीखती है कि न जाय।

श्री भैरोंसिंह : आपने बाकी फुलेरा के बारे में घोषणा कर दी, स्पष्ट रूप से सरदारशहर और सलूम्बर के लिए........

डॉ० बहादुरसिंह : लेकिन बांदीकुई के बारे में नहीं कहा है।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन श्रीमाधोपुर के लिए नहीं कहा तो क्या इस दृष्टि से सोचते हैं कि........

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में है।

श्री भैरोंसिंह : फुलेरा के लिए आपने डेफिनिट कह दिया कि इस लाइन से होगा। बाकी के हिस्सों के लिए आपने डेफिनिटली कह दिया लेकिन श्रीमाधोपुर का क्वेश्चन आया तो कहा गया है कि प्रश्न विचाराधीन है। तो क्या यही समझा जाय कि विरोधी दल के क्षेत्रों के प्रश्न विचाराधीन ही रहते हैं, बाकी के सब कवर कर लिये जाते हैं ?

श्री पी. के. चौधरी : It is a Jaipur-Ajmer line, from where both the Opposition candidates...

श्री भैरोंसिंह : It is for Phulera alone.

डॉ० बहादुरसिंह : मोरेना और धौलपुर वाली लाइन का और बता दें कि कब काम करेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं माननीय सदस्यों के समक्ष यह कहना चाहता हूँ कि न तो सरकार की ऐसी मन्शा है और न इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ऐसी मन्शा है कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन रखा जाय कि विरोधी दल के सदस्य हैं वहां पर काम नहीं हो। मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में इस तरह की विचार धारा न रहती है और न रहनी चाहिए........

डॉ० बहादुरसिंह : उनकी भावना ऐसी ही है।

श्री हरिश्चन्द्र : आपकी विचार धारा कुछ इस तरह की हो सकती है, इसलिए आप कहते हैं। हमारी तरफ से नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस बात को आप देखेंगे कि श्रीमाधोपुर में बिजली आ जाय........

श्री भैरोंसिंह : आश्वासन के लिए तो चौथी पंचवर्षीय योजना रख देते तो वह भी आश्वासन था और आश्वासन की संज्ञा में आ जाता।

श्री हरिश्चन्द्र : और आश्वासन दे सकता हूँ। फेक्ट्स और फीगर्स दे रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : बाकी सब लाइन्स कन्स्ट्रक्ट कर दी और चौमू और रींगस लाइन पर खम्भे लगे हुए हैं और कोई डिसीज़न नहीं लिया गया है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कह दिया कि लाइन पहुँच जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : कब तक पहुँच जायेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : ६५ तक। इन ५ ईयर्स के अन्दर।

धौलपुर और मुरेना के लिए माननीय सदस्य ने कहा उसके लिए मैं निवेदन करता हूँ कि सवाई माधोपुर से जो ग्वालियर लाइन जायेगी वहीं मुरेना को फीड करेगी, और मुरेना से, हम चाहते हैं कि धौलपुर को फीड किया जाय। कन्स्ट्रक्शन सवाई माधोपुर से ग्वालियर वाली लाइन का जब भी हम शुरू करेंगे तो साइमलटेनियसली मुरेना से धौलपुर की जो लाइन है वह भी शुरू करेंगे। ग्वालियर जब इनर्जाइज़ हो सवाई माधोपुर जब इनर्जाइज़ हो तो धौलपुर भीइनरार्जाइज़ हो मुरेना के साथ-साथ।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने पाली में क्योंकि वहां पर पेकेज डील हो रहा है और सरकार और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कोई ध्यान नहीं दिया कि वहां पर प्रोडक्शन इन्क्रीज़ करने के लिए पॉवर दिया जाय। मैं समझता हूँ कि मैं पहला आदमी था जब कि पेकेज डील की बात सुनी। तो मैंने कहा कि अच्छा यह हो कि १४ करोड़ रुपये पेकेज डील में खर्च कर रहे हैं तो आप हमको पेकेज डील में से किसी न किसी रूप से एकाध करोड़ रुपया दिलवा दें तो हम सारे पाली डिस्ट्रिक्ट के अन्दर बिजली दे देंगे। मैं समझता हूँ कि उस पेकेज डील के द्वारा कुछ पैसा मिल सकता है, तो कोशिश करनी चाहिये और पैसा आयेगा तो जरूर हम सारे पाली डिस्ट्रिक्ट को इलेक्ट्रिफाई कर सकते हैं। मगर पैसा नहीं आता है तो पुराने ईडीयम को ही दोहराऊंगा। I can only cut my coat according to the cloth that I have got. उस लिहाज़ से इसमें रखा है। फालना के अन्दर पॉवर दे रहे हैं और फालना से रानी और बाली एक और जगह है वहां पर पॉवर सप्लाई करेंगे। जहां जहां पर इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स कायम की हैं उनको हम जरूर फीड करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाली को इग्नोर करने का कोई सवाल नहीं है।

एक प्रश्न माननीय सदस्य ने बांदीकुई के लिए रखा था। तो बांदीकुई के लिए यह अर्ज करना है कि ६१-६५ में हम इस टाउन को इलेक्ट्रिफाइ करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। अलवर से आने वाली माननीय सदस्या ने विलेजेज़ के लिए कहा तो २९ विलेजेज़ जो हैं, मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर तो काम चल रहा है और अगर आप चाहें तो जायं और देख सकती हैं और जहां तक दूसरों का सवाल है एक विलेज है वहां उसको भी २९ विलेजेज़ के साथ में इलेक्ट्रिफाइ करवा देंगे।

(श्री हरिश्चन्द्र)

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भरतपुर के लिये कहा। भरतपुर में जैसा कि आपको मालूम है अभी एक स्टीम टर्बाइन वहां लगाया है, एनर्जी प्रोड्यूस कर दिया। इसको लेकर डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल है, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं ! क्या करें, कैसे फंड्स अवेलेबल हों या न हों लेकिन यह तय कर लिया है, यहां तक कि जो विलेजेज हम इलेक्ट्रिफाई करना चाहते हैं ६१, ६२ या ६३ में वे हैं बयाना, कनार और वेयर। इन तीनों को इलेक्ट्रिफाई करना चाहते हैं, और जब तक भरतपुर इलाके में से लाइन नहीं निकलेगी तब तक पॉवर का डिस्ट्रिब्यूशन साइड बड़ा लो रहेगा, यह मानते हुए स्कीम बनाई है क्योंकि स्टीम टर्बाइन चल रहा है, जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिब्युशन हो सकता है इसलिये कायम किया, लेकिन फंड्स अवेलेबल होंगे और लाइन में सक्सेसफुल होंगे तो और भी लाइन ला सकते हैं, गांवों को सप्लाई कर सकते हैं। इमीजियेटली तो भरतपुर, बयाना वाया वेयर और नंदलाई लाइन लेने का सवाल है।....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : डीग से नगर, कामा पहाड़ी के बारे में ?

श्री हरिश्चन्द्र : कामा में भी सप्लाई की जायेगी।

गंगापुर, लालसोट, सवाई माधोपुर के लिये वहां के माननीय सदस्य ने कहा। मैं समझता हूँ, इस बारे में हमने पहले भी कहा कि आपको डर नहीं होना चाहिये, लालसोट में जरूर बिजली आयेगी। कब आयेगी, इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि इसी फाइनेंशियल इयर में लालसोट तक पहुंच जानी चाहिये। आप कह रहे हैं कि काम कम चल रहा है तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा कि क्यों नहीं तेजी से चल रहा है और आपको बता भी दूंगा कि क्यों नहीं चल रहा है....

श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : पहली पंचवर्षीय योजना तक पहुंच गये इसलिये विश्वास कम हो रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र : अब मैं कह रहा हूँ जरूर पहुंच जायेगी।

अंत में, मैं माननीय सदस्यों को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगा। जो जो सुझाव रखे हैं, मैं आशा करता हूँ विद्युत् बोर्ड द्वारा राजस्थान की प्रगति दिन पर दिन देखेंगे।

श्री सभापति : The House stands adjourned till Monday, the 3rd April, 1961 upto 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५. १२ बजे, सोमवार, दिनांक ३ अप्रेल, १९६१ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(शनिवार, १ अप्रेल, १९६१)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ६०६०

रतनगढ़ नगरपालिका के निर्वाचित अस्थायी अध्यक्ष पं० खेमचन्द्र शर्मा को पुनः कार्य भार सम्भलवाना।

थानेदार चरणसिंह व डिप्टी एस. पी., चुरू के विरूद्ध की गई शिकायतों पर कार्यवाही।

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में सिरोही जिले में विद्युत व्यवस्था।

पी. एस. सी. की अनुमति बिना नियुक्त सार्वजनिक सम्पर्क अधिकारी।

नगरपालिकाओं में बकाया ऋण रकम की सहायता रूप में परिणति की अपेक्षा।

चिकित्सालयों में रोगियों के मनोरंजन की व्यवस्था।

तहसील दौसा में हुई चोरियां।

अरबन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड, जयपुर द्वारा आवंटित भूमि।

स्कम्भ

राजस्थान विश्व विद्यालय में आयुर्वेद फैक्लटी की स्थापना।

राजस्थान अपीलैट ऑथोरिटी के विचाराधीन मामले।

जयपुर शहर की आवास समस्या के हल हेतु योजनायें।

रूपनगढ़ तहसील के ग्रामों में पानी का अभाव।

राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र की जमीन के आवंटन हेतु नियम।

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत राज्य में खोली जाने वाली रेल्वे लाइनें।

बांसवाड़ा जिले के जंगल एरिया के सैटलमेन्ट का कार्य।

सरदार समन्द बांध से असिंचित भूमि का नहरी लगान।

• बामनवास कस्बे को बिजली।

टौंक से सवाई माधोपुर जाने वाली बस का उनियारा होकर नहीं जाना।

बांगड़ अस्पताल, पाली।

लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के बाजार की सड़क का निर्माण कार्य।

आर-बी लोपर नहर पर पुल निर्माण।

टौंक से इन्द्रगढ़ जाने वाली बस का उनियारा होकर जाना।

दौसा-लालसोट सड़क पर पड़ने वाले नाले।

भीलवाड़ा में गांधीसागर स्थित शिव मन्दिर की मूर्तियों का भंजन।

टौंक-लाखेरी से तथा लाखेरी-वाही–इन्द्रगढ़-खातोली-उनियारा-टौंक सड़क का निर्माण।

राजस्थान राज्य विद्युत-मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) १९६१-६२ पर वाद-विवाद ६१२२

श्री हरिश्चन्द्र, विद्युत् मंत्री ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :

"मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान राज्य विद्युत्-मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक), १९६१-६२ को जो दिनांक २९ मार्च, १९६१ को सदन की मेज पर रखा गया था विचारार्थ लिया जाय।"

इस पर की गई बहस में निम्न-लिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

१. श्री सोहनलाल भटनागर
२. श्री रघुवीरसिंह
३. रावराजा श्री सरदारसिंह
४. श्री पुरुषोत्तमलाल
५. श्री मदनसिंह दांता
६. डॉ० बहादुरसिंह
७. श्री दलपतसिंह
८. श्री हरिप्रसाद यादव
९. रावल श्री नरेन्द्रसिंह
१०. श्री मूलचन्द डागा
११. श्री जगदीशप्रसाद माथुर
१२. श्री पी. के. चौधरी
१३. श्री शंकरलाल
१४. श्री मुरलीधर व्यास

Page No 116

स्कम्भ

१५. श्रीमती गंगादेवी डाटा

१६. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

१७. श्री चन्दनमल वैद

१८. श्री प्रभुलाल पुरोहित

१९. श्री सम्पतराज जैन

२०. श्री रामचन्द्र

२१. डॉ० चन्द्रकला

२२. श्री लादूराम

स्कम्भ

सरकार की ओर से श्री हरिश्चन्द्र, विद्युत मंत्री ने बहस का उत्तर दिया।

सोमवार, ३ अप्रेल, १९६१
की कार्य-सूची

१. राजस्थान कृषि आय-कर (संशोधन), विधेयक १९६१ (पुरःस्थापन)

२. राजस्थान वित्त विधेयक, १९६१ (विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६८ का उत्तर देखिये)

चिकित्सालयों की सूची जिनमें रोगियों के मनोरंजन के लिये व्यवस्था है

१. विक्टोरिया अस्पताल, भरतपुर	एक रेडियो की व्यवस्था है। मैग्ज़ीन्स व अन्य पेपरों से चित्रों को लेकर रोगियों के पास मनोरंजन के लिये भेज दिया जाता है और शिक्षित रोगियों को हिन्दी व अंग्रेजी के पुराने मैग्ज़ीन्स की भी व्यवस्था है।
२. महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा	रोगियों के मनोरंजन के लिये २ रेडियो उपलब्ध है जो कि प्रातः एवं सायंकाल बजाये जाते हैं।
३. बूंदी अस्पताल	रोगियों के मनोरंजन के लिये २ रेडियो उपलब्ध है जो कि प्रातः व सायंकाल बीमारों के मनोरंजन हेतु बजाये जाते हैं।
४. जनाना अस्पताल, अलवर	यहां पर बच्चों के वार्ड में मनबहलाव रोगी बच्चों के लिये खिलौने एवं गुब्बारे उपलब्ध हैं। पब्लिक रिलेशन्स विभाग की ओर से समय समय पर रोगियों को सिनेमा दिखलाया जाता है। रोगियों के मनबहलाव के लिये कठपुतली का खेल भी दिखाया जाता है।
५. बांगड़ अस्पताल, पाली	यहां पर रोगियों के मनोरंजन के लिये १ रेडियो उपलब्ध है।
६. अलेग्जेन्ड्रा अस्पताल, अलवर	यहां एक रेडियो एवं एक लाउड स्पीकर उपलब्ध है जो रोगियों के प्रत्येक वार्ड में लगाया हुआ है।
७. जनरल अस्पताल, उदयपुर	रोगियों के मनोरंजन के लिये अन्तरंग विभागों में रेडियो एवं पुस्तकों की व्यवस्था है। बच्चों के अन्तरंग विभागों में खिलौनों आदि का प्रबन्ध है।
८. जनाना अस्पताल, उदयपुर	रोगियों के मनोरंजन के लिये अन्तरंग विभागों में रेडियो की सुविधा है।
९. यक्ष्म आरोग्य सदन, बाडी	रोगियों के मनोरंजन के लिये अन्तरंग विभाग में मनोरंजक पुस्तकें, रेडियो, ताश, केरम एवं खेलकूद के साधनों की व्यवस्था है।

१०. एम. जी अस्पताल, जोधपुर	इस चिकित्सालय के निम्नलिखित वार्डों में रेडियो सेट हैं। १. मेन मेडिकल वार्ड २. टी. बी. वार्ड ३. आई वार्ड ४. चर्म रोग वार्ड ५. आरथोपेडिक वार्ड। एम. जी अस्पताल व उम्मेद अस्पताल जोधपुर के वीमैनसर्जीकल वार्ड एवं बच्चों के वार्ड में क्रमानुसार रोगियों के मन बहलाने के लिये खिलौनों की व्यवस्था है।
११. मर्दाना अस्पताल, बीकानेर	मर्दाना एवं जनाना अस्पताल के बीच में एक शिशु वाटिका (बच्चों का पार्क) है जिसका निर्माण जनता द्वारा दिये गये दान तथा स्टाफ के श्रमदान से हुआ है।
१२. जनाना अस्पताल, बीकानेर	इस अस्पताल के शिशु वार्ड में एक रेडियो उपलब्ध है तथा काफी संख्या में गुड़ियों का संग्रह है जो रोगी बच्चों के खेलने में काम आती है।
१३. टी. बी अस्पताल, बीकानेर	रोगियों के मनोरंजन के लिये रेडियो एवं पुस्तकालय है। अस्पताल में एक प्रोजेक्टर भी है जिससे मरीजों को फिल्म दिखाई जाती है।
१४. मानसिक चिकित्सालय, जयपुर	इस चिकित्सालय में एक ऑक्युपेशनल थिरेपी एवं मनोरंजन विभाग कार्य कर रहा है। इसके अन्तर्गत रोगियों के मनोरंजन के लिये निम्नलिखित व्यवस्था है :— १. खेल के सामान: टेनिस, क्रिकेट, वोलीबॉल, बेडमिन्टन आदि। २. संगीत का सामान: हारमोनियम, तबला, ढोलक, सितार, वायोलीन ३. पुस्तकालय: साप्ताहिक अखबार, दैनिक राष्ट्रदूत। प्रत्येक शनिवार को सोशियल कार्यक्रम बनाया जाता है, जिसमें रोगी नृत्य करते हैं, संगीत गाते हैं और मनोवैज्ञानिक नाटक करते हैं। रोगियों के मन बहलाव के लिये ताश, चौपड़, शतरंज तथा केरम आदि की व्यवस्था है।

२५. सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	इस चिकित्सालय में रोगियों के मनोरंजन के लिये एक रेडियो सेट बच्चों के वार्ड में है। आक्युपेशनल थिरेपी में कुछ पुस्तकें मैगजीन्स, समाचार-पत्र एवं खिलौने रखे हैं। साल में एक-दो बार सिनेमा भी दिखलाया जाता है।
१६. के. जी. वी सेनेटोरियम, जयपुर	यहां पर रोगियों के मनोरंजन के लिये एक रेडियो, ताश तथा दैनिक-पत्र उपलब्ध हैं।
१७. जनाना अस्पताल, जयपुर	यहां पर रोगियों के मनोरंजन के लिये एक रेडियो है।
१८. एस. आर. जनरल अस्पताल,	यहां पर एक रेडियो उपलब्ध है, जिसमें लाउडस्पीकर लगे हुये हैं जो दिन में दो बार बजाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त टी. बी. रोगियों के लिये भी खेल कूद की व्यवस्था है। कभी २ पब्लिक रिलेशन्स ऑफिस की ओर से टी.-बी. के रोगियों को सिनेमा भी दिखलाया जाता है।
१९. लीपर असाइलम, जयपुर	दो रेडियो से स का प्रबन्ध है।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६७२ का उत्तर देखिये)

LIST GRANTED.

1. Kishangarh-Kekri.
2. Alwar-Bharatpur.
3. Lalsot-Bonli-Sawai Madhopur.
4. Dabla-Bansur.
5. Sawai Madhopur-Khandar.
6. Monda-Renwal.
7. Bissau-Lohara.
8. Bagad-Gudha.
9. Jaipur-Ajmer.
10. Beawar-Vijainagar,
11. Gangapur-Garhmoran.
12. Jaipur-Gangapur.
13. Karauli-Gangapur.
14. Pali-Sumerpur.
15. Bayana-Bhusawar.
16. Jodhpur-Pali.
17. Sikar-Salasar.
18. Jhunjhunu-Sadulpur.
19. Bhawni Mandi-Soyat.
20. Jodhpur-Bilara.
21. Hanumangarh-Sirsa.
22. Ajmer-Pisagan.
23. Beawar-Nasirabad.

24. Beawar-Bijainagar.
25. Ajmer-Barmer.
26. Ajmer-Bhinai.
27. Ajmer-Ramgarh.
28. Ajmer-Deoli.
29. Ajmer-Srinagar.
30. Mori-Dera Nand.
31. Jaipur-Delhi.
32. Nathdwara-Fetehnagar.
33. Alwar-Bharatpur.
34. Salumber-Rikhabdev.
35. Jodhpur-Bhopalgarh Asop
36. Jodhpur-Osian.
37. Jodhpur-Ramdeora.
38. Bhilwara-Ajmer.
39. Badnor-Davar.
40. Nathdwara-Desuri.
41. Alwar-Behror.
42. Alwar-Tijara.
43. Chittor-Pratapgarh.
44. Alwar-Nagar.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६७६ का उत्तर देखिये)

SARDAR SAMAND BUNDH JAWAI CANALS ERINPURA ROAD

Sl. No.	Years	Gauge	Irrigated area area irrigated H. JH. Farms in Bighas		Other Cultivators in Bighas		Total area Bed and Flow in Bighas	
			Flow	Bed	Flow	Bed	Flow	Bed
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1944-45							
2.	1945-46							
3.	1946-47	18.25			Not available			
4.	1947-48	13.46						
5.	1948-49	18.80						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	1949-50	8.83						
7.	1950-51	13.64	1302.17	-	3730.4	3285.3	5032.1	3285.3
8.	1951-52	9.90	178.10	337.10	390.2	1495.8	568.12	1832.18
9.	1952-53	25.00	6378.10	232.17	32776.9	5746.8	39154.19	5979.5
10.	1953-54	19.42	5465.10	32.86	20816.9	5904.19	26281.19	5937.5
11.	1954-55	13.20	2558.16	329.11	2403.12	3159.17	4961.8	3481.8
12.	1955-56	26.00	6601.10	204.9	36985.10	3269.13	43587.0	3474.0
13.	1956-57	18.95	5050.6	306.14	19788.15	5630.3	24839.1	5942.17
14.	1957-58	12.18	1704.6	619.19	1623.14	3579.15	3328.0	4199.14
15.	1958-59 (end-of March, 1960)	11.24	690.6	308.10	705.01	1083.10	1325.16	1392.0
16.	1959-60	11.51	1326.1	221.19	1966.3	727.18	3292.4	949.17

शुद्धि-पत्र

(१ अप्रेल, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६०६२	अन्तिम से ६	नारायणसिं हजी उस के लड़के	नारायणसिंह व उसके लड़के
६०६३	१०	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
६०६४	अन्तिम से ५	,,	,,
६०६७	१४	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
६०६८	१०	(पालों) :	(पाली) :
६०७२	अन्तिम से ३	डॉ० बहादुरसिह	डॉ० बहादुरसिंह
६०७३	१०	रेडियों	रेडियोज़
६०७८	अन्तिम पंक्ति	implementetion	implementation
६०८०	११	भैरोंसिह	भैरोंसिंह
६०८१	१२	रूटस	रूट्स
६०८६	९ व १०	पॉवर	पॉवर्स
६०८६	अन्तिम से ५	श्री लादूराम सुलाणियां	श्री लादूराम सुलाणिया
६०८७	१	,,	,,
६०८९	अन्तिम से ८	सदन्द	समन्द
६०९२	शीर्ष	(श्री रामचस्द्र चौधरी)	(श्री रामचन्द्र चौधरी)
,,	६	कसबे	कस्बे
६०९३	७	रावराजा श्री सरदारसिह	रावराजा श्री सरदारसिंह
६०९५	७	छौड़	छोड़
६०९८	१७	१६४८१	१६४८५
६१०१	४	रावराजा श्री सरदारसिह	रावराजा श्री सरदारसिंह
६१०१	अन्तिम से ३	हुक	रुक
,,	,,	मोटर्स	मोटरें
६१०३	९	मीलवाडा	भीलवाड़ा
६१०४	शीर्षक	७१०४	६१०४
,,	अन्तिम से ४	टोंक	टौंक
६१०७	शीर्षक	तारंकित	तारांकित
६११३	५	आवटित	आवंटित
६११६	८	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
,,	अन्तिम से ८	श्री सम्पराम	श्री सम्पतराम

१	२	३	४
६११६	१०	है	हैं
६१२४	अन्तिम से ६	इसको	इसकी
६१२६	शीर्ष	ी हरिश्चन्द्र)	(श्री हरिश्चन्द्र)
६१२६	५-६	फाइ–नेन्सयली	फाइ–नेन्शियली
६१३२	१७	व	वे
६१३३	शीर्षक	वित्तिव	वित्तीय
६१३८	शीर्षक	भियत	विद्युत
,,	शीर्ष	(श्रीं रघुवीरसिंह)	(श्री रघुवीरसिंह)
६१३६	शीर्षक	यित्तिय	वित्तीय
६१४०	११	सेटस	सेट्स
६१४१	अन्तिम से १२	वैल्स	वैल्स
६१४२	शीर्ष	(श्री रघुवीरमिंह)	(श्री रघुवीरसिंह)
६१४६	,,	(वराजा श्री सरदारसिंह)	(रावराजा श्री सरदारसिंह)
६१४७	२२	हे	हैं
६१५३	५	मंकट	संकट
६१५५	१५	सकटे	सकते
६१५६	१८	कॉन्स्टिटीटयून्सी	कॉन्स्टीट्यूएन्सी
६१५७	४	करगे	करेंगे
,,	शीर्षक	भित्तीय	वित्तीय
६१५६	अन्तिम से ७	उतको	उनको
६१६१	शीर्षक	विवरग	विवरण
,,	१०	लेवरलफेयर	लेबर वैल फेयर
६१६३	२३	शार्नल	थर्मल
६१६४	अन्तिम से ७	(वल्लमनगर–सु०)	(वल्लभनगर–सु०)
६१६५	अन्तिम से ५	खींच कर	खींच कर
,,	शीर्षक	विवरल	विवरण
६१७३	,,	विवरध	,,
६१८३	३	श्री शकरलाल	श्री शंकरलाल
६१८४	अन्तिम से १२	श्री श्रीमानसिह	श्री श्रीमानसिंह
६१८६	५	आव्हान	आह्वान
६१६४	१७	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
६१६६	७	श्रीमधोपुर	श्रीमाधोपुर
६१६७	११	हमें	हम

१	२	३	४
६१९९	६	इन्डिवीन्युअल	इन्डिवीज्युअल
६२००	६	ro	or
६२०१	शीर्षक	वित्तीय	वित्तीय
,,	१२	कन्सेश्शन	कँसेश्शन
,,	अन्तिम से ४	hearths	hearts
६२०२	६ और ९	टैस्न्डर्ड	स्टैन्डर्ड
६२०३	८	द्रष्टि	द्दष्टि
६२०५	शीर्षक	विततीय	वित्तीय
६२०६	,,	१९६१ सु ६२	१९६१–६२
६२०७	अन्तिम से ११	हीं	ही
६२०८	शीर्षक	कां	का
६२१२	११	श्री शकरलाल	श्री शंकरलाल
६२१४	शीर्षक	५२१४	६२१४
,,	शीर्ष	(श्री शकरलाल)	(श्री शंकरलाल)
६२१५	८	स्टेटस	स्टेट्स
६२१६	शीर्षक	वियुत	विद्युत
६२२२–२३	शीर्षक	१९६२–६२–६१ मार्च, ६१	१९६१–६२–अप्रेल,६१
६२२६	३	इतने	इतना
६२२७	१३	बनन	बनने
६२३०	६	खेडली	खेड़ली
६२४०	१	डॉ बहादुसिंह	डॉ० बहादुरसिंह
६२४३	अन्तिम से १४	प्राति	प्राप्ति
,,	अन्तिम से १०	पच	पंच
६२४५	१३	जार ही है।	जा रही है।
,,	अन्तिम से १५	ओर	और
६२४७	१३	क्रिटिसज्म	क्रिटिसिज़्म
६२४८	१५	वालां	वालों
६२५१	५	इसकी सफलता	इसकी ही सफलता
६२५५	अन्तिम से १२	ि िवेदन	निवेदन
६२५७	अन्तिम से ३	बक्त	वक्त
६२६०	अन्तिम से १३	श्री लाद्राम सुलाणिया	श्री लादूराम सुलाणिया
६२६३	शीर्षक	वित्तीय	वित्तीय
,,	अन्तिम से १२	अचीवमेंटस	अचीवमेंट्स

१	२	३	४
६२६३	अन्तिम से ५	एडल्स्टमेंट	एडजस्टमेंट
६२६४	अन्तिम पंक्ति	है भी	हैं वे भी
६२६७	शीर्षक	वित्तीय	वित्तीय
,,	१०	पोइन्टस	पोइन्ट्स
६२६६	शीर्षक	विवरल	विवरण
,,	अन्तिम से १०	बाढ़ने	बढ़ाने
,,	अन्तिम से ४	हैं इतना	हैं कि इतना
६२७१	३–४	इंग्लिश इडियम	इंग्लिश का ईडियम
६२७५	शीर्षक	विवरण	विवरण
६२७६	१४	श्री भैरोंसिह	भैरोंसिंह
६२७७	११	legsand	legs and
६२७८	६	डिपार्टमेंटस	डिपार्टमेंट्स
६२८२	४	दो	दी
६२८३	६	कोशिश	कोशिश
६२८४	३	कामा	कामां
६२८८	१	बांगड	बांगड़
६२६४	अन्तिम पंक्ति	से स	सेट्स

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
मुख पृष्ठ (विषय सूची)	[illegible]	का वित्तय	का वित्तीय
६२८०	शीर्षक	का वितिव	का वित्तीय
६२८७	२	फैक्लटी की	फैकल्टी की